चिंतन

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों की उपेक्षा क्यों

हिंदू छात्रों के विरोध और शिकायतों के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। विवाद की शुरुआत तब हुई, जब कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले बैच में 50 छात्रों में 42 मुस्लिम समुदाय से थे, जबकि हिंदू छात्रों की संख्या सिर्फ 7 और 1 सिख छात्र शामिल थे। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया और आरोप लगाया कि कॉलेज में हिंदू छात्रों की उपेक्षा क्यों की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना था कि चूंकि यह कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से संचालित होता है, इसलिए श्राइन बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कॉलेज श्राइन बोर्ड की जमीन पर ही बना है और ज्यादातर फंडिंग हिंदू भक्तों के चढ़ावे से आती है। हिंदू तीर्थयात्रियों की आस्था से जुड़े पैसे का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सीटें ज्यादातर एक खास समुदाय को मिल गईं। ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और भेदभाव जैसा लगता है। सवाल उठता है कि हिंदू धर्म के संगठनों के पैसे का इस तरह उपयोग कितना जायज है। बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम आबादी 68.3%, हिंदू 28.44%, सिख 1.87%, बौद्ध 0.90% और ईसाई 0.28% है। इस तरह देखा जाए तो हिंदू यहां अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी 50 में सिर्फ 7 सीटें हिंदू छात्रों को मिलना कहां का न्याय है। हालांकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मान्यता रद्द करने के पीछे कई कारण गिनाए हैं। इनमें बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की कमी, मरीजों की कम संख्या और न्यूनतम मानकों के गंभीर उल्लंघन शामिल हैं। अब मौजूदा एमबीबीएस छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जिसमें 60 सामाजिक और दक्षिणपंथी संगठन शामिल हैं, ने पहले दाखिला सूची रद्द करने की मांग की थी। जब यह संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने कॉलेज बंद करने पर जोर दिया। समिति का तर्क था कि माता वैष्णो देवी श्राइन के चढ़ावे से मिलने वाले लाभ मुख्य रूप से हिंदुओं को ही मिलने चाहिए। मेडिकल कॉलेज ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से 5 दिसंबर और 19 दिसंबर, 2024 को एक पब्लिक नोटिस के तहत नया एमबीबीएस प्रोग्राम शुरू करने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद संस्थान को 2025-26 एकेडमिक सत्र के लिए 50 एमबीबीएस छात्रों को एडमिशन देने की मंजूरी मिली थी और इसी के बाद मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर विवाद शुरू हो गया था। भाजपा ने भी इसका समर्थन किया था और उपराज्यपाल से एडमिशन रिव्यू की मांग की थी। हिन्दू संगठन ने कहा था कि कॉलेज को हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस मिले या नई मेरिट से दाखिले हों। हालांकि कॉलेज के अधिकारियों और राज्य के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दाखिला पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है। धर्म से इसका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन विरोध करने वाले इसे आस्था और फंडिंग के दुरुपयोग का मामला मानते रहे। यही वजह थी कि महीनों तक ये विवाद गरमाया रहा और अब इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई। अब कॉलेज के छात्रों को जम्मू-कश्मीर के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। समायोजन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा।

ट्रंप की बेलगामी और यूएन की लाचारी

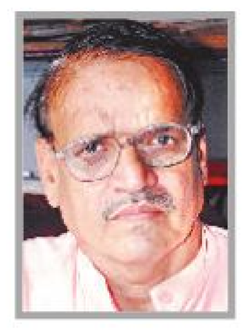

विश्लेषण
प्रमोद भार्गव

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस का अमेरिका द्वारा किए अपहरण और गिरफ्तारी का घटनाक्रम आजकल चर्चा में है। वेनेजुएला के पक्ष में आवाज उठाने वाले दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आपात बैठक भी हुई, जिसमें अमेरिका ने अपना पक्ष रखा और अपने तानाशाही रवैये को जायज ठहराया। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस सैन्य कार्यवाही को सीधे-सीधे दादागिरी बताया। रूस ने भी आपाति जताई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताने के अलावा अमेरिका के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य में लाचार नजर आए।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस का अमेरिका द्वारा किए अपहरण और गिरफ्तारी ने महाकवि तुलसीदास की इस कहावत 'समरथ को नहीं दोष गुसाईं' को चरितार्थ कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जिन कुतर्कों को तर्क बताकर अपने हठ को सच बताते रहें, वास्तविकता यही है कि इस कार्यवाही को किसी भी कानून के परिप्रेक्ष्य में तर्कसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है? वेनेजुएला के पक्ष में आवाज उठाने वाले दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आपात बैठक भी हुई, जिसमें अमेरिका ने अपना पक्ष रखा और अपने तानाशाही रवैये को जायज ठहराया। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस सैन्य कार्यवाही को सीधे-सीधे दादागिरी बताया।

रूस ने भी आपात्ति जताई है, लेकिन बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताने के अलावा अमेरिका के विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य में लाचार नजर आए। गुटेरस ने कहा कि यह इस कार्यवाही में अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों का पालन नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किंतु इसकी अनदेखी की गई। वेनेजुएला के प्रतिनिधि ने अमेरिका द्वारा किए इस हमले को अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों और तेल को प्राप्त करना बताया। ऐसी ही रूस, चीन, मैक्सिको, क्यूबा और कई देशों ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की, किंतु अमेरिका के मित्र देश उसके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। दुनिया के तेल भंडार का 18.17 प्रतिशत तेल अर्थात 303 अरब बैरल तेल और दुर्लभ खनिज के भंडार वेनेजुएला की धरती में समाए हुए हैं, किंतु उसके पास कच्चे तेल को शोधन करने के तकनीकि संसाधन नहीं हैं। इसलिए इस तेल को ईंधन में नहीं बदल पा रहा है। इस तेल को शोधन के लिए जब मादुरो ने चीन से तेल और रूस से हथियार खरीदने की नीति को अंजाम दिया तो ट्रंप की नाराजगी बढ़ गई और मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया का अपहरण कर लिया।

इस अपहरण की घटनाक्रम को लेकर मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा ने कहा है कि इतिहास बताएगा कि हमारे भीतर के लोगों ने किस तरह से गद्दारी करते यह राष्ट्रघात किया? मीडिया द्वारा ऐसी जानकारियां सामने लाई गई हैं कि वेनेजुएला सरकार में काम कर रहे लोगों ने ही उपहारों के लालच में आकर अमेरिकी सेना को राष्ट्रपति मादुरो के आवास तक पहुंचाने में मदद की है। हालांकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी करने का हवाला देकर इस सैन्य कार्यवाही को जायज ठहराया है। मादुरो को अमेरिकी कानून केर-फ्रिस्बी के तहत पकड़ा गया है। यह कानून अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद-2 के तहत राष्ट्रपति को गैर-कानूनी तरीकों से ऐसे लोगों और भगोड़ों को पकड़ने की अनुमति देता है, जो अमेरिका को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हों। इसमें प्रावधान है कि गिरफ्तारी का तरीका कितना भी गैर-कानूनी हो, एक बार अमेरिका में लाने के बाद अमेरिकी अदालत में मामला चलाया जा सकता है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। मादुरो पर मादक पदार्थ तस्करी के आपराधिक मामले अमेरिका में

दर्ज हैं। इनमें कम से कम 20 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। अमेरिका ऐसा दुस्साहस 1990 में पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार करके दिखा चुका है। इन्हें अमेरिकी अदालत ने 40 साल की सजा सुनाई थी, किंतु 2011 में रिहा कर दिया गया था। यदि मादुरो को सजा सुनाई जाती है तो ट्रंप के राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद कोई दूसरा राष्ट्रपति मादुरो को क्षमादान दे सकता है। खुद ट्रंप होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति हर्नाडेज को 2025 में माफी दे चुके हैं। अमेरिका कभी मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी का बहाना ढूंढकर अपने शत्रु राष्ट्रों के मुखियाओं को सबक सिखाता रहा है। 2003 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकार ने इराक पर जैविक और रासायनिक हथियार होने का दावा कर ईराक को नेस्तनाबूद कर दिया था। वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी अपदस्थ कर दिया था। इन हस्तक्षेपों के चलते आज भी इन देशों में गृहयुद्ध एवं अस्थिरता के हालात बने हुए हैं। यही हश्र अब वेनेजुएला का होना निश्चित है। अमेरिका के सरकारी शोध संस्थान कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार 1798 से लेकर अब तक अमेरिका 469 सैन्य हस्तक्षेप दुनिया में इसलिए कर चुका है, जिससे उसे महाशक्ति माना जाता रहे। दुनिया में लगातार ऐसे हालातों की निर्मिति सामने आने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की कार्य-संस्कृति लाचार बनी हुई है। उस पर निरंतर प्रश्न-चिन्ह उठ रहे हैं। अतएव यदि यह वैश्विक संस्था अपने भीतर समयानुकूल सुधार नहीं लाती है तो कालांतर में महत्वहीन होती चली जाएगी और फिर इसके सदस्य देशों को इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। भारत जैसे देश को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता से बाहर रखते हुए इस संस्था ने जता दिया है कि वहां चंद अलोकतांत्रिक या तानाशाह की भूमिका में आ चुके देशों की ही तूती बोलती है।

इसकी निष्पक्षता भी संदिग्ध है, इसीलिए वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र ताकतवर देशों की मनमानी रोकने, शांति स्थापित करने और आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था। इसका अहम मकसद भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका और आतंकवाद से सुरक्षित रखना था। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर समेत तीन बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक और अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस के जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीषिका के शिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं। रूस और यूक्रेन तथा इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच युद्ध एक नहीं टूटने वाली कड़ी बन गया है। अनेक इस्लामिक देश गृह-कलह से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ और शांति सेना जैसे संगठन काम करते हैं। चंद देशों की ताकत के आगे ये संगठन नतमस्तक होते दिखाई देते हैं, इसीलिए शांति सेना की विश्व में बढ़ते सैनिक संघर्षों के बीच कोई निर्णायक भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संगठन जी-20, जी-8, आसियान और ओपेक जैसे संगठन विभाजित दुनिया के क्रम में लाचारी का अनुभव कर रहे हैं। अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों द्वारा इन्हें दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती कर दिए जाने के कारण भी इनका भविष्य संकट में है। इन सब खतरों के चलते इस वैश्विक मंच की विश्वसनीयता संकट में है, लिहाजा इसमें पर्याप्त सुधारों की तत्काल जरूरत तो है ही, वेनेजुएला के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसा करना जरूरी है, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रति सदस्य देशों में विश्वास पैदा करे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

जयंती विशेष

डॉ. मोनिका शर्मा

स्त्री चेतना का मुखर स्वर बनीं कथाकार आशापूर्णा देवी

साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य, सामाजिक-पारिवारिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव का पुख्ता धरातल भी बनाता है। स्त्री जीवन से जुड़े यथार्थ को उकेरने वाले कथानक परिवेशगत परिवर्तन के इस पक्ष पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। महिलाओं के सशक्त व्यक्तित्व, संघर्षशील विचार और व्यावहारिक जीवन से जुड़ी उलझनों को सहजता से शब्दों में ढालने वाली बांग्ला कथाकार व कवयित्री आशापूर्णा देवी ने नारी जीवन से जुड़ी इन्हीं मार्मिक बातों-हालातों को अपनी साहित्यिक यात्रा का हिस्सा बनाया। प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली देश की इस पहली महिला साहित्यकार ने अपनी रचनाओं में पारिवारिक जीवन की समस्याओं से लेकर सामाजिक परिवेश की कुंठा, स्वार्थ, दमनकारी सोच और स्त्रीमन के संवेदनात्मक पहलुओं तक का अत्यंत पैनेपन के साथ चित्रण किया है।असल में उनका रचनाकर्म बिना लाग-लपेट के महिलाओं के उत्पीड़न और समाज एवं परिवार की कटु हकीकत से मिलवाने वाली रूपरेखा लिए है। यही वजह है कि बेबाकी से कलम चलाने वाली आशापूर्णा देवी का उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान सदैव स्मरणीय है। अपनों के बीच भी उनके महिला चरित्रों की असहजता, अधिकारों की लड़ाई और संघर्षपूर्ण दिनों में मुखर भूमिका निभाने से जुड़ी सृजनशीलता ने कई पुरस्कार भी उनकी झोली में डाले। उनकी कृति 'प्रथम प्रतिश्रुति' के लिए 1976 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री से भी

नवाजा गया।ध्यातव्य है कि दूरदर्शन पर 'प्रथम प्रतिश्रुति' नामक टीवी कार्यक्रम भी प्रसारित हुआ था। विश्वभारती विश्वविद्यालय ने 1989 में उनको 'देशिकोत्तम से सम्मानित किया था। साथ ही 1994 में साहित्य अकादमी द्वारा भी आशापूर्णा देवी को साहित्य अकादमी फेलोशिप के रूप में अपना सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ज्ञात हो कि उनके रचना संसार में लगभग 225 कृतियां शामिल हैं। प्रथम प्रतिश्रुति के बाद उनके दो अन्य उपन्यास, 'सुवर्णलता' और 'बकुल कथा' भी बहुत अधिक चर्चित रहे हैं। तीन पीढ़ियों की कहानी कहती इस त्रयी 'प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा के माध्यम में उन्होंने बांग्ला साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी। इतना ही नहीं, उनकी रचनाओं का अनुवाद हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी और संस्कृत जैसी कई अन्य भारतीय भाषाओं भी हुआ है। साथ ही अंग्रेज़ी सहित बहुत सी विदेशी भाषाओं में भी उनकी कृतियों का अनुवाद किया गया है। 8 जनवरी 1909 को उत्तरी कलकत्ता में जन्मी आशापूर्णा देवी को उनकी सात दशक से अधिक की साहित्यिक यात्रा में सामाजिक समानता और घर-परिवार में बुनियादी बदलाव लाने वाले स्त्री चेतना के स्वर को बल देने वाली रचनाकार माना जाता है। समझना आवश्यक है कि आशापूर्णा देवी के रचना संसार के स्त्री चरित्र ही नहीं उनका व्यक्तिगत संघर्ष भी आम स्त्रियों के लिए प्रेरणादायी है। उनके अथक संघर्ष और अनवरत सृजन की यात्रा महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन रण में डटे रहने की सीख देते हैं।

गौरतलब है कि उस दौर के एक रूढ़िवादी बंगाली परिवार में जन्मी आशापूर्णा देवी की कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं हुई। विवाह के बाद अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने साहित्य साधना की। दूरदर्शन को दिए गए एक साक्षात्कार में आशापूर्णा देवी ने कहा था कि 'मेरे लिए गृहस्थी मेरी धरती है और साहित्य सृजन मन का आकाश। मेरी दृष्टि आकाश पर लगी रही जबकि पैर धरती पर रहे। मैंने कभी गृहस्थी और साहित्य को एक-दूसरे का पूरक या प्रतिस्पर्धी नहीं माना। मेरे लिए दोनों मेरे लिए समानांतर रहे।' इसी संतुलित सोच के साथ जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनकी कलम ने दैनिक जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं के माध्यम से स्त्रीमन की घुटन को पन्नों पर उतारा। पारिवारिक ढांचे में मौजूद पीढ़ियों के टकराव और महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई को अपने लेखन में जगह दी। समाज और परिवार की वास्तविक स्थितियों को उकेरने में उन्हें सिद्धहस्त माना जाता है। यही वजह है कि साधारण जीवन जीते हुए असाधारण कृतियाँ लिखने वाली यह रचनाकार आज भी भारतीय स्त्रियों की पथ-प्रदर्शक सी लगती हैं। उनकी रचनाएं न केवल तत्कालीन समाज की रूढ़िवादी सोच और वर्जनाओं को सामने लाती ही हैं बल्कि स्त्रियों को संघर्ष कर मुक्ति पाने का मार्ग भी दिखाती हैं।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अच्छा काम करना है तो आलस छोड़ दें

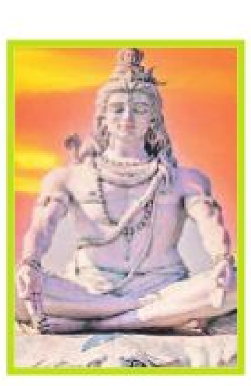

संकलित
दर्शन

शिव का अर्थ है- भोलापन। दुनिया में भोलापन उदय हो जाए, इसका उपाय है- 'शिव सूत्र'। शिव सूत्र छोटे-छोटे सुंदर सूत्र हैं। जीवन के लिए एक सूत्र ही काफी है। आपका जीवन इन सूत्रों के आनंदमय प्रकाश से भर जाएगा। जीवन में भोलापन उदय हो जाएगा। हमारा शरीर और मन दोनों अलग-अलग नियमों पर चलते हैं; जैसे- आप जितना व्यायाम करेंगे, शरीर उतना हष्ट-पुष्ट होने लगता है, लेकिन मन के लिए एक अलग ही ढंग है। आप जितना विश्राम करेंगे, मन उतना ही तेज होने लगेगा। सबने सुना है, सब भगवान की इच्छा से होता है। 'तेन विना तृणमपि न चलति' उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो भी होता है, सब भगवान ही करते हैं। जब हमें अपना पुरुषार्थ या उद्यम नहीं करना होता है, तो हम कह देते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा। जब हमारा संकल्प मजबूत नहीं होता है, तब कह देते हैं कि भगवान की इच्छा। लेकिन, ये बात और जगहों पर लागू नहीं होती है। जब भगवान भोजन कराएंगे, तब करेंगे। जब भगवान सिनेमा दिखाएंगे, तब देखेंगे। हम अपनी इच्छा और प्रभु की इच्छा को अलग-अलग मानते हैं। ऐसे लोगों को 'अनुकूल सिंधु' कहते हैं। जो अपने अनुकूल हुआ, वह मैंने किया है और जो प्रतिकूल हुआ, वह भगवान ने किया। कहीं जीत हो जाए तो मैंने जीता और कहीं हार गए तो भगवान की इच्छा। हम यह नहीं कहते हैं कि हमने अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी, इसलिए हम हार गए।

गुरु का स्थान श्रेष्ठ

संकलित
प्रेरणा

एक राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री-परिषद् के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे परन्तु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान, गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिये। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरूजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी, हे गुरुवर क्षमा कीजिएगा, मैं कई महिनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है ? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया- राजन इसका कारण बहुत ही सीधा सा है... गुरूजी ने कहा- राजन बात बहुत छोटी है परन्तु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं। आप हर दृष्टि से मुझ से पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं परन्तु यहां पर आप का और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है।.. गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परन्तु आप स्वंय ऊँचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आप से यह बात नहीं कह पा रहा था।

अंतर्मन

आज की पाती

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाएं

महात्मा गांधी का कथन है कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ के समान हैं, जो कि दर्शाता है कि किसी भी लोकतंत्र में इन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए इन संस्थाओं में चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों में योग्यता, अनुभव, लक्ष्य तथा जनहित में शुरू की गई सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने की कार्यकुशलता जैसे गुणों का होना अति अनिवार्य है। प्राचीन काल में पंच परमेश्वर व्यवस्था से वर्तमान की हाईटेक पंचायती राज व्यवस्था तक का सफर कर चुकी ये संस्थाएं आज के समय में उतनी प्रभावी नहीं बन पाई है जितना इनको होना चाहिए था। हालांकि इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास जारी हैं, जिन्हें तीव्र गति देने की जरूरत है। *- मदन अग्रवाल, रायगढ़*

करंट अफेयर

सीआईए के पूर्व एजेंट एमेस की जेल में मृत्यु

अमेरिका की खुफिया जानकारियां सोवियत संघ को बेचने वाले सीआईए के पूर्व एजेंट एल्ड्रिक एमेस की 84 वर्ष की आयु में मैरीलैंड की जेल में मृत्यु हो गई। कारागार ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि एमेस की मृत्यु सोमवार को हुई। लगभग 31 साल तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए में काम करने वाले एमेस ने स्वीकार किया था कि उन्हें 1985 से 1994 तक अमेरिकी खुफिया जानकारी बेचने के लिए मॉस्को से 25 लाख डॉलर मिले थे। उन्होंने 10 रूसी अधिकारियों और एक पूर्वी यूरोपीय अधिकारी की पहचान बताई थी, जो अमेरिका या ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने उपग्रह के जरिये जासूसी से जुड़े अभियानों, गोपनीय बातचीत और जासूसी के सामान्य तरीकों की जानकारी भी दी थी। सोवियत संघ को जानकारी साझा करने से पश्चिमी देशों के कई खुफिया एजेंट की मौत हुई थी और यह शीत युद्ध के दौरान सीआईए के लिए बड़ा झटका था। उन्होंने जासूसी और कर चोरी के आरोप स्वीकार किए थे, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक अमेरिका से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां छिपाए रखीं।

ऑफ बीट

नई शुरुआत का उत्साह जल्दी पड़ जाता है फीका

हर जनवरी के साथ कार्यालयों में नयी शुरुआत का माहौल बनता है। नयी डायरी, नयी नोटबुक और व्यवस्थित कार्य सूची (टू-डू लिस्ट) के साथ यह उम्मीद रहती है कि इस साल सब कुछ अलग होगा। लेकिन फरवरी आते-आते वही योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और शुरुआती उत्साह कम हो जाता है। आमतौर पर इसे अनुशासन या इच्छाशक्ति की कमी माना जाता है, लेकिन मनोविज्ञान इसके पीछे एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, नयी शुरुआत हमें काम शुरू करने में तो मदद करती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने में नहीं। नई शुरुआत क्यों लगती है प्रभावशाली- मनोवैज्ञानिक नयक साल को 'टेम्पोरल लैंडमार्क' मानते हैं, जो हमारे पुराने और नये रूप के बीच एक सीमा रेखा खींच देता है। 'टेम्पोरल लैंडमार्क' समय में आने वाले वे खास पल या घटनाएं होती हैं जो हमें अपने जीवन में ''नये सिरे से शुरुआत'' करने का अहसास दिलाती हैं। शोध के मुताबिक, ऐसे पड़ाव 'फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट' पैदा करते हैं, जिससे लोग बड़े और आदर्श लक्ष्य तय करने के लिए खुद को अधिक प्रेरित महसूस करते हैं।

ट्रेंड

जैव-बिटुमेन का उत्पादन

आज भारत के सड़क अवसंरचना के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है, क्योंकि हमारा देश व्यावसायिक रूप से जैव-बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सीएसआईआर और उसके समर्पित वैज्ञानिकों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई।
- नितिन गडकरी, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री

युवाओं की भूमिका

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भोपाल निवास पर युवाओं से "विकसित भारत यंग लीडर संवाद" कार्यक्रम में बात की। आप अपने ऊर्जावान विचार व संकल्प से देश को नई दिशा दें और मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाएं।
-डॉ. मोहन यादव, सीएम, मध्यप्रदेश

शो-पीस बना खेल केंद्र

यह बेहद दुखद है कि जोधपुर में हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए बनाया गया प्रदेश का इकलौता स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूट एवं हाई-परफॉर्मेंस खेल केंद्र आज एक शो-पीस बन कर रह गया है। खिलाड़ी इस संस्थान के लिए आवाज उठाएं।
- अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

विपक्ष में छटपटाहट

मनरेगा योजनाओं में जो लूट मची हुई थी, उसे वीबी-जीरामजी योजना के माध्यम से बंद कर दिया गया है। इस वजह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में छटपटाहट मची हुई है।
-बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम, झारखंड

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

कोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को प्रथम दृष्टया मानहानिकारक माना

हाईकोर्ट ने दिया निर्देशः दुष्यंत कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कटेंट हटाएं कांग्रेस और आप

2022 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या का मामला

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना नाम उछाले जाने के मामले भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने गौतम पर लगाये गए आरोपों को प्रथम दृष्टया मानहानिकारक मानते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को दुष्यंत गौतम से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने को कहा है। दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो

कर्मचारियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। बाद में सत्र न्यायालय ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिए गए एक अंतरिम आदेश में, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को हत्या के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव को कथित 'वीआईपी' बताकर टारगेट करने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से भी रोक दिया।

हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ बातें सामने आई थीं, जिनमें भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम भी कथित तौर पर जोड़ा गया था। इन आरोपों को दुष्यंत गौतम ने सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि को खराब करने की सोची-समझी साजिश बताया था। उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्यंत गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि प्रथम दृष्टया, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जानकारी मानहानिकारक प्रतीत होती है, जिससे भाजपा नेता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। इस आधार पर, अदालत ने तत्काल प्रभाव से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे दुष्यंत गौतम से संबंधित सभी विवादास्पद पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को हटा दें।

अदालत के आदेश के बाद भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने इस फैसले को कानून की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो सस्ती राजनीति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिना तथ्य और आधार के पोस्ट डालना गंदी राजनीति का सबसे घटिया रूप है और अदालत ने इस पर स्पष्ट रेखा खींच दी है।

दूसरी ओर दुष्यंत कुमार गौतम ने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पीड़ित परिवार के दर्द को राजनीतिक हथियार बनाकर तीन साल से अधिक समय तक उनका नाम घसीटा गया। उन्होंने याद दिलाया कि इतने समय में विपक्ष एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर सका जिससे उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो सके। दुष्यंत कुमार गौतम ने यह भी कहा कि पचास वर्षों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक मर्यादा का पालन किया है। इसके बावजूद उन्हें और उनके परिवार को जिस मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने भरोसा जताया कि सच अंततः सामने आएगा और झूठ की राजनीति टिक नहीं पाएगी।

खबर संक्षेप

अजित का वादा-शहर को बनाएंगे खुशहाल

मुंबई। बीएमसी चुनाव को लेकर अजित पवार की एनसीपी ने मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने वादा किया है कि एनसीपी मुंबई को एक वर्ल्ड-क्लास, सबको साथ लेकर चलने वाला और खुशहाल शहर बनाने के लिए कमिटेड है। हम मुंबई को एक ऐसा शहर मानते हैं जो हर मुंबईकर के सपनों को पूरा करे।

नोबलिस्ट सेन को एसआईआर का नोटिस

कोलकाता। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को एसआईआर का नोटिस मिला तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। टीएमसी ने इसे बंगाल के गौरव का अपमान बताया और पूछा-क्या भारत रत्न से भी यह सवाल होना चाहिए। मामले में चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी। नोटिस सिस्टम जेनरेटेड प्रॉसेस है।

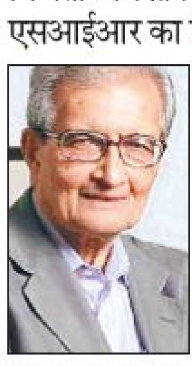

बंगाल भाजपा की समिति में 34 को मिला 'नेतृत्व'

कोलकाता। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की नई प्रदेश समिति के 34 सदस्यों के नामों की घोषणा की। राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में नई प्रदेश समिति का गठन किया गया है। इसमें 12 उपाध्यक्ष, 5महासचिव, 12 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 2संयुक्त कोषाध्यक्ष, 1-1 कार्यालय,संयुक्त कार्यालय सचिव हैं।

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने साहू

पटना। हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति को पटना हाईकोर्ट के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी।

इतिहास के दस्तावेज सामने रखकर भाजपा ने फिर किया दावा

नेहरू को थी सोमनाथ से सर्वाधिक नफरत पवित्र नदी के जल से अभिषेक को रोका था

नेहरू ने विरासत की रक्षा करने के बजाए मंदिर के पुनर्निर्माण को कम महत्व दिया

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु ने कांग्रेस की आलोचना की, सुनाई खरी-खरी

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रुख की कड़ी आलोचना की है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ऐतिहासिक आक्रांताओं ने तो मंदिर को केवल भौतिक रूप से लूटा था, लेकिन नेहरू के मन में भगवान सोमनाथ के प्रति सबसे ज्यादा घृणा थी।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए त्रिवेदी ने नेहरू द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे गए एक पत्र को साझा किया। त्रिवेदी ने दावा किया कि पत्र में नेहरू ने खान को 'प्रिय नवाबजादा' कहकर संबोधित किया और सोमनाथ के दरवाजों की कथा को पूरी तरह झूठा बताया। यह पत्र एक प्रकार का आत्मसमर्पण था, जिससे यह संकेत मिलता है कि नेहरू ने भारत की सभ्यतागत विरासत की रक्षा करने के बजाए मंदिर के पुनर्निर्माण को कम महत्व देने की कोशिश की। पाकिस्तान के दुष्प्रचार की जगह नेहरू ने पड़ोसी देश को खुश करने की बात की थी।

आक्रांताओं ने तो मंदिर को केवल भौतिक रूप से लूटा

देश के प्रथम प्रधानमंत्री को थी इससे सर्वाधिक घृणा

नेहरू ने लियाकत को 'प्रिय नवाबजादा' किया था संबोधित

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पूरी तरह से किया था विरोध

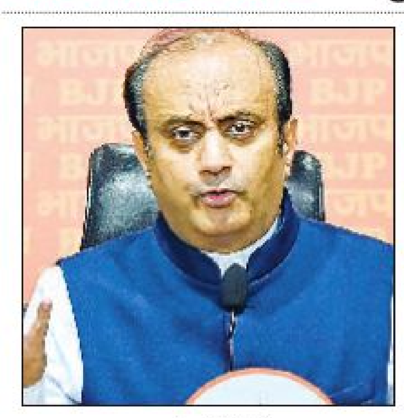

सुधांशु त्रिवेदी

पंडित नेहरू

त्रिवेदी ने दावा किया कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पूर्णतः विरोध किया था। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मंत्रिमंडल के सहयोगियों को पत्र लिखकर मंदिर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर प्रश्न उठाए थे और उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की सलाह दी थी।

मुख्यमंत्रियों को 2 बार बार पत्र भी लिखे

मंदिर निर्माण से विदेशों में भारत की छवि धूमिल हुई

त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू ने कथित तौर पर सभी मुख्यमंत्रियों को 2 बार पत्र लिख शिकायत की थी कि मंदिर निर्माण से विदेशों में भारत की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री आरआर दिवाकर को पत्र लिखा।

अंधी तुष्टिकरण की राजनीति की और मुग़ल आक्रांताओं का किया महिमामंडन

भाजपा नेता ने नेहरू पर सोमनाथ मंदिर को लेकर करारा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह अंधी तुष्टिकरण की राजनीति और मुग़ल आक्रांताओं का महिमामंडन नहीं था तो और क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते ही नहीं थे कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो।

सोमनाथ मंदिर में अभिषेक के लिए सिंधु नदी का पानी औपचारिक रूप से नामंजूर किया था

त्रिवेदी ने बताया कि नेहरू ने उस समय पाकिस्तान के भारतीय राजदूत को भी पत्र लिखा था। पाकिस्तान में भारत के राजदूत को लिखे पत्र में नेहरू ने कहा कि सोमनाथ मंदिर में अभिषेक के लिए सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल को औपचारिक रूप से नामंजूर कर दिया, विदेश सचिव के जरिए यह बताया कि इस अनुरोध को उनकी मंजूरी नहीं है और आदेश दिया कि भविष्य में ऐसे किसी भी अनुरोध को पहले से मंजूर किया जाए।

कांग्रेस के कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग का जमीनी मजबूती

चार- छह हफ्तों में होगा पूरे होंगे सारे कार्यक्रमः सिंघवी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए संगठनात्मक मज़बूती और ज़मीनी स्तर पर पुनर्गठन से जुड़े कई अहम फैसलों की जानकारी दी।

डॉ. सिंघवी ने कहा कि कुछ महीने पहले विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब पार्टी संगठन को जिला स्तर तक सशक्त और सक्रिय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की पहल के अनुरूप कानून, आरटीआई और मानवाधिकार—इन तीनों विभागों का जिला स्तर पर पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत देश के हर प्रशासनिक ज़िले में कम से कम पांच वरिष्ठ सदस्यों की टीम गठित की जाएगी, जो इन विभागों की गतिविधियों का संचालन और समन्वय करेगी।

उन्होंने बताया कि आज हुई बैठक में करीब 10–11 राज्यों के विभागीय अध्यक्षों ने प्रत्यक्ष या वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। जिन राज्यों में अभी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हैं, वहां केंद्रीय टीम द्वारा जिला स्तर पर पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

डॉ. सिंघवी ने कहा कि दूसरा अहम निर्णय 'रैपिड रिस्पांस फोर्स' के गठन से जुड़ा है। इसके तहत प्रत्येक राज्य में न्यूनतम पांच वरिष्ठ वकीलों की टीम बनाई जाएगी, जो कांग्रेस से जुड़े मामलों में अदालतों में त्वरित, प्रभावी और सशक्त कानूनी हस्तक्षेप कर सकेगी। इस पूरी प्रक्रिया को भी चार से छह सप्ताह के भीतर अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है।

तीसरे निर्णय के तहत कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग से जुड़े सदस्यों की एक व्यापक अखिल भारतीय डिजिटल डायरेक्टरी तैयार की जाएगी। यह डायरेक्टरी राज्यवार और वर्णानुक्रम दोनों रूपों में उपलब्ध होगी, जिससे ज़िला और राज्य स्तर पर त्वरित समन्वय संभव हो सकेगा।

डॉ. सिंघवी ने बताया कि जिन राज्यों में अब तक विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, वहां भी शीघ्र पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा एक नवीन और महत्वपूर्ण पहल के तहत 21 से 28 (या 21 से 30) वर्ष आयु वर्ग के युवाओं—जो कानून, आरटीआई या मानवाधिकार से जुड़े हैं और अभी कांग्रेस से औपचारिक रूप से नहीं जुड़े हैं—के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में ऐसे इंटर्न कांग्रेस के लगभग 127 सांसदों के साथ जोड़े जाएंगे और कार्यक्रम के सफल होने पर इसे विधायकों तक भी विस्तारित किया जाएगा।

डॉ. सिंघवी ने कहा कि बैठक बेहद उपयोगी रही और देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की।

जेएनयू में नारेबाजी, फडणवीस भड़के

शरजील इमाम की 'औलादों' के इरादों को हम कुचल देंगे

एजेंसी ⏭ मुंबई

दिल्ली स्थित जवावहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में लगे विवादास्पद नारों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि जेएनयू में पैदा हुईं शरजील इमाम की 'औलादों' के इरादों को कुचल दिया जाएगा। यह जेएनयू में विरोध प्रदर्शन को लेकर हुए विवाद के मद्देनजर आई है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान 53 लोग मारे गए। 700 घायल हो गए।

राहुल ने केंद्र सरकार को घेरा

ट्रंप के एक फोन से शीर्ष नेतृत्व झुक गया, फर्क समझो, सर जी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। रहुलने पिछले साल जून में कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' से संबंधित एक कार्यक्रम में दिए गए अपने भाषण का एक अंश साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ट्रंप के एक फोन से केंद्रीय नेतृत्व उनके सामने झुक गया। उस भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस तथा उसके नेताओं ने महाशक्तियों के सामने कभी 'सरेंडर' नहीं किया, लेकिन थोड़े से दबाव के आगे झुक जाना ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल स्वभाव है। कांग्रेस नेता ने इस भाषण से जुड़ा वीडियो 'एक्स' पर साझा करते हुए पोस्ट किया, 'फर्क समझो, सर जी।

बायो-बिटुमेन विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में क्रांतिकारी कदम

कृषि अपशिष्ट को मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन में बदला जा सकता हैःगडकरी

सड़क अवसंरचना में सुधार होगा, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक बना

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि कृषि अपशिष्ट को मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन में बदला जा सकता है। कृषि अपशिष्ट को एक मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन में परिवर्तित करने के तरीकों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बायो-बिटुमेन विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। 'कृषि अवशेषों से सड़क तकः पायरोलिसिस से बायो-बिटुमेन' विषय के साथ सीएसआईआर के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह में गडकरी ने कहा कि आज का दिन सड़क अवसंरचना में ऐतिहासिक उपलब्धि का दिन है, क्योंकि भारत व्यावसायिक रूप से बायो-बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।

कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके, बायो-बिटुमेन फसल जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। 15 प्रतिशत मिश्रण के साथ, भारत लगभग 4,500 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचा सकता है और आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है।

गडकरी ने सीएसआईआर और इसके समर्पित वैज्ञानिकों को बधाई दी और इस अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त करने में निरंतर सहयोग के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह नवाचार किसानों को सशक्त बनाएगा, ग्रामीण आजीविका उत्पन्न करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

सैलजा ने भर्ती पर उठाए सवाल

एचपीएससी व एचटेट में गड़बड़ियों के आरोप की हो निष्पक्ष जांच कराएं

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

सांसद कुमारी सैलजा ने एचपीएससी भर्ती प्रक्रिया और एचटेट परीक्षा परिणाम को लेकर सामने आए गंभीर आरोपों पर कहा है कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। बाहरी युवाओं को तरजीह देने, योग्य अभ्यर्थियों को वंचित करने और परीक्षा परिणामों में कथित गड़बडिय़ों ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सैलजा ने मांग की कि एचपीएससी भर्तियों और एचटेट परीक्षा प्रकरण की स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के हक की लड़ाई सडक़ से लेकर संसद तक लड़ेगी और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक सरकार पर दबाव बनाया जाता रहेगा।

सांसद बोलीः हरियाणा सरकार की महिला-हितैषी घोषणाएं खोखली

हरियाणा में भाजपा सरकार एक ओर लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की 43,747 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को उनका वैधानिक मानदेय तक समय पर नहीं दिया जा रहा। यह स्थिति सरकार के महिला-सम्मान के दावों की पोल खोलती है। सैलजा ने कहा कि जुलाई माह से केंद्र सरकार के हिस्से का मानदेय जारी नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने लगभग 3000 तक कम भुगतान मिल रहा है। इससे हजारों गरीब महिलाएं गंभीर आर्थिक संकट में फंस गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य निगरानी और प्रारंभिक शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। उन्हें बच्चों की स्कूल फीस न भर पाने और घरेलू खर्च में परेशानी हो रही।

माघ मेले में 150 साधु-संतों ने खुद को असुरक्षित बताया, मांग की

बाबाओं को भी चाहिए गनर, 90 को मिल चुकी सुरक्षा

एजेंसी ⏭ प्रयागराज

माघ मेले में प्रवास कर रहे करीब 150 साधु-संतों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए मेला पुलिस से सुरक्षा मांगी है। पुलिस के अनुसार आवेदनों में कारणों का सत्यापन गोपनीय तरीके से कराया जा रहा है। यह जिम्मेदारी स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) को दी गई है। इकाई यह जांच कर रही है कि किन साधु-संतों को वास्तव में जान का खतरा है। एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर अब तक करीब 90 साधु-संतों को सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है, जबकि शेष आवेदनों पर रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं, मेला क्षेत्र में लगे 65 से अधिक शिविरों की सामान्य सुरक्षा के लिए पहले से ही होमगार्ड की तैनाती की गई है।

65 से अधिक शिविर लगे मेला क्षेत्र में

16 महिला हेल्प डेस्क बनीं

761 फायरकर्मी तैनात किए

7 अपर अधीक्षक और कई कर्मी लगे

पुलिस इकाई जांच कर रही, किसे वास्तव में जान का खतरा

साधु-संतों के साथ गनर दिखाई दे रहे।

मेला क्षेत्र में लगे 400 कैमरे

शहर से लेकर मेला क्षेत्र में 1552 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसमें मेले में 400 कैमरे शामिल है। एक सेंट्रल कंट्रोल रूम, 16 महिला हेल्प डेस्क, 17 साइबर हेल्प डेस्क, 761 फायरकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा 20 वाच टावर भी लगाए गए हैं।

आवेदनों की एलआईयू से जांच हो रही

इस संबंध में एसपी माघ मेला नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि 60 से अधिक शिविरों में होमगार्ड और करीब 90 साधु-संतों को गनर उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य आवेदनों की एलआईयू से जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट के बाद सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

क्षेत्र की सुरक्षा में कई पुलिस टीमें लगाई गईं

7 अपर पुलिस अधीक्षक, 14 सीओ, 29 इंस्पेक्टर, 221 दरोगा, 15 महिला दरोगा, 1593 सिपाही, 136 महिला सिपाही, पीएसी की 5 बाढ़ राहत कंपनियां, 7 कानून-व्यवस्था के लिए पीएसी कंपनियां, 2 एनडीआरएफ टीमें, 1 एसडीआरएफ, 2 आरएएफ कंपनियां, संपूर्ण मेला अवधि के लिए 4 आरएएफ कंपनियां, 6 बीडीडीएस टीमें, 2 एटीएस हैं।

परिवर्तन को स्वीकार करना जीवन को सहज बना देता है

अमेरिका की अराजकता

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह यह कहा कि वेनेजुएला अमेरिका को पांच करोड़ बैरल तेल देगा और उसकी बिक्री वे खुद करेंगे, वह उनकी मनमानी का एक और शर्मनाक उदाहरण है। इससे यही सिद्ध होता है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी सेनाओं के हमले का मूल उद्देश्य इस देश के तेल संसाधन पर कब्जा करना ही था। वे इस कब्जे को लेकर जिस तरह कोई शर्म-संकोच नहीं कर रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों की कोई परवाह नहीं। वे सैन्य शक्ति के मद में चूर होकर यह देखने से भी इन्कार कर रहे हैं कि उनकी अराजकता किस तरह विश्व को संकट की ओर धकेल रही है। वे अपनी हरकतों से विश्व के दबंग देशों को मनमानी करने का लाइसेंस दे रहे हैं। उनके रवैये से विश्व में उथलपुथल मच सकती है और कुछ नए युद्ध भी छिड़ सकते हैं। खुद को शांति का मसीहा बताने और इसी बहाने नोबेल पुरस्कार की चाह रखने वाले ट्रंप दुनिया को अशांत और अस्थिर करने का काम जिस बेशर्मी से कर रहे हैं, वह उन्हें भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एक के बाद एक देश उनसे आजिज आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह डेनमार्क के अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी, उसके बाद वे यूरोपीय देश भी उनसे खफा हैं, जो हर बात में उनकी हां में हां मिलाते थे। अब इन देशों को यह समझ आ जाए तो अच्छा कि अहंकारी ट्रंप अपने मित्र देशों के भी सगे नहीं।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ट्रंप कूटनीतिक शिष्टाचार को धता बताकर भारतीय प्रधानमंत्री समेत अन्य अनेक शासनाध्यक्षों पर तंज कस रहे हैं। उनके बड़बोलेपन से यह नहीं लगता कि निकट भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापार समझौता हो पाएगा। ट्रंप भले ही ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने और लोकतांत्रिक शक्तियों को बल देने की आड़ ले रहे हों, लेकिन उनकी मनमानी का मूल कारण डालर के प्रभुत्व को कायम रखना है। डालर के दबदबे के पीछे एक बड़ी भूमिका तेल व्यापार में अमेरिकी मुद्रा का चलन है। चूंकि अमेरिका एक लंबे समय से मनमानी करता चला आ रहा है, इसलिए विश्व के देशों ने डालर से दूरी बनानी शुरू की। जब इराक और लीबिया ने ऐसा किया तो उन पर हमला किया गया। वेनेजुएला ने भी डालर के बजाय अन्य मुद्राओं में तेल बेचना शुरू कर दिया था। हालांकि तेल बिक्री-खरीद में रूस और चीन भी डालर से परहेज कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का इन देशों पर जोर नहीं, इसलिए वे कमजोर देशों को अपना निशाना बना रहे हैं। वे यह नहीं देख पा रहे कि उनके अराजक रवैये से डालर का वर्चस्व कायम नहीं रहने वाला, क्योंकि उनकी दादागीरी विश्व को डालर में व्यापार न करने के लिए ही विवश कर रही है।

निंदनीय घटना

पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान उग्र भीड़ द्वारा नारेबाजी और पुलिस पर पथराव की घटना अत्यंत निंदनीय है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है, जब ये सामने आता है कि इस घटना में चांदनी महल थाने के एसएचओ समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना मंगलवार देर रात की है, जब हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी का दस्ता रामलीला मैदान के एक हिस्से में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंचा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोग उग्र हो उठे और पथराव शुरू कर दिया।

> एमसीडी को सभी इलाकों को अतिक्रमणमुक्त करने को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए, ताकि दिल्ली को रहने योग्य स्वच्छ व सुंदर शहर बनाया जा सके

पहले अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया जाना और फिर उसे अपनी संपत्ति समझकर उसे ध्वस्त करने आए सरकारी कर्मचारियों पर पथराव कर उन्हें घायल कर देना किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में पुलिस का जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले छोड़ना और उपद्रवियों पर लाठी चार्ज करना सर्वथा उचित है। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस को सभी उपद्रवियों की पहचान कर उनपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही एमसीडी को भी राजधानी के सभी इलाकों को अतिक्रमणमुक्त करने को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए, ताकि दिल्ली को रहने योग्य एक स्वच्छ व सुंदर शहर बनाया जा सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद उमर और शरजील इमाम को जमानत न देकर सही किया?

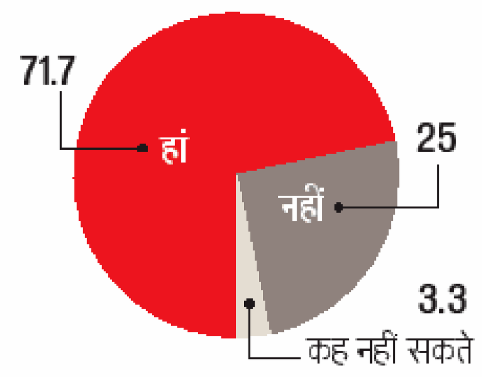

आज का सवाल
क्या ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

हमारी सभ्यतागत चेतना का प्रतीक

ज्योतिरादित्य सिंधिया

सोमनाथ मंदिर की हजार वर्ष की यात्रा हमें सिखाती है कि स्मृतियां कभी मिटती नहीं और सच्ची आस्था कभी हारती नहीं

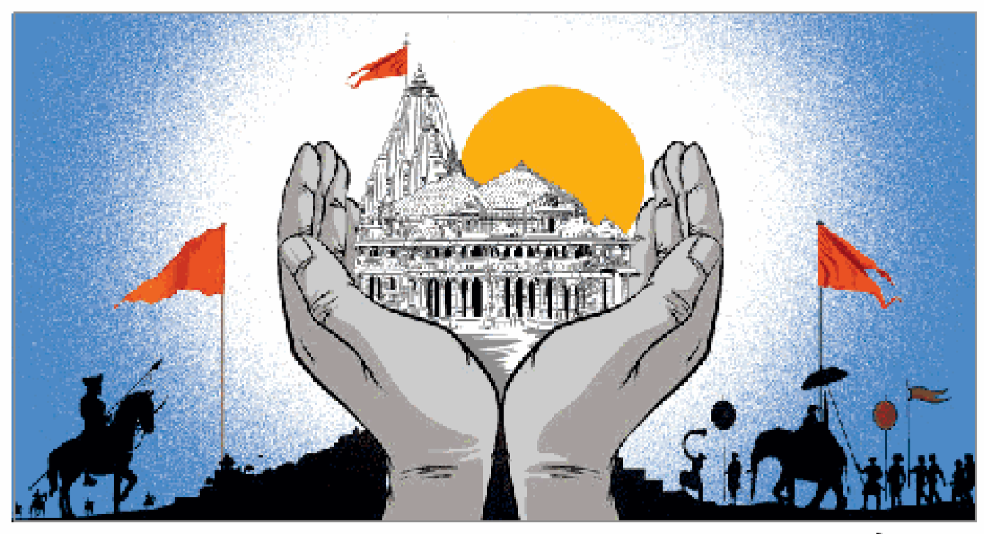

अवधेश राजपूत

सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के एक हजार वर्ष पूर्ण होना हमें उस शाश्वत चेतना का स्मरण कराता है, जिसने सदियों से भारत के आत्मा को पोषित किया। सोमनाथ की यह यात्रा प्रमाण है कि हमारी सभ्यतागत चेतना वह 'अक्षयवट' है, जिसे कोई भी आक्रांता नष्ट नहीं कर सका। महमूद गजनवी द्वारा इस पवित्र मंदिर पर किया गया आक्रमण मात्र एक स्थापत्य संरचना पर आघात नहीं, बल्कि वह उस गौरवशाली सभ्यतागत पहचान को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास था, जो युगों-युगों से इस पूण्यभूमि को भारत के रूप में परिभाषित करती आई है। वर्ष 1026 का वह घाव गहरा था, जिसने न केवल मंदिर की शिलाओं को खंडित किया, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान को भी चुनौती दी थी। हालांकि समय की धारा ने यह सिद्ध किया कि भारत की सांस्कृतिक चेतना कभी समाप्त नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के संकल्प से लेकर ज्योतिर्लिंगों की मर्यादा की रक्षा तक, यह यात्रा निरंतर जारी रही। स्वराज की इस लौ को छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मेरे पूर्वज महाराजा महादजी सिंधिया जैसे हजारों योद्धाओं ने अनवरत अपने शौर्य से जलाए रखा। इस ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिकार अठारहवीं शताब्दी में तब देखने को मिला, जब महाराजा महादजी सिंधिया की शक्ति ने भारत के स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध (1761) की भीषण त्रासदी के पश्चात, जब महादजी महाराज ने अपने परिवार के सोलह सदस्यों को खोया तो यह मराठाओं की शक्ति के अस्तित्व की कठोर परीक्षा थी। तब महादजी महाराज ने अदम्य धैर्य, निरंतर संघर्ष और दूरदर्शी रणनीति के बल पर 10 फरवरी, 1771 को दिल्ली के लालकिले पर मराठा-भगवा ध्वज फहराया। यह विजय मात्र एक नगर की प्राप्ति नहीं, बल्कि मराठा-सनातन स्वाभिमान और राजनीतिक प्रभुत्व की पुनः स्थापना का प्रतीक भी थी। वर्ष 1771 से 1803 तक दिल्ली पर सिंधिया वंश का प्रभावी नियंत्रण रहा।

वर्ष 1785 में महाराजा महादजी सिंधिया ने दिल्ली विजय के बाद लाहौर विजय अभियान आरंभ किया। उन्होंने सिखों के साथ रणनीतिक गठबंधन और स्थानीय समर्थन के बल पर सशक्त युद्धनीति अपनाई। 29 मई, 1785 को दिल्ली से भारी तोपखाने के साथ लाहौर की ओर कूच करते हुए उन्होंने अफगान गढ़ी को घेर लिया। जुलाई में हुए लगातार संघर्षों में अफगान सेनापति शाह गुलजार हुसैन, परवेज खान और अशरफ अली मारे गए। मानसून के बाद सितंबर में निर्णायक विजय मिली और मोहम्मद शाह अब्दाली को मराठाओं की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस विजय के साथ अटक से कटक तक और प्रयागराज से भरूच तक 'हिंदवी स्वराज्य' की सुदृढ़ और प्रतिष्ठित स्थापना हुई। 1785 का लाहौर युद्ध महाराजा महादजी सिंधिया की अद्वितीय सैन्य कुशलता का प्रमाण था, जिसने अफगान सेनाओं में भय उत्पन्न किया। उनके शासन में मराठा साम्राज्य अटक से कटक तथा भरूच से प्रयागराज तक विस्तृत हुआ और भगवा ध्वज सर्वत्र लहराया। इस बार लाहौर की धरती पर उन्होंने विजय पताका फहराई और अफगान सेनाओं को सिंधु के पार खदेड़ा। इस युद्ध में महादजी महाराजा ने सदियों पहले 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर किए गए उस आघात का वह सभ्यतागत प्रतिशोध लिया, जिसने भारत के आत्मा पर गहरी चोट की थी।

महाराजा महादजी सिंधिया लाहौर में मोहम्मद शाह अब्दाली के महल से वे ऐतिहासिक चांदी के द्वार वापस लेकर आए, जिन्हें गजनवी सोमनाथ से लूटकर ले गया था। उन्होंने भारी सुरक्षा में उन द्वारों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भेजने की व्यवस्था की, परंतु उन द्वारों के सोमनाथ पहुंचने पर पुजारियों का कहना था कि वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहने के कारण उन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर महादजी महाराज ने उन्हें उज्जैन भेजा, जहां गोपाल मंदिर में उन द्वारों की प्रतिष्ठा की गई। 760 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने सीमाओं के पार जाकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आक्रांताओं के चंगुल से वापस लाने का अदम्य साहस दिखाया। उन द्वारों का भारत लौटना 'सांस्कृतिक न्याय' की पुनर्स्थापना थी। 1234-1235 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा ध्वस्त किए गए महाकाल मंदिर का 1734 में उज्जैन में महादजी महाराज के पिता महाराजा राणोजीराव सिंधिया द्वारा शून्य से पुनर्निर्माण कराया गया और आगे चलकर स्वयं महादजी महाराज ने उसे भव्यता एवं गौरव का स्वरूप प्रदान किया। यही वह वैचारिक भूमि थी, जिसने सोमनाथ के गौरव को सहेजने का आधार तैयार किया।

स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण आधुनिक भारत के आत्मविश्वास का प्रखर चेहरा बना। 12 नवंबर, 1947 को लौहपुरुष सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनरुद्धार का ऐतिहासिक संकल्प लिया। सोमनाथ ट्रस्ट के संस्थापकों में से एक केएम मुंशी के प्रयासों और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद के सान्निध्य में 11 मई, 1951 को जब ज्योतिर्लिंग की प्राण-प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया ने देखा कि भारत अब अपनी सभ्यतागत जड़ों से विमुख नहीं होगा। सोमनाथ आंदोलन से प्रेरणा लेकर 1990 में राम-रथ यात्रा सोमनाथ से आरंभ हुई और 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए अयोध्या की ओर बढ़ी। इस ऐतिहासिक यात्रा के उद्घाटन में मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयाराजे सिंधिया का योगदान भी रहा है, मानो इतिहास स्वयं अपनी निरंतरता को साक्षात अनुभव कर रहा हो।

सोमनाथ कारिडोर का निर्माण इस सत्य का साक्ष्य है कि हम अपनी आस्था के केंद्रों को न केवल सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित भी कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में सोमनाथ से लेकर राम जन्मभूमि तक जो कायाकल्प हुआ है, वह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने वाला एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र बन चुका है। सोमनाथ की यह एक हजार वर्ष की यात्रा हमें सिखाती है कि स्मृतियां कभी मिटती नहीं और सच्ची आस्था कभी हारती नहीं।

(लेखक केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं)
response@jagran.com

कूटनीति में बौद्ध विरासत का उपयोग

लावण्या शिवशंकर

भारत का अपनी बौद्ध विरासत पर नियंत्रण रखना और स्वयं को उसका पालक दिखाना आवश्यक है

भगवान बौद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष ● फाइल

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष केवल कलाकृतियां नहीं हैं। ये हमारी विरासत एवं सभ्यता का अभिन्न हिस्सा हैं और भारत इसका संरक्षक है। पिपरहवा अवशेषों को एक सदी से अधिक समय बाद देश वापस लाया गया है। भारत लाए जाने के बाद इन अवशेषों को रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में ले जाया गया, जहां 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने उनका अवलोकन किया। इसके अलावा उन्हें भूटान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड भी ले जाया गया। भारत से निकले असंख्य ज्ञानी भिक्षुओं के कारण बौद्ध धर्म दुनिया के अनेक देशों में प्रचलित और स्वीकार्य है। चूंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में शासक आपसी संवाद में बौद्ध धर्म को बहुत महत्व देते थे, इसलिए विश्व सुलह और शांति के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग स्वाभाविक है। वर्तमान एशिया में लगभग 45 करोड़ बौद्ध रहते हैं, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म एक साफ्ट पावर है। भारत से ही बौद्ध धर्मावलंबी तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम आदि गए। बौद्ध धर्म पर आधारित कूटनीति चलाना भारत के लिए नई बात नहीं है। मनमोहन सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इस विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य शास्त्रीय भाषा पाली का प्रचार-प्रसार करना और एशिया से छात्रों और शोधकर्ताओं को भारत आकर्षित करना भी है। बौद्ध धर्म का कूटनीतिक उपयोग मोदी सरकार का एक अंग बन गया है। इस संदर्भ में यह ठीक ही कहा गया है कि कि मोदी सरकार की नीति है-हिंदू संस्कृति, बौद्ध विरासत।

पिपरहवा अवशेषों की कहानी भी दिलचस्प है। 1898 में अमूल्य रत्न उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में अंग्रेज जमींदार विलियम पेप को मौर्यकालीन स्तूप की खोदाई में मिले। उनके साथ कुछ अस्थि-अवशेष एक कलश में पाए गए, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी में उत्कीर्ण था कि स्वयं भगवान बुद्ध के शाक्य कुल के सदस्यों ने इसे यहां रखा है। अंग्रेजों ने कुछ रत्न श्याम (प्राचीन थाईलैंड) के बौद्ध नरेश को उपहार में दिए, कुछ श्रीलंका और म्यांमार के बौद्ध मंदिरों में भेजे और एक हिस्सा कोलकाता के संग्रहालय में रखा और करीब 334 रत्नाभूषण जमींदार पेप ने अपने पास रखे। इन्हें बीते साल उनके वंशजों ने एक नीलामी घर सूथबीज को बोली लगाने के लिए सौंप दिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सूथबीज को नोटिस भेज नीलामी रुकवाई और गोदरेज समूह ने इस अमूल्य धरोहर को भारत लाने में आर्थिक योगदान दिया, पर हर देश ऐसा नहीं कर पाता।

कोरियाई युद्ध के बाद हजारों-हजार बौद्ध पुरावशेष चोर बाजार में हाथों-हाथ बिके। कोरिया में बौद्ध धर्म का सबसे तेजी से ह्रास हुआ है, पर अपने आसपास के बौद्ध देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए बड़े पैमाने पर वहां बौद्ध गोष्ठियां होती हैं। कभी चोल साम्राज्य और तदनंतर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव में रहे दक्षिण-पूर्वी एशिया देशों की हमने उपेक्षा की। इसका फायदा पहले पश्चिमी देशों और फिर चीन ने उठाया। 2000 में मीकांग-गंगा कोआपरेशन के तहत भारत ने पांच आसियान देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के साथ-साथ परिवहन और संचार क्षेत्र में सहयोग की पहल की।

आज ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में कई संसाधनसंपन्न विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और पाली के पठन-पाठन के माध्यम से अपने राजनीतिक हित पूरे कर रहे हैं। इससे बौद्ध धर्म के अध्ययन में अप्रासंगिक त्रुटियां घर कर जाने का खतरा है, जो चिंताजनक है। हमें यह समझना चाहिए कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म पालन और संरक्षण में हमारी स्वाभाविक और निर्णायक भूमिका है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गांधार सभ्यता और उसकी शैव और बौद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भारत की है। अपने बौद्ध स्थलों का हवाला देते हुए कुछ समय पहले पाकिस्तानी राजदूत नबील मुनीर ने कहा था कि बौद्ध धर्म पाकिस्तान से कोरिया गया और वहां प्रचलित महायान बौद्ध धर्म का उद्भव भी पाकिस्तान में ही हुआ। भारत अगर पाकिस्तान की ऐसी कुटिलता का प्रत्युत्तर नहीं देगा और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म नामक वृक्ष की ही एक डाली नहीं कहेगा, तो पाकिस्तान हमारी अनमोल विरासत को हथिया सकता है। बौद्ध धर्म का सर्वेसर्वा बनने के लिए चीन भी हाथ-पांव मार रहा है। दरअसल जब भारत अपना भविष्य यूरोप और अमेरिका में देख रहा था, तब बौद्ध धर्म के सहारे चीन एशिया में अपने पांव जमा रहा था।

भारत को आज ज्यादा से ज्यादा मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति में बौद्ध धर्म पर आधारित कूटनीति बहुत कारगर हो सकती है। इसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि हम वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म से प्रभावित जनता की सद्भावना आकर्षित कर सकें। भारत का अपनी बौद्ध विरासत पर नियंत्रण रखना और स्वयं को उसका पोषक दिखाना आवश्यक हो चुका है। आज विश्व दो धुरियों में विभाजित है। एक अमेरिका और दूसरा चीन के नेतृत्व में। सर्वस्वीकार्य तीसरा ध्रुव बनने के लिए हमें हिंदुत्व और बौद्ध धर्म का समान प्रतिनिधित्व करना होगा। हमें अपने विमर्श और आख्यान का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा।

(लेखिका रिसर्च स्कालर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

ईर्ष्या-द्वेष से मुक्ति

कोई हमसे घृणा, ईर्ष्या अथवा द्वेष रखता है तो यह हमेशा ही हमारे लिए खराब बात नहीं है। देखना यह होता है कि हमें ऐसी भावनाएं कहां से और किससे मिल रही हैं? अगर कोई विद्वान, गुणी, संभ्रांत और धार्मिक व्यक्ति हमसे द्वेष रखता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बुरी बात है। हमने अवश्य ही उन सज्जन व्यक्ति का दिल दुखाया है। तभी तो वह अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध हमें पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई खराब, चरित्रहीन और भ्रष्ट हमसे द्वेष रखता है तो वह हमारे लिए बहुत चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर कुछ ऐसी अच्छाई है या हमने कुछ अच्छा किया है जो उस खराब व्यक्ति को हमसे द्वेष रखने पर विवश करता है। वस्तुतः, वे हमसे द्वेष नहीं करते, बल्कि खुद से करते हैं और उसका गुबार हम पर निकालते हैं। इस संदर्भ में अमेरिकी विद्वान एंथोनी लिसिओन ने यथार्थ ही कहा है कि जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हों तो तैयार रहें कि लोग काले बादलों और तूफानों के साथ आपके सामने से गुजरेंगे ही।

भले ही ईर्ष्या या द्वेष को जाहिर न किया जाए और वह देखने में नियंत्रित लगे, लेकिन भीतर से ऐसे भाव एक अदृश्य आभास सा लेकर आते हैं कि आसपास मौजूद हर कोई तनाव में आ जाता है। पीछे हट जाता है या सहजता खो देता है और अधिक सतर्क हो जाता है। यह सब बिना किसी सचेत प्रयास के होता है। ईर्ष्या-द्वेष ऐसी नकारात्मक भावनाएं हैं, जो अक्सर डर, असुरक्षा, चोट या अविश्वास से पैदा होती हैं। यह हमें दूसरों से अलग करती हैं। यह भी एक आश्चर्य है कि ऐसा नकारात्मक भाव भी उनके प्रति ही उत्पन्न होता है, जिनसे कहीं न कहीं कुछ लगाव भी होता है। ईर्ष्या से हमारा हृदय और जीवन दोनों भस्म होते हैं। ऐसी नकारात्मक भावनाएं स्वयं द्वारा सृजित होती हैं। इनसे मुक्ति पाकर ही जीवन को सहज एवं सुंदर बनाया जा सकता है।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

स्थिति की समीक्षा करे भारत

'भारतीय कूटनीति की परीक्षा का समय' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में शिवकांत शर्मा ने जिस बात को रेखांकित किया है, वह बिल्कुल सामयिक और पूरी दुनिया के लिए चिंतनीय है। भारत के लिए चिंतनीय इस रूप में कि भारत जिस बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था की कामना करता है, वह स्थिति दूर की कौड़ी दिखने लगी है। लोकतांत्रिक सिद्धांत और व्यवहार वास्तविक अर्थों में आज द्वंद्व की स्थिति में हैं। मानवाधिकार और लोकतांत्रिक समृद्धि के नाम पर अमेरिकी दादागीरी कमजोर राष्ट्रों को डरा रही है। रूस और चीन भले ही सामरिक एवं आर्थिक शक्ति हों, लेकिन अमेरिका की एकध्रुवीय व्यवस्था आज भी कहीं न कहीं हावी है, जो दुनिया को अपने नियंत्रण में करने को आतुर है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पंगु बन गई है। वहीं, भारत जैसा देश अपनी पारंपरिक सहिष्णुता की नीति पर चलने के बावजूद पड़ोसी देशों में अनुकूल परिवेश तैयार नहीं कर पा रहा है। भारत के लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि वह अपने पड़ोसियों को सहायता दे रहा, फिर भी इन देशों में भारत विरोधी भावना से निपट नहीं पा रहा। ऐसी समस्या का समाधान निकालना ही होगा।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर (बिहार)

राष्ट्रद्रोहियों के साथी

आज देश के विपक्षी दलों के नेता मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए कितनी हताशा और निराशा के शिकार हैं, इस बात का अंदाजा इन्हीं बातों से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह किडनैप कर लेगा? इस तरह की खोखली व अनर्गल बयानबाजी देश के नागरिकों का ही अपमान नहीं है वरन राष्ट्र को भी शर्मशार कर चव्हाण की राजनीतिक मानसिक विकलांगता, अदूरदर्शिता और हल्केपन, मनभेद को अधिक दर्शाता है। वहीं देश के टैक्सपेयर्स के पैसे पर शिक्षा प्राप्त करने वाले जेएनयू जैसे विख्यात विश्वविद्यालय के कुछ वामपंथी छात्र नेता प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती लाल होगी आदि जैसे स्तरहीन और अमर्यादित नारे लगा रहे हैं। पर्दे के पीछे से छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर आतंकियों जैसी मानसिकता पाले अदृश्य शक्तियां अपना काम कर गईं। भीषण दिल्ली दंगों में लगभग 53 निर्दोष लोगों की हत्याएं व 700 से ज्यादा घायल और सरेआम सिलीगुड़ी कोरिडोर (चिकन नेक) को काटने और उकसाने की धमकी देने के आरोपियों शरजील इमाम और उमर खालिद को देश की एपेक्स कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी पाया। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती दोनों आरोपियों को जमानत ना मिलने पर कहती हैं कि अन्याय के बोझ तले न्याय का पलड़ा टूट रहा है, निश्चित ही गैरजिम्मेदाराना बयान है। वहीं दोनों कुख्यात आरोपियों को जमानत मिलने से पहले न्यूयार्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी का ये कहना कि हम सब आपके (शरजील और खालिद) साथ हैं। निश्चित घोर निंदनीय और भारतीय न्याय-व्यवस्था में बाहरी हस्तक्षेप है। निस्संदेह वर्तमान भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाती है।

दीपक गौतम, सोनीपत

इंटरनेट मीडिया और सच की लड़ाई

आज का दौर सूचना का है, लेकिन विडंबना यह है कि इसी दौर में सच सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया है। इंटरनेट मीडिया ने हर व्यक्ति को बोलने का मंच दिया, पर साथ ही सच और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला भी कर दिया है। वाट्सएप, फेसबुक, एक्स जैसे मंचों पर खबरें इतनी तेजी से फैलती हैं कि उनके सही या गलत होने की जांच का समय ही नहीं मिलता। भावनात्मक भाषा, डर पैदा करने वाले संदेश और आधी-अधूरी जानकारी लोगों को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है। कई बार हम बिना सोचे-समझे किसी पोस्ट को आगे बढ़ा देते हैं और अनजाने में गलत सूचना के वाहक बन जाते हैं। समस्या यह नहीं है कि इंटरनेट मीडिया बुरा है। समस्या यह है कि हमने सूचना को परखने की आदत छोड़ दी है। पहले खबर अखबार या विश्वसनीय माध्यम से आती थी, अब वह किसी अनजान प्रोफाइल से भी आ सकती है। ऐसे में सच की जिम्मेदारी संस्थानों से ज्यादा आम नागरिकों पर आ गई है। जरूरी है कि हम हर संदेश पर विश्वास न करें। स्रोत देखें, भाषा पर ध्यान दें और खुद से पूछें-क्या यह जानकारी तर्कसंगत है? क्या इसे फैलाने से समाज में शांति बनी रहेगी? डिजिटल साक्षरता आज उतनी ही जरूरी हो गई है जितना पढ़ना-लिखना। इंटरनेट मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है। यह समाज को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी। फैसला हमारे हाथ में है कि हम इसका उपयोग समझदारी से करें या भीड़ का हिस्सा बन जाएं।

तरुण शर्मा, नंगली वाजिदपुर नोएडा

X पोस्ट

अगर आप किसी तानाशाह को हटाकर बिना चुनावों के जरिये ही उसकी जगह कमान संभालते हैं तो फिर आप भी तानाशाह ही हुए। जेमी @JamieBonkiewicz

तेजस्वी यादव का भांजा दो वर्ष की सैन्य सेवा के लिए सिंगापुर फौज में जा रहा है, जबकि तेजस्वी और उनका परिवार यहां अग्निवीर योजना को बकवास बताते रहे हैं।
अनुपम मिश्रा @scribe9104

बांग्लादेश में हिंदू विधवा महिला से वीभत्स अत्याचार के बारे में पढ़कर बहुत दुख पहुंचा। किसी के विरुद्ध कहीं भी इस प्रकार का अत्याचार बिल्कुल अस्वीकार्य है। यही प्रार्थना है कि पीड़िता को न्याय और आवश्यक सहायता मिले। शिखर धवन @SDhawan25

मई में भारत के आपरेशन सिंदूर और अब वेनेजुएला में अमेरिका के आपरेशन एब्सोल्यूट रीजोल्व ने यही साबित किया है कि न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए भी सशक्त सैन्य शक्ति होना बहुत आवश्यक है। आधुनिक समय में भी यही पुरानी वास्तविकता ही प्रासंगिक है। केजेएस ढिल्लों @TinyDhillon

जनपथ

कब्र खोदाई में हुआ जेएनयू एक्सपर्ट,
दिया फैसला कोर्ट ने इन्हें हो रहा दर्द।
इन्हें हो रहा दर्द सर्द दिल्ली का मौसम,
इस मौसम में खाय रहा है खालिद का गम!
सोच रहे मां-बाप लाल कर रहा पढ़ाई,
जेएनयू में लोग कर रहे कब्र खोदाई!!
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय :0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 174

संसदीय समिति करेगी रामलला के दर्शन, राहुल गांधी भी सदस्य

रमाशंकर अवस्थी ● जागरण

- रक्षा मंत्रालय की 32 सदस्यीय समिति 23 जनवरी को पहुंच रही है रामनगरी अयोध्या
- समिति के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रामनगरी जाने को लेकर बढ़ गई है दिलचस्पी

अयोध्या: रक्षा मंत्रालय की 32 सदस्यीय संसदीय समिति 23 जनवरी को रामनगरी पहुंच रही है। इस समिति में शामिल सांसद अयोध्या यात्रा के दौरान रामलला के दर्शन करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप कैंट क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस संसदीय दल के अध्यक्ष राधामोहन सिंह हैं। इस समिति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस समिति में शामिल होकर राहुल गांधी रामलला के दर्शन करेंगे या नहीं।

राहुल गांधी अभी तक रामलला के दर्शन को नहीं आए हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी भेजा गया था, किंतु तब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने रामलला से दूरी बनाए रखी थी। यद्यपि कालांतर में इक्का-दुक्का शीर्ष स्तर के कांग्रेस नेता रामलला के दर्शन करने आते रहे, किंतु सोनिया गांधी के परिवार ने अब भी रामलला से दूरी बनाए रखी है।

अयोध्या आने वाली इस समिति में संभव है कि राजनीतिक मतभेद की वजह से राहुल गांधी न शामिल हों, किंतु उनके रुख से रामलला के प्रति कांग्रेस का सरोकार जरूर ज्ञापित होगा। यद्यपि राहुल गांधी 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व अयोध्या यात्रा के दौरान श्रीराम के परम प्रिय दूत हनुमानजी का हनुमानगढ़ी पहुंच दर्शन-पूजन कर चुके हैं।

बढ़ी ठंड तो रामलला को दिन में भी ओढ़ाई गई पश्मीना शाल

जासं, अयोध्या: भीषण ठंड में जनजीवन अस्तव्यस्त है। लोग इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न कर रहे हैं तो श्रीराम मंदिर में विराजमान रामलला को भी सर्दी से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। बुधवार को गलन और अधिक बढ़ी तो उन्हें दिन में भी कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शाल ओढ़ाई गई।

पश्मीना शाल मुख्य रूप से कश्मीर में ही निर्मित होती है। सर्दी के दिनों की शुरुआत से ही रामलला को रात्रि में शयन के समय राजस्थानी रजाई ओढ़ाई जा रही है। राम मंदिर के व्यवस्थापक व विहिप पदाधिकारी गोपाल राव ने बताया कि एक भक्त ने पश्मीना शाल रामलला को भेंट की थी। ठंड बढ़ने के बाद उसे रामलला को ओढ़ाया गया है।

राम मंदिर में विराजमान रामलला को ओढ़ाई गई पश्मीना शाल ● सौ. श्रद्धालु

चौथी कक्षा के प्रश्न पत्र में कुत्ते के नाम का विकल्प 'राम' देने पर छग में हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा चार की अर्द्धवार्षिक परीक्षा के दौरान धार्मिक आस्था से संबंधित विवादित प्रश्न पूछे जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। बुधवार को अंग्रेजी विषय के पेपर में 'मोना के कुत्ते का क्या नाम है' के विकल्प में 'राम' नाम दिया गया था। इस पर हिंदूवादी संगठनों ने जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार का घेराव किया व कलेक्टर-एसपी को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी नेता विजय महतो ने कोतवाली थाने में आवेदन देकर जिला शिक्षा अधिकारी व जिम्मेदार व्यक्तियों पर धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज करने की मांग की। मामला तूल पकड़ने पर डीईओ ने कहा कि यह प्रश्न पत्र त्रुटिवश छपा था, जिसे निरस्त कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सात महिलाओं समेत 26 माओवादियों ने किया समर्पण

- इन माओवादियों पर कुल 64 लाख रुपये का घोषित था इनाम
- सुकमा के अलावा ओडिशा में भी कई गतिविधियों में संलिप्त रहे

नईदुनिया न्यूज, सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में बुधवार को 26 माओवादियों ने समर्पण किया, जिनमें सात महिलाएं भी शामिल हैं। इन माओवादियों पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम घोषित था। ये माओवादी सुकमा के साथ-साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।

प्रमुख माओवादियों में 10 लाख का इनामी लाली उर्फ मुचाकी, आठ-आठ लाख के इनामी हेमला लखमा, आसमिता उर्फ कमलू सन्नी, रामबती उर्फ संध्या और सुंडाम पाले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पांच-पांच लाख के इनामी निलेश, संदीप और मड़कम चैते ने भी समर्पण किया है। एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि शासन की समर्पण पुनर्वास नीति और पूना मार्गेम अभियान से माओवादी प्रभावित हो रहे हैं।

इस बीच, माओवादियों के हिंसक दल पीएलजीए नंबर-एक के प्रमुख हिड़मा के मारे जाने के बाद 75 लाख के इनामी बारसे देवा के तेलंगाना में सरेंडर करने के मामले में नया मोड़ आया है। देवा ने कहा कि पुलिस ने उसे चार दिन तक हिरासत में रखा और फिर समर्पण करवाया।

आत्मसमर्पित माओवादियों के साथ पुलिस अधिकारी ● नईदुनिया

एक नजर में

बिहार में दो दिन कार्यालयों में सुनी जाएंगी शिकायतें

पटना: अब बिहार में आम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सप्ताह में दो दिन- सोमवार और शुक्रवार को किसी भी सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं। दोनों दिन सरकारी अधिकारी कार्यालय अवधि में उनकी शिकायत सुनेंगे। समाधान का रास्ता निकालेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की है। (राब्यू)

नेहा राठौर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित इंटरनेट मीडिया पर किए गए उनके विवादित पोस्ट के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुर्कर की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई दमनात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। (प्रेट्र)

महादेव सट्टा एप मामले में 91.82 करोड़ की संपत्ति कुर्क

रायपुर: ईडी ने महादेव आनलाइन सट्टा एप प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 91.82 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। ईडी के छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर जोनल कार्यालय ने दुबई स्थित कंपनियों के नाम पर रखे गए 74.29 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है। ये कंपनियां कथित तौर पर मुख्य आरोपित सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छापरिया द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जिन्होंने अपराध की आय को वैध निवेश के रूप में छिपाने के लिए इनका उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां भी अटैच की गईं। (नईदुनिया प्रतिनिधि)

एनआइए कोर्ट ने गोल्डी बराड़ को भगोड़ा घोषित किया

चंडीगढ़: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की चंडीगढ़ स्थित विशेष अदालत ने आतंकी सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को भगोड़ा घोषित किया है। अदालत ने उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के तहत यह कार्रवाई की है। उसे 30 दिन के भीतर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश भावना जैन ने जारी किया। बराड़ को भारत सरकार पहले ही आतंकी घोषित कर चुकी है। उधर, सूत्रों के मुताबिक बराड़ को कनाडा से वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। (राब्यू)

इंदौर के भागीरथपुरा में टेस्टिंग के दौरान ही फूट गई पाइपलाइन

दूषित पानी से 20 की मौत के बाद भी पटरी पर नहीं आ रही व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से 20 लोगों की मौत के बाद भी नगर निगम की व्यवस्था पटरी पर आती नहीं दिख रही है। बुधवार को जिस 'टेस्टिंग' को सुधार की दिशा में अहम कदम बताया गया, उसी ने निगम की लापरवाही की पोल खोल दी। जल वितरण लाइन की जांच के लिए जैसे ही क्लोरीनयुक्त पानी छोड़ा गया, पाइपलाइन फूट गई। तेज दबाव के साथ बहता पानी घरों और दुकानों में घुस गया। आनन-फानन में सप्लाई बंद करनी पड़ी।

लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर बुधवार को पाइपलाइन फूटी, वहां पहले गड्ढा खोदकर काम किया गया था, लेकिन लाइन को सही ढंग से जोड़े बिना ही गड्ढा भर दिया गया। बुधवार को जब दबाव के साथ पानी छोड़ा गया, तो यह लापरवाही सामने आ गई। इस बीच, दूषित पेयजल को लेकर एक और गंभीर खामी सामने आई है। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल में पाए गए कोलिफार्म बैक्टीरिया का खतरा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले वर्ष फरवरी में शहर की पाश शालीमार टाउनशिप को सप्लाई होने वाले नर्मदा के पानी में भी इसी बैक्टीरिया की उपस्थिति सामने आई थी। उस समय टाउनशिप में 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। उधर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर सप्लाई किए जा रहे पानी को परखा। कई इलाकों से ड्रेनेज मिले पानी की शिकायतें सामने आईं। उन्होंने कहा कि साफ पानी के लिए लोगों को खुद संघर्ष करना होगा, सिर्फ नेताओं के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा।

मृत्यु पंजीयन के आधार पर मृतकों के स्वजन को देंगे राहत राशि: भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से मरने वालों की संख्या को लेकर आ रहे अलग-अलग आंकड़ों पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बुधवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्टकारी है। इसलिए हम इसके आंकड़ों में नहीं पड़ रहे हैं। इंदौर नगर निगम में मृत्यु पंजीयन के आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार संबंधितों के स्वजन को राहत राशि देगी।

इंदौर: सुधारी गई पाइपलाइन से परीक्षण के लिए जैसे ही पानी सप्लाई किया गया, वह फूट गई। भागीरथपुरा मुख्य मार्ग पर जलमग्न सड़क ● नईदुनिया

भागीरथपुरा क्षेत्र में डर कायम, 24 नए मरीज मिले

भागीरथपुरा क्षेत्र में बुधवार को उल्टी-दस्त के 24 नए मरीज मिले। अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन लोगों में अब भी भय बना हुआ है। दूषित पानी का असर कृष्णबाग कालोनी तक दिखाई दिया। यहां उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद 14 माह की जुड़वां बच्चियों रिद्धि और सिद्धि को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिता चंदन सिंह पवार ने बताया कि पूरे क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है।

चाकलेट दिलाने के बहाने मासूम से दरिंदगी

ननिहाल में घर के बाहर खेल रही थी बच्ची से अधेड़ ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने 12 घंटे में मुठभेड़ में आरोपित को दबोचा

जागरण संवाददाता, अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई। मुरादाबाद से ननिहाल आई और घर के बाहर खेल रही साढ़े तीन साल की बच्ची को अधेड़ दरिंदा गजेंद्र चाकलेट दिलाने के बहाने उठा ले गया। गांव से करीब 500 मीटर दूर नहर किनारे उसने उससे वहशियाना हरकत की और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। मंगलवार शाम मासूम नहीं लौटी तो मां बेचैन होकर पूरे गांव में खोजने लगीं। खेतों और नहर किनारे तलाश करते ग्रामीण तब भौचक्क रह गए, जब गंभीर हालत में बच्ची मिली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने खुद जांच की कमान संभाली। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दरिंदा बाइक से बच्ची को ले जाता नजर आया। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मुठभेड़ में आरोपित गजेंद्र को गोली मारकर दबोच लिया।

मुरादाबाद के एक गांव निवासी विवाहित अपनी मासूम बेटी के साथ करीब एक साल से अमरोहा में रह रही है। आरोपित गजेंद्र सिंह कुंदरकी भूड़ का निवासी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो देखा कि आरोपित गजेंद्र खेल रही बच्ची के पास खड़ा था। उधर, पीड़ित बच्ची ने भी पूछताछ में बताया कि उसे पांच रुपये दिखाकर चाकलेट दिलाने का लालच देकर वह अपने साथ ले गया था। आरोपित का हुलिया मिलने पर तलाश शुरू की तो वह बेगपुर मुंडा नहर के पुल पर बाइक से आता दिखा। रुकने का इशारा करने पर आरोपित ने फायर झोंक दिया। गोली वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट में जा धंसी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली गजेंद्र के बाएं पैर में लगी और वह मौके पर ही दबोच लिया गया। आरोपित राजमिस्त्री और खुद तीन बच्चों का पिता है। नशे की हालत में उसने बच्ची से दरिंदगी की। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता की आवाज की फोरेंसिक जांच के आदेश

जासं, नई दिल्ली: विशेष अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म से जुड़े मामले में पीड़िता की आवाज की फोरेंसिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश मुरारी प्रसाद सिंह की अदालत ने आरोपित शुभम सिंह की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि केस रिकार्ड में मौजूद आडियो व वीडियो रिकार्डिंग की प्रमाणिकता तय करने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी है। आडियो-वीडियो रिकार्डिंग में पीड़िता की आवाज होने का दावा किया गया है, जबकि पीड़िता ने गवाही के दौरान इन रिकार्डिंग से खुद को अलग करते हुए कहा कि आवाज उसकी नहीं है।

'अंकिता भंडारी मामले में भाजपा नेता के विरुद्ध पोस्ट हटाएं कांग्रेस-आप'

जासं, नई दिल्ली: भाजपा महासचिव व राज्यसभा सदस्य दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर किए गए मानहानिकारक पोस्ट को हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कई अन्य लोगों को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए कई अन्य प्रतिवादियों को भी ऐसा कोई भी ऐसे कंटेंट पोस्ट करने या सर्कुलेट करने से रोक दिया, जिसमें दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआइपी के तौर पर नाम दिया गया हो या निशाना बनाया गया हो।

अंकिता के पिता ने सीबीआइ जांच की जताई इच्छा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने सीबीआइ जांच की इच्छा जताई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री धामी ने इस पर सहमति जताते हुए मामले का परीक्षण कर तदनुसार ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता प्रकरण पर न्याय सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत दिवस अपने वादे के मुताबिक बुधवार देर शाम अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी भंडारी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता देने व मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया।

पूर्व विधायक राठौर की गिरफ्तारी पर रोक : नैनीताल: हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित आडियो-वीडियो प्रसारित होने के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर के विरुद्ध दर्ज मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार व शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

मुख्यमंत्री आवास में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी व माता सोनी देवी से मुलाकात करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ● फोटो:सूचना विभाग

समाज के अंतिम व्यक्ति को भी आरएसएस से जोड़ें : भागवत

जासं, वृंदावन: सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने बुधवार को हिंदुत्व के मुद्दे को प्रखरता से उठाने और समाज के अंतिम व्यक्ति को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने का संदेश दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए देश के प्रत्येक हिंदू को संघ से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में गली-गली हिंदू सम्मेलन आयोजित कर जागरूकता फैलाई जाएगी।

वृंदावन के केशवधाम में चल रही संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सात दिवसीय बैठक के चौथे दिन बुधवार को तीन सत्रों में बैठक हुई। सुबह के सत्र में संघ प्रमुख ने कहा कि अब आवश्यकता है कि हिंदुत्व के मुद्दे को प्रखरता से उठाया जाए। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदुओं के बीच अलख जगाने की जरूरत बताई। वहां संघ के जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, उनके सहयोग से गली-गली हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे तो इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी। बुधवार को बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष भी पहुंचे।

प्रांत प्रचारक पद समाप्त करने पर मंथन : कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को शाम के सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत प्रचारक का पद समाप्त करने पर मंथन चला। नई व्यवस्था में प्रांत प्रचारक के स्थान पर एक प्रदेश प्रचारक होगा और उसके नीचे संभागीय प्रचारक की नई व्यवस्था लागू हो सकती है। हालांकि, जिला प्रचारकों की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा।

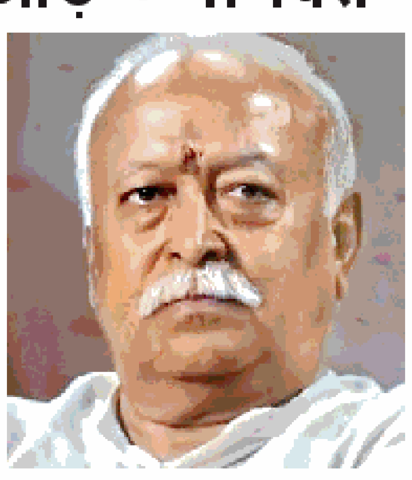

मोहन भागवत ● सौ. इंटरनेट मीडिया

जीविका दीदियों की बढ़ सकती है प्रति माह 30 हजार तक कमाई

- कृषि व ग्रामीण मंत्रालय के साथ डाक विभाग का समझौता
- डाक नेटवर्क से जुड़ेंगी देश की 12 करोड़ जीविका दीदियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच बुधवार को एक करार हुआ है, जिससे देश की लगभग 12 करोड़ जीविका दीदियों की कमाई में हर महीने 15 से 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी का रास्ता खुलेगा।

इस करार से स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, ग्रामीण उद्यमों व छोटे उद्योगों को बैंकिंग, बीमा, पेंशन, पार्सल और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं एक मंच पर मिलेंगी। डाक विभाग का एक अन्य करार कृषि मंत्रालय के साथ भी हुआ, जिससे किसानों को घटिया बीजों एवं कीटनाशकों से बचाव होगा। देश में 1.6 लाख से अधिक डाकघर हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से जीविका दीदियां डाक सखी के रूप में डाक सेवाओं, बैंकिंग सुविधाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की आपूर्ति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। इसके बदले उन्हें कमीशन आधारित नियमित आय प्राप्त होगी। समझौते के बाद ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे जीविका दीदियों की आय बढ़ेगी और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रशिक्षित डाक सखियां आधुनिक डिजिटल साधनों के साथ सेवाएं देंगी, जिससे ग्रामीण लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। समझौते से ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद अब डाक विभाग के पार्सल और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए देश और विदेश तक भेजे जा सकेंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

Y iDA FUTURE IS HERE

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1 (पी-2), ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर-201308 (उ0प्र0)

Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक : वाई.ई.ए./भूलेख/1112/2025 दिनांक 02/01/2026

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम दयौरार के सैक्टर 08 डी के अन्तर्गत आने वाली भूमि का सुनियोजित विकास हेतु सम्बन्धित कृषकों द्वारा दी गयी सहमति की दर रू0 3808/- प्रति वर्गमी0 से प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या-314/77-3-183एम, दिनांक 23.02 2018 में तय प्रक्रियानुसार निम्नानुसार क्रय किया जाना प्रस्तावित है-

क्रमांक	सैक्टर/ग्राम का नाम	खातेदार का नाम व पता	खाता संख्या	खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (है0 में)	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (है0में)
1.	सैक्टर 8डी. दयौरार	श्री गुरुदत्त शर्मा पुत्र जगमोहन शर्मा नि0 मोहबलीपुर	75 76	13 16	0.2530 7.3430	में से	0.0422 1.2239
2.	सैक्टर 8डी. दयौरार	श्री लालबहादुर पुत्र जगमोहन नि0 मोहबलीपुर	75 76	13 16	0.2530 7.3430	में से	0.0422 1.2238
3.	सैक्टर 8डी. दयौरार	श्री विनोद कुमार पुत्र जगमोहन नि0 मोहबलीपुर	75 76 376	13 16 18	0.2530 7.3430 1.8800	में से	0.0422 1.2239 0.0940
4.	सैक्टर 8डी. दयौरार	श्री किशन स्वरूप शर्मा पुत्र जगमोहन नि0 मोहबलीपुर	75 76	13 16	0.2530 7.3430	में से	0.0421 1.2238
5.	सैक्टर 8डी. दयौरार	श्री कृष्णा पुत्र जगमोहन नि0 मोहबलीपुर	75 76	13 16	0.2530 7.3430	में से	0.0422 1.2239
6.	सैक्टर 8डी. दयौरार	बाला पत्नी गिरवर नि0 बरौला, सैक्टर-134, नोएडा	184	120	0.8430	में से	0.0843
7.	सैक्टर 8डी. दयौरार	शिव कुमार कनोडिया पुत्र किशनलाल कनोडिया नि0 कौशाम्बी वसुंधरा, गा0बाद	285	209	3.8860	में से	0.1265
8.	सैक्टर 8डी. दयौरार	रघुराज सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह नि0 दिल्ली	256 255	16/2 17/2	0.0160 2.5420	में से 1/5	0.0032 0.5084
9.	सैक्टर 8डी. दयौरार	मोहनलाल पुत्र देवीराम नि0 दयौरार	140	208	1.7540	में से	0.4884
10.	सैक्टर 8डी. दयौरार	रविन्दर पुत्र मुला नि0 दयौरार	85 84	126 210	1.3030 2.9380	में से में से	0.2178 0.3843
11.	सैक्टर 8डी. दयौरार	करूटी पुत्र रेवती सिंह नि0 भयोकरा	43 142 42 41 42 42 42 42 43 43 43	94 105 128 129M 129M 130 372 373 382 383 384	0.4400 0.9480 0.2380 0.2660 0.4210 0.7840 2.8870 0.2170 0.4330 0.1093 0.5250	में से 1/3 1/3 सम्पूर्ण 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3	0.1467 0.3160 0.0795 0.2660 0.1403 0.2613 0.9623 0.0723 0.1443 0.1093 0.1760
12.	सैक्टर 8डी दयौरार	दीपक गुप्ता पुत्र विश्वनाथ नि0 बी 3/2754 पश्चिम विहार, दिल्ली	272	44	2.9020	में से	0.0843
13.	सैक्टर 8डी. दयौरार	विद्या देवी पत्नी मुनेश व भारत कुमार व लाल बहादुर पुत्रगण मुनेश नि0 मोहबलीपुर	318	34	0.9990	में से	0.1665
14.	सैक्टर 8डी. दयौरार	गायत्री पत्नी हंसराज, चन्द्रपाल, जीतु व रवि पुत्रगण हंसराज निवासी मोहबलीपुर	318	34	0.9990	में से	0.1665
15.	सैक्टर 8डी दयौरार	विमला देवी पत्नी भंवर सिंह नि0 छलैरा बांगर, तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर	392	58	4.2410	में से	0.2651

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

डिप्टी कलेक्टर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

पराली से बनेगा बायो बिटुमिन, 14 कंपनियों को टेक्नोलाजी ट्रांसफर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ कदम बढ़ाते हुए देश के विज्ञानिकों ने पराली प्रबंधन का ऐसा तोड़ निकाला है, जो न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मददगार होगा, बल्कि पेट्रो बिटुमिन के आयात पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाले देश के खजाने का 25-30 हजार करोड़ रुपये भी बचाएगा। खास बात यह है कि यह अनुसंधान प्रयोगशालाओं और पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से आगे बढ़ते हुए व्यावसायिक उत्पादन तक पहुंच चुका है। काउंसिल आफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च- सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट व सीएसआइआर-इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम देहरादून की इस सफलता की सराहना करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. जितेंद्र सिंह ने नौ राज्यों की 14 कंपनियों को व्यावसायिक उत्पादन का लाइसेंस प्रदान किया। सीएसआइआर की महानिदेशक एन. कलाइसेल्वी ने बताया कि भारत एक ही वर्ष में जैव-बिटुमिन प्रौद्योगिकी को औद्योगिक और वाणिज्यिक स्तर पर ले जाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। उन्होंने दावा किया कि पराली से बायो-बिटुमिन बनाने की यह प्रक्रिया प्रदूषण-मुक्त और लागत में काफी किफायती है। महानिदेशक ने बताया कि मेघालय में जोरबाट-शिलांग एक्सप्रेसवे पर बायो-बिटुमिन का उपयोग करके 100 मीटर का एक परीक्षण खंड बिछाया जा चुका है, जिससे जमीनी स्तर पर इसकी व्यावहारिकता की पुष्टि हुई है। इस प्रौद्योगिकी के पेटेंट के लिए आवेदन किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में अभी प्रतिवर्ष लगभग सौ लाख टन बिटुमिन की आवश्यकता होती है, जिसमें से करीब 50 प्रतिशत का आयात करना पड़ता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि यह बायो-बिटुमिन बीआइएस मानकों पर पूरी तरह खरा रहा तो इसका उपयोग हाईवे निर्माण में करने की प्रक्रिया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय शुरू करेगा।

सीएसआइआर-सीआरआरआइ और आइआइपी के सफल परीक्षण के बाद व्यावसायिक उत्पादन को हरी झंडी

एनएचएआइ ने 24 घंटे में सड़क बना बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड

प्रेट्र, अमरावती: आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु-कडपा-विजयवाड़ा इकोनामिक कारिडोर के निर्माण के दौरान सिर्फ 24 घंटे में सड़क निर्माण का ऐतिहासिक रिकार्ड बनाया गया। एनएचएआइ ने 24 घंटे में 28.95 लेन-किलोमीटर सड़क और 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर दो गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम किए।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के मसौदा पर सुझाव मांगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : कृषि मंत्रालय ने बुधवार को कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का मसौदा जारी करते हुए इस पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी। यह कानून 57 साल पुराने कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 की जगह लेगा। एक बयान के अनुसार, मंत्रालय ने संसद में पेश किए जाने से पहले कानून को बेहतर बनाने के लिए चार फरवरी, 2026 तक सभी अंशधारकों से उनकी टिप्पणियां मांगी हैं। प्रस्तावित किसान-केंद्रित कानून में कई सुधार के उपाय शामिल हैं, जिसमें किसानों को बेहतर सेवा देने के लिए पारदर्शी और उत्पत्ति स्थल की शिनाख्त के प्रविधान शामिल हैं।

एक नजर में

आइनाक्स क्लीन एनर्जी ने 3,100 करोड़ रुपये जुटाए

नई दिल्ली: आइनाक्स क्लीन एनर्जी ने ताजा इक्विटी फंडिंग दौर में 3,100 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सूत्रों ने बताया कि करीब छह प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर यह राशि विभिन्न विदेशी व घरेलू निवेशकों से जुटाई गई है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि वित्त वर्ष 2027-28 तक 10 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह राशि इस्तेमाल होगी। हालांकि, कंपनी ने बेची गई हिस्सेदारी की मात्रा को लेकर जानकारी नहीं दी है। कंपनी चालू तिमाही के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए दस्तावेज जमा करने पर भी विचार कर रही है। (प्रेट्र)

महंगे सोने से टाइटन का राजस्व 40 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: ज्वेलरी और घड़ी निर्माता कंपनी टाइटन के राजस्व में 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में 40 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इसमें सोने की कीमतों में तेजी का प्रमुख योगदान रहा है। टाटा समूह की कंपनी ने बताया कि बीती तिमाही के दौरान उसके ज्वेलरी कारोबार के राजस्व में 41 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि रही है। कंपनी के कुल राजस्व में ज्वेलरी कारोबार की करीब 85 प्रतिशत हिस्सेदारी है। अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी की सोने के सिक्के की बिक्री करीब दोगुना रही है, जिससे उनकी मजबूत निवेश वैल्यू साबित होती है। (प्रेट्र)

एटरनल को 3.7 करोड़ का जीएसटी मांग आर्डर मिला

नई दिल्ली: जोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी एटरनल को 3.7 करोड़ रुपये का जीएसटी मांग आर्डर मिला है। इसमें ब्याज और जुर्माना दोनों शामिल है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिए यह जीएसटी मांगा गया है। एटरनल ने शेयर बाजारों को बताया कि बंगाल में राज्य कर अपील्स के अतिरिक्त आयुक्त ने यह आदेश भेजा है। कंपनी का कहना है कि उसका मामला मजबूत है और वह इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकरण के सामने अपील करेगी। (प्रेट्र)

बजट में बीमा को सस्ता बनाने व दायरा बढ़ाने का एलान संभव

ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष तौर पर लाए जा सकते हैं इंश्योरेंस उत्पाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वर्ष 2047 तक सभी देशवासियों को इंश्योरेंस के दायरे में लाने का प्रयास आगामी बजट में दिख सकता है। फरवरी में पेश होने वाले बजट में ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष इंश्योरेंस उत्पाद की घोषणा की जा सकती है, जिसे जन-धन खाते से जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अब तक 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं और इन खातों में 55 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इंश्योरेंस उत्पाद को जन-धन खाते से अनिवार्य रूप से जोड़े जाने पर ये सभी महिलाएं इंश्योरेंस के दायरे में आ जाएंगी। सरकार जन सुरक्षा स्कीम को जन-धन खाते से जोड़ सकती है।

बजट में सरकार इंश्योरेंस को सस्ता बनाने के भी उपाय कर सकती है। हाल ही में आरबीआइ ने इंश्योरेंस प्रीमियम की लागत अधिक होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इस क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था लाने का लाभ ग्राहकों को नहीं मिला। इंश्योरेंस की खरीदारी पहले की तरह ही महंगी है। गत सितंबर में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की खरीदारी पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त कर दिया था। हालांकि, इसके बावजूद एजेंटों का कमीशन अधिक होने से इंश्योरेंस की लागत अधिक बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस उत्पाद पर एजेंट के कमीशन को कम किया जा सकता है। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में हो रही धोखाधड़ी पर लगाम के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में अतिरिक्त लालच देकर (मिस-सेलिंग) उत्पादों को बेचने की शिकायत बड़ी संख्या में मिल रही है। इन पर लगाम के लिए मजबूत तंत्र बनाने की घोषणा की जा सकती है या फिर नियामक प्राधिकरण को कहा जा सकता है।

- जनधन खाते से जोड़ने पर अधिकांश महिलाएं आ जाएंगी बीमा के दायरे में
- बीमा क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी पर लगाम के लिए भी उपाय संभव

"बजट में सरकार किसानों के फसल व जलवायु जोखिम बीमा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने के लिए इनके मद में अधिक राशि का आवंटन कर सकती है। बाढ़, लू व चक्रवात जैसे जलवायु जोखिमों के लिए कवरेज बढ़ाने से किसानों को आवश्यक सुरक्षा मिलेगी।"
-सुब्रता मोंडल, एमडी और सीईओ, इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस

टियर-2 व टियर-3 शहरों में इंश्योरेंस की मांग 55% बढ़ी

हेल्थ इंश्योरेंस क्षेत्र में कंपनियों को उपयोग आधारित छोटे उत्पाद लाने के लिए कहा जा रहा है। पालिसी बाजार के मुताबिक ग्राहक अब उपयोग आधारित उत्पादों की खरीदारी पर फोकस कर रहे हैं। तभी वर्ष 2025 में मेटरनिटी कवर खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या में वर्ष 2024 के मुकाबले 150 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। टियर-2 व टियर-3 शहरों में इसकी मांग में 55 प्रतिशत का इजाफा देखा गया।

आयात में कमी लाने के लिए बजट में लाई जाए प्रोत्साहन योजना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उद्योग संगठन एसोचैम के प्रेसिडेंट निर्मल कुमार मिंडा ने सरकार से बजट में आयात को कम करने के लिए प्रोत्साहन योजना लाने की मांग की है। उनका कहना है कि अभी बहुत सारे उत्पादों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का आयात किया जाता है। इस आयात में कमी लाकर निर्माण करने वाले उद्यमियों को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। आयात को कम करने के लिए ऐसे उत्पादों की पहचान करनी चाहिए जिनका उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा सकता है। इससे मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात बिल भी कम होगा।

मिंडा ने कहा कि मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन के लिए निजी क्षेत्र को औद्योगिक इलाके स्थापित करने के लिए आगे लाया जाना चाहिए। इस औद्योगिक इलाके में कोई भी उद्यमी सिर्फ शुल्क देकर उत्पादन शुरू कर सकता है। वियतनाम और इंडोनेशिया में इस प्रकार के माडल से मैन्यूफैक्चरिंग हो रही है। इससे एमएसएमई को निर्माण विस्तार में मदद मिलेगी। किसी भी वस्तु के निर्माण में 40 प्रतिशत लागत जमीन व भवन की होती है। अगर जमीन व भवन उन्हें मामूली किराए पर मिलेंगे तो उनकी लागत कम होगी।

निर्मल मिंडा

- एसोचैम के प्रेसिडेंट ने कहा, निजी क्षेत्र के लिए बनें औद्योगिक इलाके
- मिंडा बोले- सरकार को बजट में और बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य पर फोकस करना चाहिए

चांदी 5,000 रुपये बढ़ फिर नए रिकार्ड पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: बुधवार को चांदी कीमतें 5,000 रुपये बढ़कर 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकार्ड पर पहुंच गईं। मंगलवार को यह सफेद धातु 2,51,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने सुरक्षित निवेश की अपील को बढ़ाया है। वहीं औद्योगिक इस्तेमाल में बढ़ोतरी ने चांदी कीमतों को नए रिकार्ड पर पहुंचाने में मदद की है।

एक विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि निवेशकों की लगातार खरीदारी और एक जनवरी से चीन द्वारा निर्यात पर लगाई गई रोक से भी चांदी की कीमतें बढ़ीं। इस बीच सोने की कीमत कीमत 100 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि पिछली बार यह 1,41,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि हाल की रैली के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे बुधवार को सोने में गिरावट दर्ज की गई।

भारत को बढ़ाना चाहिए चांदी का प्रसंस्करण

नई दिल्ली, प्रेट्र: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) का कहना है कि भारत को चांदी के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही इसके लिए दीर्घकालिक विदेशी खनन आपूर्ति सुनिश्चित करने, घरेलू रिफाइनिंग और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने, आयातित तैयार चांदी पर निर्भरता कम करने और आयात स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है।

जीटीआरआइ के अनुसार, चीन विश्व का प्रमुख चांदी प्रसंस्कर्ता है, जो लगभग 5.6 अरब डालर की चांदी का आयात करता है। यह धातु को घरेलू स्तर पर परिष्कृत करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों व सौर पैनलों में उच्च मूल्य वाली चांदी का निर्यात करता है। इसके विपरीत, भारत ने 2024 में लगभग 6.4 अरब डालर की परिष्कृत चांदी का आयात किया, जो वैश्विक व्यापार का 21.4 प्रतिशत है, जिससे यह तैयार चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है।

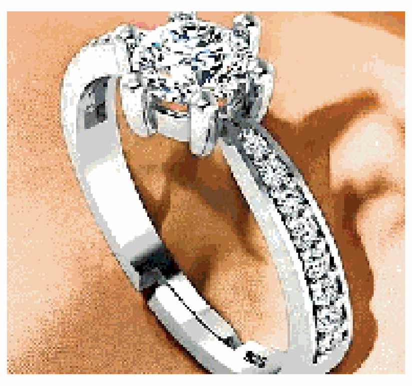

आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआइ ने आयातित तैयार चांदी पर निर्भरता घटाने, आयात स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत बताई

जीटीआरआइ के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत को घरेलू मूल्य संवर्धन के लिए चांदी को खनिज स्तर से प्रसंस्कृत करना सीखना चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने केवल 47.84 करोड़ डालर के चांदी उत्पादों का निर्यात किया, जबकि 4.83 अरब डालर का आयात किया, जो इसकी गहरी आयात निर्भरता को दर्शाता है। यह निर्भरता 2025 में बढ़ गई है। अक्टूबर 2025 में आयात अकेले 2.7 अरब डालर तक पहुंच गया और इसमें वार्षिक आधार पर 529 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नवंबर में आयात 126 प्रतिशत बढ़कर 1.1 अरब डालर रहा है। कुल मिलाकर, जनवरी-नवंबर 2025 के दौरान आयात 8.5 अरब डालर तक पहुंच गया और पूरे वर्ष के लिए 9.2 अरब डालर का अनुमान है, जो 2024 की तुलना में लगभग 44 प्रतिशत अधिक है।

श्रीवास्तव ने कहा कि चांदी की सप्लाई चेन बहुत कम पारदर्शी है, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ रणनीतिक होती जा रही हैं। आयात विविधीकरण महत्वपूर्ण है, खासकर जब चीन ने निर्यात नियंत्रण को कड़ा किया है। नए नियमों के तहत, केवल अनुमोदित कंपनियां चांदी का निर्यात कर सकती हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति चिंताओं में वृद्धि हुई है। चांदी की मांग का 55-60 प्रतिशत औद्योगिक है।

तीन दिन में 800 अंक गिरा सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र: भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के एलान से जुड़ी चिंताओं के चलते बुधवार को लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट रही। बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक 102.20 अंक गिरकर 84,961.14 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह 445.85 अंक गिरकर 84,617.49 पर आ गया था। वहीं एनएसई निफ्टी 37.95 अंक गिरकर 26,140.75 पर आ गया। पिछले तीन दिनों में सेंसेक्स में 800 अंक और निफ्टी में 186 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

कारोबारियों ने कहा कि लगातार विदेशी फंड की निकासी से बाजार नीचे आया। हालांकि, कुछ ब्लू-चिप शेयरों में खरीदारी से इक्विटी को सपोर्ट मिला। सेंसेक्स में मारुति, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील में सबसे ज्यादा गिरावट रही।

दिसंबर तक 94 हजार हो जाएगा सेंसेक्स

नई दिल्ली, प्रेट्र: वैश्विक अनिश्चितताओं और शेयर बाजार में ऊंचे मूल्यांकन के बीच बीएसई का प्रमुख मानक सूचकांक अपने मौजूदा स्तर 84,805 के मुकाबले करीब 11 प्रतिशत की बढ़त के साथ दिसंबर, 2026 तक 93,918 अंक तक पहुंच सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्लाइंट एसोसिएट्स ने अपनी वार्षिक इक्विटी आकलन रिपोर्ट में कहा कि बहुत अधिक उतार-चढ़ाव वाले मौजूदा बाजार परिवेश में सोना और चांदी निवेश पोर्टफोलियो के लिए अहम संतुलनकारी संपत्ति बनकर उभर रहे हैं। क्लाइंट एसोसिएट्स फर्म अमीर और बेहद अमीर निवेशकों के लिए सात अरब डालर से अधिक मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करती है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में कीमती धातुओं का प्रदर्शन मजबूत रहा। कमजोर डालर, भू-राजनीतिक तनाव और मौद्रिक नीतियों में बदलाव के कारण सोने की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। खासकर केंद्रीय बैंकों की खरीद से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की भूमिका और मजबूत हुई। वहीं, वैश्विक आपूर्ति संबंधी चिंताओं और अमेरिका-चीन तनाव के कारण चांदी की कीमतों में भी पिछले साल तेज उछाल देखा गया।

वर्ष 2026 के संदर्भ में कंपनी का मानना है कि इस साल बाजार की दिशा व्यापक तेजी से हटकर चुनिंदा, बुनियादी कारकों पर आधारित अवसरों की ओर बढ़ सकती है। रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8 प्रतिशत बताया गया है।

- क्लाइंट एसोसिएट्स के मुताबिक, मौद्रिक नीतियों में बदलाव से सोने की मांग में वृद्धि हुई
- कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8% लगाया

"भारत की घरेलू आर्थिक मजबूती और बेहतर आय अनुमान सकारात्मक हैं, लेकिन ऊंचे मूल्यांकन और वैश्विक जोखिमों के बीच निवेशकों को संतुलित और अनुशासित रणनीति अपनाने की जरूरत होगी।"
-नितिन अग्रवाल, इन्वेस्टमेंट रिसर्च हेड, क्लाइंट एसोसिएट्स

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

12 प्रमुख भाषाओं के सिनेमा को एक मंच पर लाएगा इंडियन नेशनल सिने एकेडमी

मुंबई: हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, बांग्ला और पंजाबी समेत देश की प्रमुख भाषाओं के सिनेमा को एक मंच पर साथ लाने के उद्देश्य से बुधवार की रात मुंबई में इंडियन नेशनल सिनेमा एकेडमी की घोषणा हुई। जिसकी स्थापना निर्माता विष्णुवर्धन इंदुरी ने की है। इसके तहत देश की प्रमुख 12 भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री के वार्षिक कान्क्लेव, अवार्ड समारोह का आयोजन तथा कलाकारों, क्रिएटिव व्यक्तियों का डाटाबेस एक जगह एकत्र होगा। पहले संस्करण की घोषणा नौ मार्च को मुंबई में की जाएगी। (**एंटरटेनमेंट ब्यूरो**)

चुनावी पारदर्शिता से जुड़ी पहल में 23 जनवरी को जुटेंगे 90 देशों के प्रतिनिधि

नई दिल्ली: देश के अंदर भले ही चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे सराहा जा रहा है। करीब सौ करोड़ मतदाताओं की हिस्सेदारी वाले चुनाव को कम समय में और पारदर्शी तरीके से कराने के अपने तौर-तरीके व अनुभवों को भारत निर्वाचन आयोग अब दुनिया के साथ साझा करेगा। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर 21 से 23 जनवरी 2026 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के 90 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। (**जाब्यू**)

चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा इकाई बनाएगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने बुधवार को देश में सीपेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हजारों चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष सुरक्षा इकाई की स्थापना की घोषणा की। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बीजिंग में चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री वांग शियाओहोंग से मुलाकात के दौरान यह घोषणा की। नकवी ने कहा, "चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में विशेष सुरक्षा इकाई (एसपीयू) स्थापित की जा रही है।" सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वांग ने नकवी से कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं की महत्वपूर्ण सहमति को पूरी तरह से लागू करेंगे। (**प्रेट्र**)

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों व आतंकियों के बीच मुठभेड़

जागरण टीम, बिलावर/ कठुआ : जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के पहाड़ी बिलावर क्षेत्र में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब चार घंटे तक दोनों तरफ से चली गोलीबारी के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकले। आतंकियों की संख्या तीन बताई गई है। ये जैश-ए-मोहम्मद के वहीं आतंकी हो सकते हैं, जो हीरानगर से घुसपैठ करने के लिए कई दिनों से लगातार सीमा पार देखे जा रहे थे। यह 2026 का पहला बड़ा आतंकरोधी आपरेशन है।

पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी ने इंटरनेट मीडिया पर इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। इस अभियान की निगरानी एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा खुद कर रही हैं। जानकारी अनुसार स्थानीय लोगों ने शाम लगभग चार बजे कमाड नाला के पास संदिग्ध देखे। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस का विशेष अभियान दल (एसओजी) मौके पर पहुंचा। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया और मुठभेड़ शुरू हुई।

कश्मीर में 22 ठिकानों पर छापे, 22 हिरासत में लिए

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: कश्मीर में दम तोड़ रहे आतंकवाद को वित्तीय आक्सीजन देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ और आतंकी संगठनों के हैंडलरों ने अब फर्जी बैंक खातों के इस्तेमाल का सहारा लिया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलीजेंस-कश्मीर (सीआइके) विंग ने एक विशेष जांच के दौरान इसका पर्दाफाश करते हुए बुधवार को कश्मीर में 22 जगहों पर छापे मारे। इस दौरान 22 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

ग्रोक की ओर से बनाई जाने वाली अश्लील तस्वीरों पर कई देशों ने जताई चिंता

लंदन, एपी: एलन मस्क के प्लेटफार्म एक्स के एआइ चैटबाट ग्रोक की ओर से महिलाओं और बच्चों की अश्लील तस्वीरें बनाए जाने को लेकर दुनिया भर की सरकारों ने चिंता जाहिर की है और इसकी आलोचना की है। ब्रिटेन के शीर्ष प्रौद्योगिकी अधिकारी ने मंगलवार को मांग की कि एक्स इस पर तत्काल कार्रवाई करे। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने ग्रोक की निंदा की है जबकि भारत, फ्रांस, मलेशिया और ब्राजील के अधिकारियों और नियामकों ने मंच की निंदा की है और जांच की मांग की है। अलग-अलग देशों की ओर से बढ़ती चिंता ऐसे एप की भयावह क्षमता की ओर इशारा करती है, जो एआइ का उपयोग करके यौन डीपफेक तस्वीरें उत्पन्न करते हैं।

समस्या पिछले साल ग्रोक इमेजिन के लांच होने के बाद सामने आई। यह यूजर्स को टेक्स्ट प्राम्प्ट टाइप करके वीडियो और तस्वीर बनाने की अनुमति देता है। इसमें एक "स्पाइसी मोड" शामिल है। पिछले महीने के अंत में यह और खतरनाक हो गया, जब ग्रोक ने दूसरों द्वारा पोस्ट तस्वीरों को संशोधित करने के लिए बड़ी संख्या में यूजर्स अनुरोधों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक्स ने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि ग्रोक के माध्यम से उत्पन्न ऐसी सामग्री मौजूद है। इसने एक पोस्ट में दावा किया कि यह बाल यौन शोषण सामग्री सहित अवैध सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करता है।

ग्रोक के अश्लील एआइ कंटेंट पर एक्स ने दिया जवाब, मंत्रालय ने जांच शुरू की

नई दिल्ली, प्रेट्र: आइटी मंत्रालय ने एआइ चैटबाट ग्रोक के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक्स द्वारा दिए गए जवाब और सबमिशन की जांच शुरू कर दी है। साथ ही सरकार ने एक्स से ग्रोक एआइ से जुड़े अश्लील कंटेंट पर उठाए गए कदमों और भविष्य में इसे रोकने के लिए उठाए कदमों पर और ज्यादा जानकारी मांगी है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स को बुधवार शाम पांच बजे तक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। मंत्रालय ने एक्स को चेतावनी दी है कि यदि वह उचित सावधानी बरतने में विफल रहता है तो उसे आइटी एक्ट की धारा 79 के तहत दी गई छूट गंवानी पड़ेगी।

शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एडेड डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का पता चला है। जांच में नकल माफिया की सक्रिय भूमिका, फर्जी प्रश्नपत्र और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दिया है। जांच में आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष कीर्ति पांडेय के गोपनीय सहायक महबूब अली की संलिप्तता उजागर हुई। इसी कारण कीर्ति पांडेय से त्यागपत्र लिया गया था ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके।

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या-51 के तहत एडेड डिग्री कालेजों में 910 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 16 और 17 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए करीब 82 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा के बाद ही बड़े पैमाने पर धांधली, नकल और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने लगी थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसटीएफ से गोपनीय जांच कराई गई। जांच के दौरान पिछले वर्ष 20 अप्रैल को एसटीएफ ने फर्जी प्रश्नपत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निरस्त करने के आदेश दिए।

- एसटीएफ जांच में धांधली, प्रश्नपत्र लीकेज और अवैध वसूली का हुआ पर्दाफाश
- आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष के गोपनीय सहायक की संलिप्तता उजागर

ब्लाक होने के बाद भी दुश्मन पर वार करेगा ये मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन

डीएवीवी की बड़ी उपलब्धि: सेना के टास्क पर डेढ़ साल की रिसर्च के बाद अमोघ द्विवेदी और पार्थ तिवारी ने तैयार किया 10 फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला ड्रोन

दस फ्रीक्वेंसी पर करता है काम

- ड्रोन एक साथ दस अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने में सक्षम है।
- आपरेशन के दौरान यदि एक फ्रीक्वेंसी ब्लाक होती है, तो ड्रोन तुरंत दूसरी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाता है।
- नौ बार तक फ्रीक्वेंसी ब्लाक होने के बावजूद भी यह ड्रोन मिशन जारी रख सकता है।
- आगे के चरण में ड्रोन को इस तरह अपग्रेड करने पर काम हो रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से बचाव की क्षमता और बेहतर हो सके।

रेंज और पेलोड क्षमता

- वर्तमान में ड्रोन की रेंज करीब छह किलोमीटर है।
- दो किलो तक वजन उठाने की क्षमता है।
- इन क्षमताओं के आधार पर ड्रोन को सुरक्षा आपरेशनों में सामग्री पहुंचाने जैसे प्रयोगात्मक उपयोगों के लिए सक्षम बनाया गया है। फिलहाल इसके रेंज और पेलोड क्षमता बढ़ाने पर काम जारी है।

आसान भाषा में समझें

समस्या: सिंगल फ्रीक्वेंसी ड्रोन आसानी से ब्लाक हो जाते हैं।
समाधान: मल्टी-फ्रीक्वेंसी हापिंग तकनीक।
लाभ: ब्लाक होने के बाद भी आपरेशन जारी।
भविष्य: एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर बचाव की क्षमता।

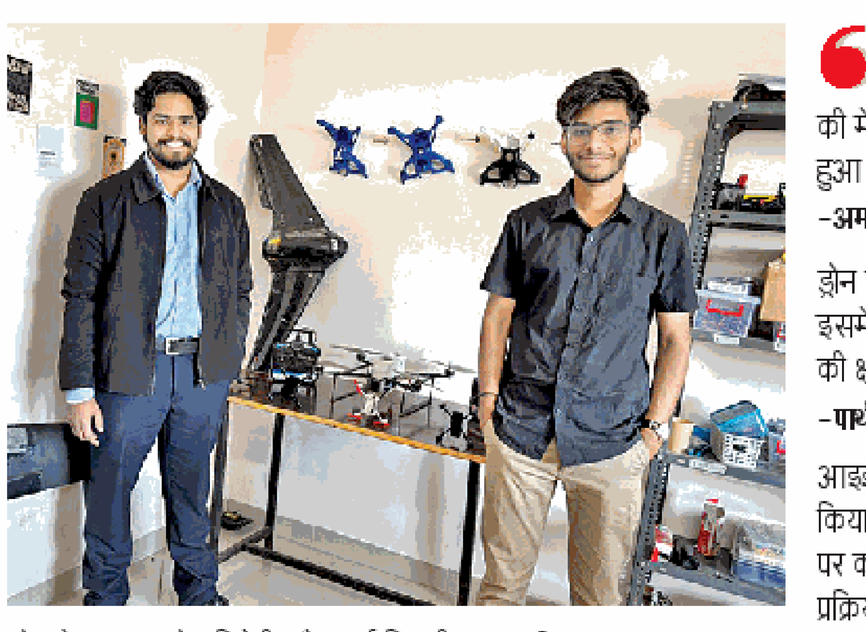

ड्रोन के साथ अमोघ द्विवेदी और पार्थ तिवारी • नईदुनिया

"हम पिछले दो वर्षों से ड्रोन टेक्नोलाजी पर अनुसंधान एवं विकास कर रहे हैं। डेढ़ साल की मेहनत के बाद यह मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन तैयार हुआ है, जिसकी टेस्टिंग भी सफल रही है।
-अमोघ द्विवेदी, छात्र, आइईटी (डीएवीवी)

ड्रोन को अपग्रेड करने की दिशा में काम जारी है। इसमें रेंज बढ़ाने और एयर डिफेंस सिस्टम से बचाव की क्षमता को और मजबूत करने पर फोकस है।
-पार्थ तिवारी, छात्र, आइईटी (डीएवीवी)

आइईटी के विद्यार्थियों द्वारा मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन पर किया गया कार्य सफल रहा है। ड्रोन इस तकनीक पर काम कर रहा है और अब इसके अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चल रही है। **-शांतनु वाइकर,** प्रभारी सीइओ, डीएवीवी इनक्यूबेशन सेंटर"

जागरण विशेष

भरत मानधन्या • नई दुनिया

इंदौर: रक्षा क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। निगरानी से लेकर आवश्यक सामग्री पहुंचाने तक, आधुनिक युद्ध और सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन अहम कड़ी बन चुके हैं। इसी दिशा में इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के छात्रों ने एक ऐसा मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन विकसित किया है, जो दुश्मन द्वारा फ्रीक्वेंसी ब्लाक किए जाने की स्थिति में भी गिरता नहीं और अपना आपरेशन जारी रखता है। एक साथ कई फ्रीक्वेंसी पर काम करने की क्षमता के कारण यह ड्रोन जटिल परिस्थितियों में अधिक भरोसेमंद साबित हो सकता है।

डीएवीवी के इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी संस्थान (आइईटी) के विद्यार्थी अमोघ द्विवेदी और पार्थ तिवारी ने इस ड्रोन को विकसित किया है, जिसे 'फ्रीक्वेंसी हापिंग कामिकाजा ड्रोन' नाम दिया गया है।

कामिकाजा ड्रोन ऐसे मिशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिनमें लक्ष्य तक पहुंचना ही प्राथमिक उद्देश्य होता है। इन्हें वापसी के लिए नहीं, बल्कि मिशन पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। तकनीकी भाषा में इन्हें लाइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है।

आम तौर पर ड्रोन सिंगल फ्रीक्वेंसी पर संचालित होते हैं। ऐसे में यदि दुश्मन उस फ्रीक्वेंसी को ब्लाक कर दे, तो ड्रोन निष्क्रिय हो सकता है। इसी तकनीकी कमी को दूर करने के लिए छात्रों ने मल्टी-फ्रीक्वेंसी हापिंग सिस्टम विकसित किया है, जिससे ड्रोन ब्लाक होने के बाद सक्रिय रह सकता है। यह दुश्मन क्षेत्र में ग्रेनेड लांच करने या आरडीएक्स ले जाने में सक्षम है।

सेना के टास्क पर हुआ अनुसंधान: विद्यार्थियों के अनुसार, वे पिछले दो वर्षों से ड्रोन टेक्नोलाजी पर अनुसंधान कर रहे थे। इसी दौरान सेना की एक तकनीकी टीम की ओर से मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन विकसित करने का टास्क मिला।

जिस पर करीब डेढ़ साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ड्रोन का प्रोटोटाइप तैयार किया। इसकी टेस्टिंग पहले प्रयोगशाला स्तर पर हुई, इसके बाद सेना के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इस नवाचार के लिए पेटेंट आवेदन भी किया गया है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

जस्टिस वर्मा केस में लोस अध्यक्ष द्वारा जांच समिति गठित करने पर रोक नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा में प्रस्ताव खारिज किए जाने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने पर न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत कोई रोक नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने जस्टिस वर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के इस तर्क से भी असहमति जताई कि तत्कालीन राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपसभापति को प्रस्ताव खारिज करने का अधिकार नहीं है।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि लोस अध्यक्ष द्वारा जांच समिति के गठन के तरीके में खामियां प्रतीत होती हैं। वह जांच करेगा कि क्या यह खामी इतनी गंभीर है कि कार्यवाही समाप्त करने की आवश्यकता है? रोहतगी ने शुरू में ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति के गठन का विरोध करते हुए कहा कि यदि महाभियोग प्रस्ताव लोस व राज्यसभा में एक ही दिन एक साथ पेश किए जाते हैं, तो समिति का गठन दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

पड़ोस की चिंता

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या के सिलसिले का न रुकना बहुत दुखद और चिंताजनक है। बीते 36 दिनों में 11 से ज्यादा अल्पसंख्यकों को बर्बर ढंग से मारा गया है। मारे गए लोगों में वे हिंदू बुजुर्ग दंपति भी शामिल हैं, जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शामिल थे। बीते महीने 2 दिसंबर से हत्याओं का जो सिलसिला चला, वह 18 दिसंबर को दीपू दास की बर्बर हत्या के बाद पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। बांग्लादेश को हर प्रकार से नसीहतें मिलीं। संयुक्त राष्ट्र ने भी नेक सलाह दी, पर वहां सांप्रदायिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए गहरी चिंता का विषय है। ध्यान रहे, वहां हिंदुओं की मौत के मामले तो चर्चा में आ रहे हैं, पर उन्हें वहां जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। यह कहने में भी दुख होता है कि महिलाओं से बलात्कार से लेकर धर्म परिवर्तन के दबाव तक, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की परेशानियों की कोई सीमा नहीं है।

इसमें एक बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत की थोड़ी-सी नाराजगी भी बांग्लादेश में उल्टा असर कर रही है। चूंकि यह तनाव क्रिकेट तक पहुंच गया है, तो बुधवार को बांग्लादेश प्रीमियर लीग की एक भारतीय प्रेजेंटर को आखिरी वक्त में अनुबंध से अलग कर दिया गया। भारत में ट्वंटी-20 क्रिकेट विश्व कप के आयोजन को लेकर भी बांग्लादेश ने नाराजगी को छिपाया नहीं है। बांग्लादेश नहीं चाहता कि उसकी क्रिकेट टीम भारत में खेले। वहां आईपीएल के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे, बांग्लादेश को इस बात की परवाह जरूर होनी चाहिए कि ऐसे बर्ताव से उसे ही नुकसान होगा। वहां तत्काल प्रभाव से सामाजिक स्थितियों को संभालना चाहिए। बीएनपी के नए नेता तारिक रहमान के बयानों से उम्मीद तो जगती है, क्योंकि वह बांग्लादेश की आजादी के उस दौर को याद कर रहे हैं, जिसे भुलाने-मिटाने की कोशिश में बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। वहां फरवरी में चुनाव होने हैं, उस देश को पूरा ध्यान चुनाव और अच्छी सरकार चुनने पर लगाना चाहिए, मगर कभी भारत के प्रति विद्वेष, तो कभी हिंदुओं को निशाना बनाने की परिपाटी इस पड़ोसी देश को पीछे ले जा रही है। ढाका के रहनुमाओं को भूलना नहीं चाहिए कि उनके यहां जब अल्पसंख्यकों का शोषण होता है, तब उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है।

आज समझदार होना समय की सबसे बड़ी मांग है। शिकायतें हमेशा रही हैं और रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है इंसानी ईमान और अमन-चैन बनाए रखना।

कोई दोराय नहीं कि भारतीय समाज को सद्भावी बनाए रखने की चुनौतियां बढ़ रही हैं। सद्भाव कभी एकतरफा नहीं होता, परस्पर अच्छे व्यवहार से ही उत्पन्न होता है। बांग्लादेश में कभी 22 प्रतिशत हिंदू थे। वह 1988 में इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ, तब से अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गईं। वहां कभी 18 गुरुद्वारे थे, अब पांच से भी कम बचे हैं। चंद सिख परिवार ही वहां रह बचे हैं। बौद्धों और ईसाइयों का भी हाल बुरा है। आज वहां आठ प्रतिशत हिंदू भी नहीं हैं। वहां की कार्यवाहक सरकार अपने देश को उस पाकिस्तान के नक्शेकदम पर ले जाना चाहती है, जहां हिंदुओं की आबादी सिर्फ दो प्रतिशत रह गई है। ऐसे पड़ोसियों को पूरी ईमानदारी से भारतीय समाज की ओर देखना चाहिए, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है। आज समझदार होना समय की सबसे बड़ी मांग है। शिकायतें हमेशा रही हैं और रहेंगी, पर सबसे बड़ी जरूरत है इंसानी ईमान और अमन-चैन बनाए रखना। कौन नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया के देश गुरबत से निकलें, पर इसके लिए जरूरी है कि हम एक-दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ें।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
08 जनवरी, 1951

प्रादेशिक सेना

आजकल देश में प्रादेशिक सेना सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं देशवासियों पर आ पड़ी है। देश में यह मांग बहुत पुराने जमाने से की जा रही थी कि देश के लोगों के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में व्यापक पैमाने पर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा। लोगों के व्यापक रूप में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें अपने के लिए खतरा नजर आया। फिर भी उन्होंने लोकमत की मांग को यत्किंचित संतुष्ट करने के लिए सन् 1919 में प्रादेशिक सेना की शुरुआत की। इस सेना में भर्ती होने और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का बहुत थोड़े भारतीयों को अवसर मिला। किन्तु देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भारतीयों के सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग की बाधायें बड़ी हद तक दूर हो गयी हैं। स्वतंत्र भारत की सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रादेशिक सेना संगठित करने का निर्णय किया है, ताकि काफी तादाद में देशवासी सैनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। अक्तूबर सन् 1949 से प्रादेशिक सेना में नयी भर्ती शुरू की गई है।

प्रादेशिक सेना नियमित सेना नहीं है। कोई भी राष्ट्र बड़ी संख्या में नियमित सेना नहीं रख सकता; कारण ऐसा करने के लिए उसे काफी व्यय करना पड़ेगा। भारत के लिए तो बड़ी नियमित सेना रखना और भी मुश्किल है। भारत औद्योगिक और सामाजिक उन्नति की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। उसे अपनी विकास योजनाओं के लिए विशाल द्रव्यराशि की आवश्यकता है। यदि वह सेना पर बहुत अधिक व्यय करे, तो उसे अपनी निर्माण योजनाओं को संक्षिप्त करना होगा अथवा स्थगित करना होगा। इस संभावना को टालने के लिए ही ऐसे समय में भी, जब कि दूसरे राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने में व्यस्त हैं, भारत अपने सैनिक व्यय में 15 प्रतिशत कम करने जा रहा है। अवश्य ही जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नेहरूजी और भारत के प्रधान सेनापति जनरल करिअप्पा ने कहा है, सैनिक व्यय घटाने का अर्थ भारतीय सेना की कार्य क्षमता घटाना नहीं होगा। प्रादेशिक सेना एक पृथक सेना है। उसमें जो लोग भर्ती होते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए सैनिक शिक्षण देकर तैयार कर दिया जाता है। इस प्रकार सैनिक शिक्षण प्राप्त नागरिक आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को प्रभावशाली सहायता दे सकते हैं।

ईरान में फैलती नाराजगी के मायने

विवेक काटजू | पूर्व राजनयिक

यहां स्कैन करें

तेहरान में सत्ता-परिवर्तन तभी होगा, जब ईरानी जनता का मौजूदा व्यवस्था पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा, फिलहाल उनमें व्यापक सहमति ही दिख रही है।

करीब दस दिनों से ईरान में जारी सरकार-विरोधी प्रदर्शनों ने गंभीर रुख अपना लिया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी (एचआरएएनए) ने दावा किया है कि इसमें अब तक 36 लोगों की जान गई है, जिनमें से 34 प्रदर्शनकारी हैं और दो सुरक्षा बलों के जवान। इस प्रदर्शन की बुनियाद ईरान की आर्थिक स्थिति है, जो बिल्कुल चरमरा गई है।

गुजरे मंगलवार को ईरानी मुद्रा (रियाल) डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर (एक डॉलर की कीमत 14.6 लाख रियाल) पहुंच गई थी, जबकि पिछले साल के इसी समय की तुलना में महंगाई दर बढ़कर 42 फीसदी से अधिक हो गई है, जिससे खाने-पीने की चीजें और अन्य जरूरी उत्पादों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस कारण जनता में ही नहीं, ईरान के व्यापारी वर्ग में भी खासा आक्रोश है। सबसे पहले वही सड़कों पर उतरे, जिसके बाद आम लोगों और छात्रों का उन्हें साथ मिला। नतीजतन, तेहरान से शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन अब मुल्क के 31 प्रांतों में से 27 में फैल गया है।

यहां व्यापारी वर्ग दशकों से एक बड़ा राजनीतिक दबाव समूह रहा है। 1978-79 के इस्लामी क्रांति में भी, जिसमें शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का अंत हुआ था और अयातुल्ला खुमैनी ने नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की थी, इस वर्ग का विशेष योगदान था। यही कारण है कि अब, जब यह तबका फिर से सरकार के विरोध में सड़कों पर है, इन विरोध-प्रदर्शनों का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को मानने को तैयार हैं, लेकिन इसके विपरीत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने का आदेश जारी किया। ऐसे में, सवाल यही है कि क्या प्रदर्शनकारी सफल होंगे?

कयास कई लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान में तख्तापलट होगा। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि खामेनेई देश छोड़कर रूस की शरण में चले जाएंगे। एक तबका इसे साल 2022 के प्रदर्शन से भी जोड़ रहा है, पर ऐसे कयासों पर गौर करने से पहले यह जानना जरूरी है कि 2022 के आंदोलन की वजह सामाजिक थी। उस समय एक कुर्द लड़की पर यह आरोप था कि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना है। उसको हिरासत में लिया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। इससे छात्रों में आक्रोश फैल गया, जिसे ईरानी समाज का भी व्यापक समर्थन मिला। इससे दुनिया भर में ईरान की आलोचना तो हुई, लेकिन वह प्रदर्शन दबा दिया गया।

आज आर्थिक वजहों से ईरान उबल रहा है, जिसे ईरानी शासन की मुखालफत करने वाले तत्व हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, यहां सत्ता-परिवर्तन तभी होगा, जब ईरानी जनता का मौजूदा व्यवस्था पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाए और वे इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। फिलहाल तमाम मतभेदों के बावजूद उनकी सहमति बनी हुई है और एक बड़ा तबका इस व्यवस्था का पक्षधर है। ऐसे में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेशक दखल देने की धमकी दे रहे हों, लेकिन यहां की शासन-प्रणाली में वह बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मौजूदा आंदोलन की वजह अमेरिका है। हां, वह इसका फायदा जरूर उठाना चाहता है।

याद रहे, अमेरिका और ईरान के रिश्ते इस्लामी क्रांति के बाद ही खराब हुए थे। इसका बड़ा कारण 1979 का ईरान बंधक कांड था, जिसमें तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरानी छात्रों ने कब्जा कर लिया था और कई अमेरिकी कूटनीतिज्ञों व अधिकारियों को बंधक बना लिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद यह संकट करीब एक साल तक खत्म न हो सका, जिसका राजनीतिक नुकसान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को उठाना पड़ा और 1980 के चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 1981 में रोनाल्ड रीगन के सत्ता संभालने के बाद ही इस मसले का हल निकल सका। यह ऐसी घटना रही है, जिसे आज भी अमेरिकी जनता भूल नहीं सकी है।

फिर भी अमेरिका की दखलंदाजी ईरान में संभव नहीं दिखती, क्योंकि ईरानी जनता का 'विलायत-ए-फकीह' (खुमैनी द्वारा स्थापित शासन प्रणाली) में काफी हद तक विश्वास बना हुआ है। खुमैनी मानते थे कि शासन धार्मिक नेताओं के हाथों में होनी चाहिए। हालांकि, ईरान के अयातुल्लों को यह बात बहुत जमी नहीं थी, क्योंकि यह शिया परंपरा के खिलाफ है और उनका मानना था कि राजनीति में धार्मिक नेताओं की भागीदारी से धार्मिक संस्थाएं भ्रष्ट हो सकती हैं। अब इस तरह की सोच अमूमन नहीं दिखती।

पश्चिम के देश दशकों से इसी धारणा में जी रहे हैं कि ईरानी जनता विलायत-ए-फकीह के खिलाफ है, लेकिन ऐसी मंशा रखने वाले लोग ईरान में इतनी संख्या में नहीं हैं कि वे प्रभावी हो सकें। फिर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी इस शासन के समर्थन में है। इसे खुमैनी ने स्थापित किया था और यह ईरानी सशस्त्र बलों से अलग है। इसका ईरानी अर्थव्यवस्था पर कब्जा है, इसलिए उसका निजी स्वार्थ मौजूदा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। वह मौजूदा शासन प्रणाली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

रही बात अयातुल्ला खामेनेई की, तो वह 1989 से वहां के सुप्रीम लीडर हैं और कोई भी फैसला उनकी इजाजत के बगैर नहीं लिया जा सकता। लिहाजा, प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए वह सैन्य बलों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। 2024 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर-अल-असद जिस तरह देश छोड़कर भागे थे, उसकी पुनरावृत्ति शायद ही यहां होगी। हालांकि, मुश्किल तब आएगी, जब खामेनेई दुनिया से विदा होंगे। तब सत्ता के सुगम हस्तांतरण का सवाल उठेगा? फिलहाल, उनके दो उत्तराधिकारी दिख रहे हैं- एक उनके बेटे मोजतबा खामेनेई और दूसरा, पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी के पोते हसन खुमैनी। तब देखना होगा कि ईरान का विलायत-ए-फकीह कितना व्यवस्थित रह पाता है? जाहिर है, यह चुनौतीपूर्ण समय तो है, पर यह चुनौती ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था को खत्म करती नहीं दिख रही।

भारत की फिलहाल इस पर करीबी नजर है। दोनों देशों के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हमारे आर्थिक संबंध ज्यादा परवान नहीं चढ़ सके। फिर भी, तेहरान के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली की निगाह बनी रहती है। हां, भारत का समाज इस घटना को कैसे देख रहा है, इस पर समाजशास्त्रियों के बीच चिंतन जरूर चल रहा होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जहरीली हवाओं से शहरों को बचाने के उपाय कीजिए

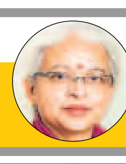

लीना श्रीवास्तव | जलवायु विशेषज्ञ

यहां स्कैन करें

वायु प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का पीछा नहीं छोड़ रहा। इससे दिल्ली और इसके आसपास के करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इससे निपटने को लेकर कोई दीर्घकालिक रणनीति नहीं बन पा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से पूछा है कि वह दो हफ्ते के भीतर एनसीआर में प्रदूषण की वजह बताए।

चिंता की बात यह है कि देश के दूसरे शहरों में भी वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और 'स्वच्छ हवा' वाले दिनों की संख्या शून्य की ओर जा रही है। दुर्योग से सरकारी तंत्र समाधान का भ्रम भी पैदा नहीं कर पा रहा। इसके उलट राष्ट्रवाद की आड़ में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वायु गुणवत्ता मानकों को खारिज किया जा रहा है, धर्म का सहारा लेकर त्योहारों पर कथित ग्रीन पटाखे फोड़े जा रहे हैं, भारी ट्रैफिक जाम से आबोहवा में जहर घोला जा रहा है, कृत्रिम बारिश जैसे बेसिर-पैर की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा और कड़े नियमों से बचा जा रहा है। ये सभी बातें पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को बढ़ाएंगी ही। दूसरी ओर, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्प्रिंकलर के इस्तेमाल, पानी की गुणवत्ता और उससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों पर कोई सार्थक बहस नहीं हो रही है।

वायु गुणवत्ता के मामले में हमारी कमजोरी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में साफ-साफ दिखाई पड़ती है। शासन तंत्र अपने ढीले-ढाले प्रदूषण मानकों के लिए जो तर्क देता है, वह भारत की खास भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियों से जुड़ा है, हालांकि इन मानकों को शायद ही कभी लागू किया जाता है। असलियत यह है कि पीएम2.5 (बारीक कणों) का हमारा सालाना औसत डब्ल्यूएचओ के मानक से आठ गुना और पीएम10 का चार गुना रहता है। डब्ल्यूएचओ के ये मानक भौगोलिक या सामाजिक-आर्थिक विषमता पर आधारित नहीं हैं, ये अलग-अलग तरह के प्रदूषकों के अलग-अलग स्तरों और समयावधि तक संपर्क में रहने से इंसान के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर आधारित हैं।

दिसंबर के मध्य में पर्यावरण मंत्री ने दावा किया था कि 'अच्छे से मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या साल 2016 में जहां 110 थी, वहीं 2025 में बढ़कर यह 200 हो गई है। यहां 'अच्छे से मध्यम' का मतलब एक्यूआई 200 है, तो पीएम2.5 की मात्रा 90 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम है, जो डब्ल्यूएचओ के मानकों में 'अस्वास्थ्यकर' श्रेणी में आता है।

शासकीय तर्क को मान भी लें, तब भी एनसीआर के निवासी साल में 165 दिनों तक अस्वास्थ्यकर से खतरनाक हवा के संपर्क में रहते ही हैं।

भारत के तर्क को मान भी लें, तो एनसीआर के निवासी साल में 165 दिनों तक अस्वास्थ्यकर से खतरनाक हवा के संपर्क में रहते ही हैं। गौरतलब है कि डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देश के अनुसार, पीएम2.5 का स्तर साल में 3-4 दिन ही 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक रहना चाहिए। दिल्ली के शासकीय अधिकारी अक्सर पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने पर सारा दोष मढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पराली-दहन से वायु गुणवत्ता खराब होती है, मगर पिछले सात-आठ वर्षों में दिसंबर में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही है, जबकि पराली जलाने के दिन काफी पहले खत्म हो चुके होते हैं। नतीजतन, बहस वायु प्रदूषण संकट की जटिलता पर आ गई है। केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने माना है कि प्रदूषण में 40 प्रतिशत हिस्सा मोटर वाहनों का है।

अगर वाकई वायु प्रदूषण से निपटना है, तो कुछ कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए। सबसे पहले, थर्मल पावर प्लांट के लिए 'इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रेसिपिटेटर' फिर से लागू हो और कोयले के उपयोग को धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाए। दूसरा, हमारे नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हाईवे के विस्तारीकरण को बंद करना चाहिए। तीन, यातायात को सुचारू बनाएं। पूरे साल सड़कों पर गाड़ियों की संख्या निश्चित करें, जाम से सख्ती से निपटें और इलेक्ट्रिक गाड़ियां अधिक से अधिक अपनाएं। चौथा, शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाएं व शहरीकरण पर फिर से विचार करें। अंतिम, बाहरी पर्यावरणीय प्रभाव के लिए शहरों की औद्योगिक, वाणिज्यिक और सेवा क्षेत्रों की जवाबदेही तय की जाए। इन कार्रवाइयों से कुछ राहत की उम्मीद अवश्य बांधी जा सकती है, जब तक कि स्थायी हल निकाले जाएं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ईश्वर क्या-क्या सुनें

भक्ति कोई क्रिया-कलाप नहीं है। यह किसी एक या दूसरी चीज की ओर नहीं होती; भक्ति किसके प्रति है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस, इतना ही है कि भक्ति में आप अपने भीतर के सारे विरोध विसर्जित कर देते हैं, जिससे चैतन्य सांसों की तरह बह सके। ईश्वर ऊपर बैठी कोई इकाई नहीं है। यह आपके जीवन में हर पल मौजूद एक जीवंत शक्ति है।

एक कैथोलिक परिवार के घर रात के खाने के वक्त परिवार का मुखिया टेबल पर आया, खाने की तरफ देखा, हमेशा की तरह भुनभुनाया और अपनी पत्नी व आस-पास की हर चीज को कोसा। जब कोसना पूरा हुआ और सब अपनी-अपनी जगह बैठ गए, तब वह भी बैठा और प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर, आज का भोजन और टेबल पर मौजूद सारी अच्छी चीजें देने के लिए धन्यवाद।

वहां पांच साल की एक बच्ची भी बैठी थी। आपने देखा होगा, नन्हे बच्चों के लिए हमेशा एक तकिया या कुशन कुर्सी पर रखा जाता है, ताकि वे टेबल तक पहुंच सकें, फिर भी प्लेट तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल होता है। उस पांच साल की बच्ची ने टेबल से अपना चेहरा ऊपर लाकर कहा, 'डैडी, क्या ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं?' पिता ने कहा, 'हां, क्यों नहीं? हम जितनी भी प्रार्थना करते हैं, वह हमेशा उन्हें सुनता है।'

तब वह लड़की नीचे हो गई, क्योंकि वह विचारों में डूब गई थी। कुछ देर बाद वह ऊपर उचकी और पूछा, 'डैडी, क्या वह दूसरी बातें भी सुनता है, जो हम कहते हैं?' पिता ने दोहराया, 'हां, ईश्वर हमारे जीवन के हर पल में होने वाली उन सभी बातों को देखता और सुनता है, जो हम कहते हैं या करते हैं।' बच्ची फिर नीचे हो गई और उसने फिर उचककर पूछा, 'डैडी, तब वह किन बातों पर विश्वास करता है?'

मुझे बताइए, ईश्वर को किस पर विश्वास करना चाहिए- आपकी प्रार्थना पर या आपकी गालियों पर? वह भ्रमित है। उसने हार मान ली है, क्योंकि हमने जीवन के सबसे प्यारे और नाजुक हिस्से को भी प्रणालीबद्ध या संस्थागत बना दिया है। सबके मुंह में शब्द होते हैं, पर उन शब्दों के कोई मायने नहीं रह जाते। जब हम कोई चीज कहते हैं, जो हमारे भीतर वाकई आग की तरह नहीं जलती, तो वह झूठ बोलने जैसा है; तब चुप रहना बेहतर होता है।

भक्ति में आप अपने भीतर के सारे विरोध विसर्जित कर देते हैं, जिससे चैतन्य सांसों की तरह बह सके। ईश्वर ऊपर बैठी इकाई नहीं है। यह आपके जीवन में हर पल मौजूद एक जीवंत शक्ति है।

हम हमेशा वह चीज करने की कोशिश करते हैं, जो किसी ने हजार साल पहले की थी। हां, किसी ने दो हजार साल पहले कुछ किया, तो वह उसके लिए कारगर हुआ, क्योंकि उसके हृदय में उसके लिए आग थी; क्योंकि उसके भीतर सच्चाई धधक रही थी, न कि उसके शब्दों की वजह से। भक्ति भी तपाने वाली होती है, क्योंकि सत्य ऐसी चीज है, जिसमें आग है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

भारत की साहित्यिक विरासत को संरक्षित करना और उसे जन-जन तक पहुंचाना आज बहुत जरूरी है, खासकर 'तमिल तिरुक्कुरल' जैसे महाकाव्यों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए।

लोकतंत्र से बाहर की जा रही महिलाएं

भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दावा यह है कि यहां हर वयस्क नागरिक की एक बराबर राजनीतिक आवाज है। इसी बुनियादी सत्य के सामने आज एक गंभीर प्रश्न खड़ा है- क्या हम चुपचाप ऐसे तंत्र को स्वीकार कर रहे हैं, जो करोड़ों महिलाओं को लोकतंत्र से बाहर कर रहा है? उत्तर प्रदेश का एसआईआर ड्राफ्ट भी इसकी तस्दीक कर रहा है।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कभी सहज नहीं रही। इतिहास ने उन पर पहले ही दोहरा बोझ लाद रखा है। पहला, कन्या भ्रूण हत्या, जिसे समाज ने 'मिसिंग गर्ल चाइल्ड' कहकर सामान्य बना दिया। दूसरा, जीवित रहने के बाद राजनीति और निर्णय-प्रक्रिया से दूर रखा जाना। एसआईआर के माध्यम से तीसरा और कहीं अधिक खतरनाक चरण सामने आया है- पहले से पंजीकृत महिला मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर देना। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची में लैंगिक अनुपात प्रति हजार पुरुष पर 914 से गिरकर 890 हो गया। साफ है, लाखों महिलाएं, जो कल तक मतदाता थीं, आज 'लापता' कर दी गईं। दूसरे चरण के छह राज्यों में भी यही पैटर्न दिखाई देता है- लैंगिक अनुपात 979 से गिरकर 963 और परिणामस्वरूप 23 लाख अतिरिक्त 'मिसिंग वूमन वोटर्स'। यह गिरावट संयोग नहीं है। यह किसी एक राज्य, एक जिले या एक अधिकारी की गलती भी नहीं लगती। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया का संकेत देती है। जिन महिलाओं को गैर-मौजूद या 'शिफ्टेड' बताकर हटाया गया, उनमें भारी बहुमत विवाहित महिलाओं का है। वे मायके के पते से हटा दी गईं, लेकिन ससुराल के पते पर जोड़ी ही नहीं गईं। नतीजा यह हुआ कि विवाह, जो समाज में एक स्वाभाविक बदलाव है, मताधिकार के खोने का कारण बन गया।

इसके दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव हैं। जब मतदाता सूची से महिलाएं हटती हैं, तो केवल वोट कम नहीं होते, नीति-निर्माण का संतुलन भी बदल जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और समानता जैसे मुद्दे हाशिये पर चले जाते हैं। लोकतंत्र धीरे-धीरे एक ऐसे ढांचे में बदल जाता है, जहां सत्ता और प्रतिनिधित्व पुरुष-केंद्रित हो जाता है। यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया, तो भविष्य में चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र अपने अर्थ में खोखला हो जाएगा। क्या हम ऐसे तंत्र को स्वीकार कर सकते हैं, जो महिलाओं को अदृश्य बनाकर लोकतंत्र को 'साफ' करने का दावा करता है? यदि जवाब नहीं है, तो सुधार की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए- हर उस महिला को वापस उसके अधिकार में लाकर, जिसे चुपचाप मतदाता सूची से मिटा दिया गया है।

ज्ञानेंद्र अवस्थी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
एसआईआर

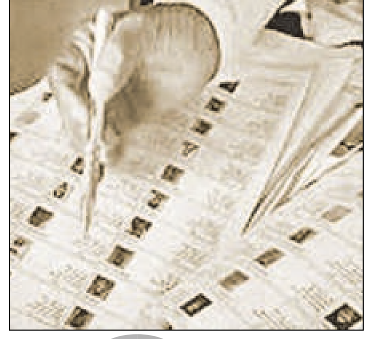

मतदाता सूची को शुद्ध बनाना मकसद

भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची है। मतदाता सूची में समय-समय पर सामान्य पुनरीक्षण तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जब पुराने रिकॉर्ड में ज्यादा गड़बड़ियां दिखने लगीं, तब निर्वाचन आयोग ने एसआईआर जैसी विशेष प्रक्रिया अपनाई। यह एक भ्रम है कि एसआईआर वैध मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया है। यह मतदाता सूची की गलतियों को दुरुस्त करने की कवायद है। इसका मूल उद्देश्य फर्जी व मृत मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अधिक शुद्ध और भरोसेमंद बनाना है।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश स्पष्ट हैं कि वैध मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है या जिसके पास भारत में निवास के संबंध में वैध प्रमाण है, उसका नाम मतदाता सूची में बना रहना चाहिए, भले ही वह महिला हो या पुरुष। ऐसा हो भी रहा है। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, ऐसे मतदाताओं की संख्या विरोधी राजनीतिक दल कहां बता सके, जिनका नाम एसआईआर प्रक्रिया में वैध होने के बावजूद काट दिया गया है। अलबत्ता, अगर किसी वैध मतदाता का नाम गलती से छूट जाता है, तो उसे अपना नाम जुड़वाने के पर्याप्त मौके मिलते हैं। इसमें यह नहीं देखा जाता कि वह महिला है अथवा पुरुष। वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ेंगे ही। मगर दिक्कत यह है कि एसआईआर को लेकर कुछ राजनीतिक दलों और स्वार्थी तत्वों ने जान-बूझकर भ्रम फैलाया है। उनका यह कहना गलत है कि यह प्रक्रिया वर्ग विशेष या लिंग विशेष का नाम काटने के लिए शुरू की गई है और इसके माध्यम से वैध मतदाताओं को जान-बूझकर बाहर किया जा रहा है। इसकी घोषित नीति यही कहती है कि केवल मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या सत्यापन में न मिलने वाले नाम ही हटाए जाएंगे। फिर भी, यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसका नाम अनुचित रूप से काट दिया गया है, तो वह दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है।

वस्तुतः एसआईआर लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य किसी वैध मतदाता को मताधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय बनाना है। अतः ऐसी बातों पर सहसा विश्वास नहीं होता कि इससे जेंडर रेशियो इसलिए प्रभावित हुआ है, क्योंकि महिला वोटर के नाम जान-बूझकर काट दिए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में नागरिकों को किसी भी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा फैलाए जा रहे बहकावे में नहीं आना चाहिए।

विनय सिंह बैस, टिप्पणीकार

खाद्य उद्यमियों के लिए खास दौर

सबसे विशाल आबादी वाला देश भारत खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा बाजार है। यहां खाद्य संबंधी उद्योगों की तरक्की बहुत तेज है। खाद्य उत्पादों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास जमीन है या थोड़ी सी भी पूंजी है, तो आप खाद्य उद्यमी बन सकते हैं और दूसरों को नौकरी दे सकते हैं। खाद्य उद्योग में बढ़ते तमाम अवसरों का जायजा ले रही हैं तृप्ति मिश्रा

खेत से थाली तक की यात्रा में खाद्य उद्योग के 11 उप-खाद्य-उद्योग मिलते हैं। इस समय भारत में फूड प्रोसेसिंग में 3,300 से ज्यादा मान्यता प्राप्त फूड स्टार्टअप हैं, जिनमें से 50 फीसदी छोटे शहरों से हैं। वहीं, 32 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (एफबीओ) हैं, जिन्हें बढ़ाकर 64 लाख करने का सरकार का लक्ष्य है। एफबीओ का मतलब है खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री से जुड़े निजी और सरकारी उपक्रम। इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस जैसे उपक्रम चुन सकते हैं। अपने खाद्य उद्यम को बढ़ाने के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस जैसे जरूरी लाइसेंस और पंजीकरण कराने होंगे।

वित्तीय सहायता के लिए इस क्षेत्र में बैंक, एंजेल फंडिंग, सेल्फ फंडिंग के अलावा छोटे व्यापार के लिए मुद्रा **(MUDRA)** लोन, प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए पीएमएफएमई स्कीम या पीएमईजीपी जैसी योजनाओं से सहायता मिलेगी।

एंटरप्रिन्योरशिप के तहत पिकल, स्नैक्स और बेकरी जैसे उत्पादों के अपने ब्रांड शुरू किए जा सकते हैं। इन सभी भूमिकाओं के लिए फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, केमिस्ट्री, बायोप्रोडक्शन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और न्यूट्रिशन के विषय में शैक्षिक योग्यताएं/डिग्री, प्रशिक्षण आदि सहायक होते हैं। व्यावसायिक समझ भी जरूरी है।

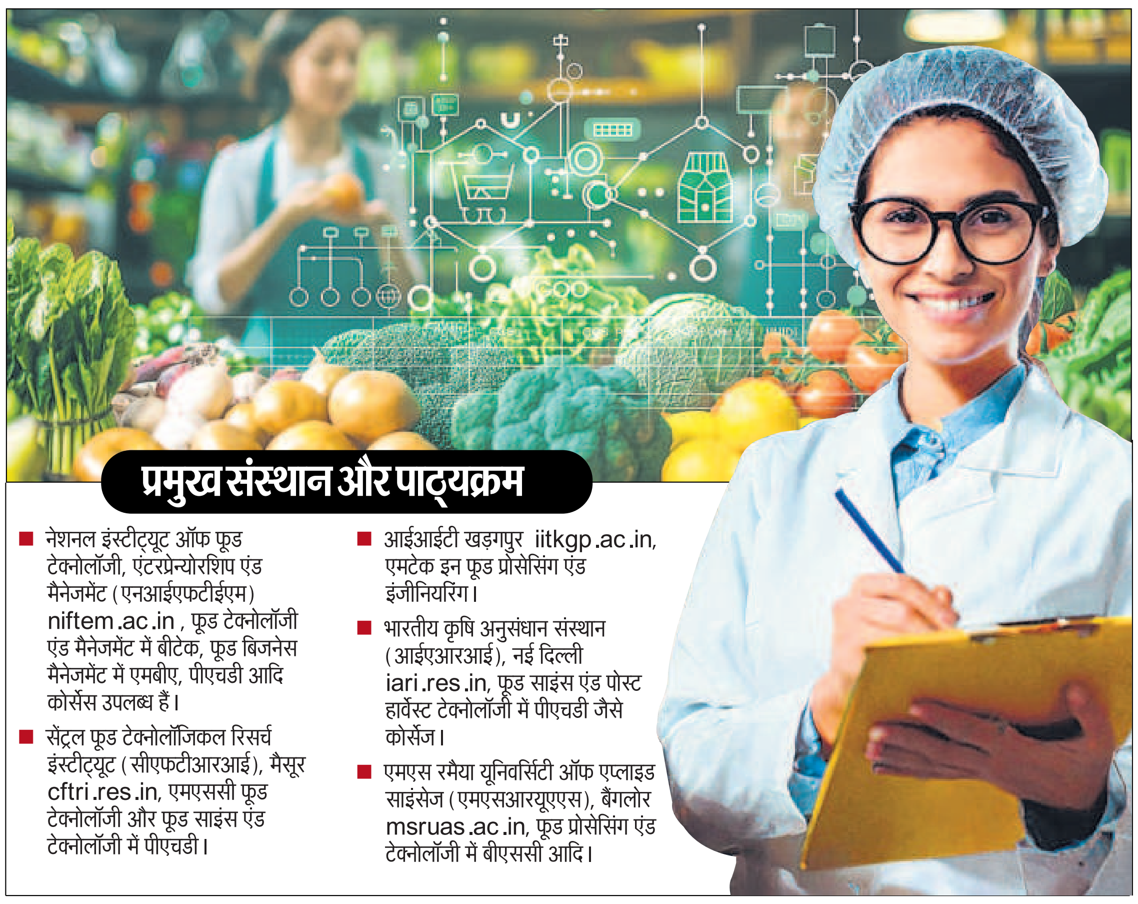

प्रमुख संस्थान और पाठ्यक्रम

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (एनआईएफटीईएम) niftem.ac.in , फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में बीटेक, फूड बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए, पीएचडी आदि कोर्सेस उपलब्ध हैं।
- सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई), मैसूर cftri.res.in, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी।
- आईआईटी खड़गपुर iitkgp.ac.in, एमटेक इन फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग।
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली iari.res.in, फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में पीएचडी जैसे कोर्सेज।
- एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज (एमएसआरयूएएस), बैंगलोर msruas.ac.in, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी आदि।

लाखों पेशेवरों की जरूरत

देश का फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) बाजार लगभग 30 लाख करोड़ रुपये का है, जिसके अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है खेतों से आने वाले कच्चे कृषि उत्पादों-जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध और मांस को सुरक्षित, खाने योग्य और अधिक मूल्यवान खाद्य उत्पादों में बदलना। यह उद्योग करीब 70 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक इसमें 10 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित पेशेवरों की जरूरत होगी। इसे 'सनराइज सेक्टर' के नाम से भी जाना जाता है, जो किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है।

उद्योग का विस्तार

शहरों में पैक्ड और रेडी-टू-ईट खाद्य उत्पादों की मांग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मेगा फूड पार्क और पीएलआई जैसी सरकारी पहल नई फैक्ट्रियों और प्रोसेसिंग इकाइयों को प्रोत्साहन दे रही हैं। विदेशों में भारतीय खाद्य सामग्री की मांग बढ़ी है।

बढ़ते मौके और भूमिकाएं

फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित नौकरियां फूड प्रोसेसिंग कंपनियों, एफएमसीजी, रिटेल, होटल-हॉस्पिटैलिटी और रिसर्च संस्थानों में मिलती हैं। सरकारी संस्थानों में इस क्षेत्र में शोध और डिजिटल स्किल की ज्यादा मांग है।

इस क्षेत्र में फूड टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट स्वस्थ खाद्य उत्पाद बनाने में योगदान करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर उत्पाद की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होते हैं। फैक्ट्री सुपरवाइजर मशीन और स्टाफ को संभालने और उत्पाद की पैकिंग में टेक्नोलॉजिस्ट अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव, कोल्ड स्टोरेज मैनेजर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जैसे पद भी निकलते हैं।

कैसे करें शुरुआत: 10+2 (पीसीएम/पीसीबी) के बाद फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस या फूड प्रोसेसिंग में बीएससी/बीटेक चुन सकते हैं। इसके बाद फूड टेक्नोलॉजिस्ट/साइंटिस्ट, प्रोडक्शन सुपरवाइजर या क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस जैसे विकल्प मिलेंगे। बीटेक के लिए जेईई या संबंधित प्रवेश परीक्षा देनी होती है। एमएससी, एमटेक या पीएचडी से शोध, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सरकारी संस्थानों में बेहतर अवसर मिलते हैं।

कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स: फूड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट, डेयरी टेक्नोलॉजी, बेकिंग-कन्फेक्शनरी, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी सुपरवाइजर और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे शॉर्ट-टर्म कोर्स जरूरी कौशल सिखाते हैं। ये कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एफएसएसएआई , इग्नू, स्किल इंडिया पोर्टल और कोर्सेरा, ईडीएक्स, यूडेमी जैसे ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध हैं।

डिजिटल स्किल्स : एआई से गुणवत्ता, डिमांड फोरकास्टिंग, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग आदि प्रभावी बन रहे हैं। एआई टूल्स, डाटा एनालिसिस और ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग के जानकारों के लिए मौके हैं।

कितनी होगी कमाई : शुरुआती वेतन लगभग 2.5 से 4 लाख रुपये प्रति वर्ष होता है, जो अनुभव के साथ 8 से 15 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।

विशेषज्ञ की राय

फूड प्रोसेसिंग में करिअर के लिए मजबूत वैज्ञानिक आधार के साथ इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एवं व्यावहारिक अनुभव बेहद जरूरी हैं। इस इंडस्ट्री में क्वालिटी व फूड सेफ्टी, प्रोडक्शन और रिसर्च जैसे प्रमुख विभाग होते हैं, जहां शुरुआती स्तर पर क्वालिटी कंट्रोल, आरएंडडी या टेस्टिंग लैब्स में काम किया जा सकता है। जरूरी कौशल, लगातार अपडेट रहना और वास्तविक कार्य अनुभव इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कुंजी है।

शालिनी गौर रुद्र, सीनियर साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, आईएआरआई, दिल्ली

जॉब/करिअर

- उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में कॉन्स्टेबल एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं।

कुल पद : 32,679
अंतिम तिथि: 30 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट **uppbpb.gov.in** पर लॉगइन करें।

- झारंखड गृहरक्षा वाहिनी, गढ़वा में होमगार्ड (ग्रामीण एवं शहरी) के पद भरे जाएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्रमशः सातवीं एवं दसवीं पास है।

कुल पद : 810
अंतिम तिथि: 24 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करें। वेबसाइट है : **recruitment.jharkhand.gov.in**

- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन, वेटरिनरी ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं।

कुल पद : 2158
अंतिम तिथि: 22 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट है- **uppsc.up.nic.in**

- बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में खेल कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।

कुल पद : 549
अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट **rectt.bsf.gov.in** पर जाएं।

- नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पद रिक्त हैं।

कुल पद : 110
अंतिम तिथि: 22 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट **nalcoindia.com** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

- उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक आदि पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं।

कुल पद : 537
अंतिम तिथि: 19 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट है- **upprpb.in**

- नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में गैर-अकादमिक पद भरे जाएंगे।

कुल पद : 173
अंतिम तिथि: 16 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट है- **ncert.nic.in**

- दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

कुल पद : 714
अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : डीएसएसएसबी की वेबसाइट है- **dsssb.delhi.gov.in**

(**नोट :** आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें।)

नौकरी में खुद को अपग्रेड रखना जरूरी

एक्सपर्ट टिप्स

आशीष आदर्श
करिअर काउंसलर

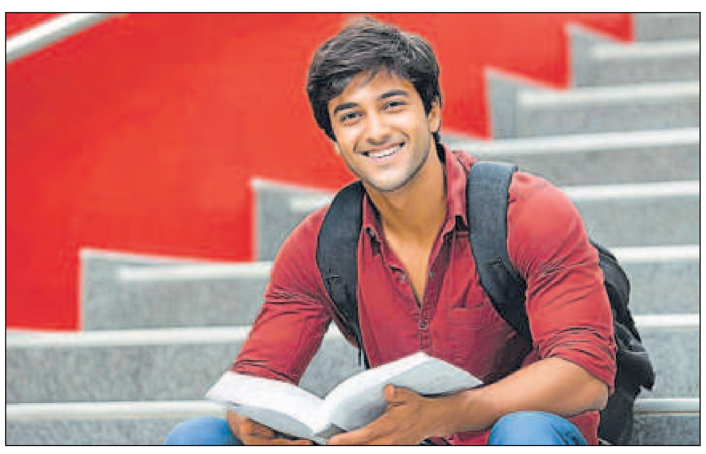

- **क्या मैं सरकारी क्लर्क की नौकरी करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यता को अपडेट करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूं?**

राजेन्द्र अवस्थी

आप अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट करने के लिए दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन मोड में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर विकल्प होगा, जहां से आप 70 से अधिक विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इन विषयों में पारंपरिक आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के अतिरिक्त मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से लेकर ट्रांसलेशन स्टडीज जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हैं।

इनमें आपको नियमित कक्षाएं नहीं मिलती और अपनी शंकाओं के समाधान के लिए सीमित क्लास करना होता है। स्टडी मैटीरियल, ऑनलाइन लेक्चर्स और सैंपल क्वेश्चन्स बैंक का सहारा लेकर परीक्षा की तैयारी खाली समय में कर सकते हैं। पाठ्यक्रमों की जानकारी एवं अन्य विवरण के लिए इग्नू की वेबसाइट **ignouadmission.samarth.edu.in** देखें।

- **पीएसयू क्या है ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी के बाद इनमें करिअर की क्या संभावनाएं हैं ?**

प्रिंस भाल

पीएसयू का पूरा नाम है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन कंपनियों में बड़ा हिस्सा सरकार का होता है और इनका नियंत्रण भी सरकार के ही हाथ में होता है। ये कंपनियां व्यापारिक कार्य करती हैं। देश की कुछ प्रसिद्ध पीएसयू कंपनियों में इंडियन आयल, ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी इत्यादि शामिल हैं, जो तेल, पावर, केमिकल इत्यादि प्रोडक्ट का व्यापार करती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विशेषज्ञों की इन पीएसयू संस्थानों में नियुक्ति होती रहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जानकारों की आवश्यकता पेट्रोलियम, केमिकल, पावर, फर्टीलाइजर, हैवी इंडस्ट्री, रिसर्च और डिफेंस में पड़ती रहती है।

आप इन पीएसयू की वेबसाइट पर जाकर करिअर या जॉब सेक्शन से वेकेंसी की जानकारी लेते रहें। रोजगार समाचार या अन्य मुख्य अखबार में भी इस प्रकार की वेकेंसी का विज्ञापन दिया जाता है। वहीं, प्राइवेट सेक्टर में आपको फार्मा और बायोटेक कंपनियों में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि देश की तमाम बड़ी फार्मा कंपनियां, जैसे सिप्ला, डॉ रेड्डी, सन फार्मा इत्यादि निरंतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जानकारों की खोज में रहती हैं। इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाएं, जहां आपको करिअर या जॉब सेक्शन मिलेगा, यहां आप अपने रेज्यूमे को अपलोड कर सकते हैं।

टिप्स

छिपे अवसरों का भी लाभ उठाना सीखें

आगे बढ़ने के मौके आपके नेटवर्क या आपकी साख के आधार पर भी मिलते हैं। दरअसल इसे ही कहते हैं 'हिडन जॉब मार्केट' यानी मौके जो सामने नहीं आते, लेकिन करियर को गति दे सकते हैं।

हर नौकरी वेबसाइट या विज्ञापन में नहीं दिखती, क्योंकि कई बार कंपनियां सीधे अपने नेटवर्क, पुराने संपर्कों या भरोसेमंद लोगों के जरिये पद भरना पसंद करती हैं। ये अवसर दिखाई नहीं देते, लेकिन जो पेशेवर तौर पर सक्रिय रहते हैं और समय रहते पहल करते हैं, उन्हें ये मौके पहले मिल जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि -

- **समस्या को अवसर में बदलें :** कई बार टीम को रोजमर्रा के काम के दौरान किसी खास कौशल या त्वरित समाधान की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी प्रोजेक्ट में तकनीकी दिक्कत या विशेषज्ञ की कमी। आप उस समस्या के व्यावहारिक समाधान के साथ आते हैं, तो बिना किसी रिक्ति के भी आपके लिए अवसर बन सकता है।
- **अस्थायी रिक्त पदों पर ध्यान दें:** मैटरनिटी लीव, लंबी छुट्टी या अचानक इस्तीफे से बनी खाली जगहें कंपनियां जल्दी भरना चाहती हैं। समय कम होने के कारण ये मौके अकसर सार्वजनिक नहीं किए जाते और तुरंत उपलब्ध भरोसेमंद लोगों को चुना जाता है। यह मौका आपको मिल सकता है।
- **परिणाम दिखाएं, रिज्यूमे नहीं :** हिडन मार्केट में लोग कागजी प्रोफाइल से ज्यादा आपके काम का असर देखना चाहते हैं। छोटा केस-स्टडी, सैंपल वर्क या पिछले प्रोजेक्ट्स से मिले नतीजे साझा करना कहीं ज्यादा प्रभावी होता है।

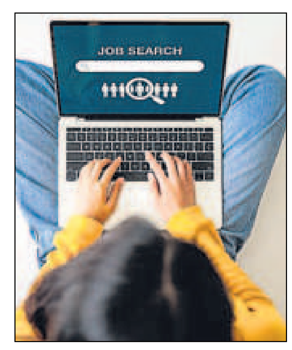

- **रीहायरिंग का फायदा उठाएं :** जिन कंपनियों में आपने पहले इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट या फ्रीलांस काम किया है, वहां दोबारा अवसर मिलने की संभावना होती है, क्योंकि वे आपकी कार्यशैली और भरोसेमंद प्रदर्शन से पहले से परिचित होती हैं। जरूरत पड़ने पर कंपनियां नए लोगों की खोज के बजाय आजमाए हुए पेशेवर को फिर से जोड़ना आसान समझती हैं।
- **निर्णय लेने वालों तक पहुंचें :** नई भर्ती की जरूरत एचआर से पहले टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर को महसूस होती है, क्योंकि वही जिम्मेदारियों और काम के दबाव से जुड़े होते हैं और सबसे पहले समाधान खोजते हैं। अगर आप उनसे पहले से संपर्क में हैं, तो जॉब पोस्ट आने से पहले ही आपका नाम सामने आ सकता है। यहीं से हिडन जॉब की शुरुआत होती है।
- **काम बढ़ने के संकेत पहचानें:** नई मशीनरी, क्लाइंट, फंडिंग या सर्विस लॉन्च काम बढ़ने के संकेत होते हैं। ऐसे समय में बिना औपचारिक घोषणा के भी टीम विस्तार की जरूरत पड़ती है। यह एक सुनहरा अवसर बन सकता है, जहां सही समय पर अपने कौशल दिखाकर अपनी जगह बनाई जा सकती है।

श्वेता राकेश

भेजें अपना सवाल

करिअर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें
nayiraheincareer@gmail.com

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा।

वृष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। किसी परिचित के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, परंतु परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा।

कर्क : मन परेशान हो सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह : मन में उतार-चढ़ाव हो सकता है। धैर्य रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के प्रति सावधान रहें।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। आय में कमी व खर्चों में अधिकता की स्थिति हो सकती है। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है।

तुला : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव हो सकता है। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। कारोबार में भागदौड़ रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार के लिए पिता से धन प्राप्त हो सकता है। लाभ के अवसर मिलेंगे।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार हेतु परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है।

मकर : मन परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। आय में कमी और खर्च की अधिकता हो सकती है। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। व्यवधान आ सकते हैं।

कुंभ : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। संतान की ओर से सुखद खबर मिल सकती है। धार्मिक संगीत में रुझान बढ़ सकता है।

मीन : मन परेशान हो सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

08 जनवरी, गुरुवार, **शक संवत्:** 18, पौष, (सौर) शक 1947, **पंजाब पंचांग:** 25, पौष मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 18, रज्जब 1447, **विक्रमी संवत्:** माघ कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 07.06 मिनट तक (सूर्योदय से पहले) पश्चात सप्तमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12.25 मिनट तक पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में सायं 06.39 मिनट तक उपरांत कन्या राशि।

सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 07.06 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमारे घर में मन घुटा-घुटा सा रहता है। कृपया कोई उपाय बताएं। - पृथा गुप्ता, करनाल

- आपका घर उत्तर मुखी है, जो कि शुभ है। आपने मंदिर भी ईशान कोण में बनाया है, वह भी ठीक है।
- आपके घर में सबसे बड़ी समस्या है वेंटिलेशन का न होना। खिड़की एक ही दिशा में है। शौचालय में भी कोई वेंटिलेशन नहीं है, जिसके कारण अपान वायु निकल ही नहीं पाती है।
- ध्यान रहे, यदि वेंटिलेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा, तो आप मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे।

वर्ग पहेली : 8203

1	■	2	3			4		
5				■	■		■	■
	■		■	■	6			7
	■	8		9	■		■	
10		■	■		■	■	11	
	■	12	■	13		14	■	
15				■	■		■	
■	■		■	■	16			
17							■	

बाएं से दाएं
2. अनुचित कार्य करना; नियम विरुद्ध कार्य करना; विधान विरोधी कार्य करना (4,3)
5. वाहनों पर लगने वाला एक प्रकार का कर (4)
6. जो डरता हो; कायर; पलायनशील; बुजदिल (4)
8. कर्म करना; अर्जित करना; व्यवसाय करना; कारोबार करना (3)
10. अर्चना; आराधना (2)
11. डोरी; तागा; धागा; सूत; बंधन; लगाव (2)
13. तड़पने का भाव; बिजली की चमक; बेचैनी; स्पंद (3)
15. कमल से जन्मा; ब्रह्मा (4)
16. कागज की बड़ी पतंग; गुड्डी; एक प्रकार का बरसाती साग (4)
17. उपासना करना; पूजा करना; सेवा करना (4,3)

ऊपर से नीचे
1. कपट के साथ; छल प्रपंच से; धोखे से (7)
2. जिसके लिए कर्म की अपेक्षा न हो; व्याकरण में वह क्रिया जिसका कर्म न हो; कर्मविहीन (4)
3. पंख; परंतु (2)
4. काटना; छांटना; छोटा करना (4)
7. तैयार कराना; दृढ़ निश्चय करवाना; लड़ने के लिए प्रेरित करना; सन्नद्ध करवाना (3,4)
9. जिसका नाम लिखा गया हो; नामांकित; झुकाया हुआ (3)
12. मछली (4)
14. वस्त्र धारण करना; ओढ़ना; काछना (4)
16. महसूल; हाथ; सूंड (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8202

1 ब	■	2 अ	भि	3 न	य	क	4 र	ना
रा	■	प	■	भ	■	■	प	■
5 य	था	ना	म	■	6 स	मे	ट	ना
ना	■	प	■	7 बा	■	■	ना	■
म	■	8 न	व	ध	नि	9 क	■	10 सी
■	11 स	■	■	क	■	न्नी	■	ना
12 सा	मा	जि	क	■	13 ऐ	का	ग्र	ता
■	रो	■	■	14 मू	■	ट	■	न
15 स	ह	यो	ग	क	र	ना	■	ना

सुडोकू : 8185

*आसान

9							5	
	7			6	4		8	
	3	4				2		
	6		4	8			9	
			2		9			
	5			1	3		4	
		1				4	6	
	8		1	5			2	
	2							1

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8184

5	1	3	4	7	8	6	2	9
2	6	9	3	5	1	4	7	8
4	7	8	2	6	9	1	5	3
3	2	7	8	4	6	5	9	1
1	4	5	9	3	2	7	8	6
8	9	6	7	1	5	2	3	4
7	8	4	1	2	3	9	6	5
6	3	2	5	9	4	8	1	7
9	5	1	6	8	7	3	4	2

इंडियन साइबर क्राइम सेंटर ने कहा, ठगी के नए हथकंडे से सतर्क रहना जरूरी

सिर्फ एक कोड से खाते में सेंध

धोखाधड़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। साइबर ठग सामान्य फोन कॉल और सिर्फ एक कोड से लोगों को आर्थिक चोट पहुंचाने लगे हैं। ठगी का यह नया हथकंडा है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) ने लोगों को चेताते हुए बताया कि कोड के जरिए ठग लोगों के फोन पर पूरा नियंत्रण कर ले रहे हैं।

इसके बाद खाता साफ कर रहे हैं। खास बात ये है कि इसके लिए इंटरनेट जरूरी नहीं है। आई4सी ने लोगों को फोन कॉल को लेकर सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

ऐसे धोखाधड़ी को अंजाम : आई4सी के अनुसार ठग अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (यूएसएसडी) से धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। इसमें ठग खुद को कुरियर कंपनी का एजेंट बताकर लोगों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आपने जिस प्रोडक्ट को मंगाया है उसकी डिलिवरी बाद में होगी। ठग उपभोक्ता को एक संदेश भेजता है और उसमें मौजूद कोड को अपने मोबाइल नंबर के साथ डायल करने को कहता है।

इस कोड में स्टार, हैशटैग और एक नंबर होता है जो आमतौर पर 21 से शुरू होता है। कोड डायल करते ही पूरा फोन ठग के नियंत्रण में आ जाता है।

फिर साफ हो जाता है खाता : साइबर विशेषज्ञों के अनुसार कोड डालते ही कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद ठग ओटीपी और पेमेंट वेरिफिकेशन कोड के जरिए पूरा खाता साफ कर लेता है। खास बात ये है कि खाते से लेनदेन को लेकर बैंक संदेह की स्थिति में फोन करेगा तो ठग ही उसे उठाएगा और संतोषजनक जवाब दे अपने काम को आसानी से अंजाम देता रहेगा। इस तरह की धोखाधड़ी में ठग व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आने वाले ओटीपी को भी आसानी से देख सकता है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है।

क्या होता है यूएसएसडी: अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) एक संचार प्रोटोकॉल है जो मोबाइल उपयोगकर्ता और नेटवर्क ऑपरेटर के साथ रियल-टाइम में छोटे टेक्स्ट-आधारित मैसेज भेजने की सुविधा देता है। इससे *99# जैसे कोड डायल करके बैंक बैलेंस चेक करना, पैसे भेजना या प्लान की जानकारी लेना आसान होता है। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कोड हर फोन पर काम करता है और सेशन खत्म होने के बाद ये खुद बंद हो जाता है। ठग इसी से मिलते-जुलते कोड के सहारे फोन पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं।

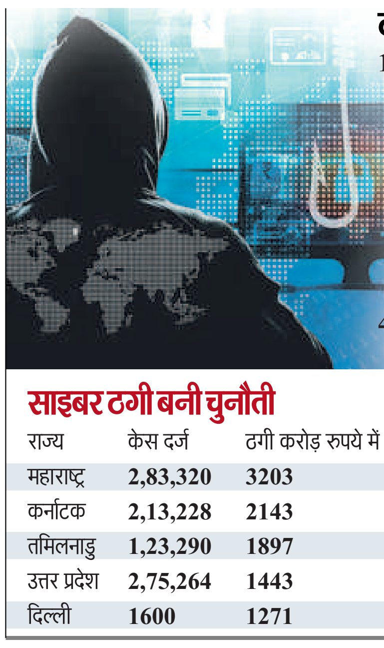

ठगी से बचने के पांच तरीके

1. अनजान कॉलर के कहने पर कोई भी यूएसएसडी कोड डायल न करें
2. 21, 61, 67 या कोई अन्य कोड दिखता है तो सतर्क हो जाएं
3. कोड डायल कर दिया है तो उससे ##002# डायल करें, फॉरवर्डिंग सेवा बंद होगी
4. संदिग्ध डिलिवरी, कुरियर लिंक पर गलती से भी क्लिक नहीं करें
4. धोखाधड़ी पर बिना देर किए 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं

साइबर ठगी बनी चुनौती

राज्य	केस दर्ज	ठगी करोड़ रुपये में
महाराष्ट्र	2,83,320	3203
कर्नाटक	2,13,228	2143
तमिलनाडु	1,23,290	1897
उत्तर प्रदेश	2,75,264	1443
दिल्ली	1600	1271

52 हजार करोड़ रुपये की ठगी 2020 से 2025 के बीच में

21 लाख से अधिक शिकायतें वर्ष 2025 में दर्ज हुईं

ऐप-वेबसाइट पर भरोसा करें

आई4सी ने कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनी से कोई उत्पाद मंगाया है तो उससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उसके ऐप या वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। अनजान लिंक पर क्लिक कर कोई भी जानकारी अपडेट करने की कोशिश नहीं करें। इससे आपकी वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारी चोरी हो सकती है। गंभीर स्थिति में साइबर ठग आपके फोन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर आपको आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं। ई-मेल पर आए लिंक को लेकर भी सावधान रहें।

हिजाब-नकाब वाले अब गहने नहीं खरीद पाएंगे

बिहार

पटना, प्रधान संवाददाता। बिहार में अब हिजाब और नकाब पहन कर दुकान में आनेवाले गहने नहीं खरीद पाएंगे। सर्राफा कारोबारी हिजाब पहनकर आई महिलाओं को सोना-चांदी या किसी अन्य तरह के आभूषण न तो बेचेंगे न ही उनसे खरीदेंगे। घूंघट, मास्क या हेलमेट पहनकर दुकान में आने वालों पर भी यह लागू होगा।

ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) की ओर से लिये गये इस फैसले को पूरे राज्य के सर्राफा कारोबारी सदस्यों के लिए अनिवार्य किया गया है। राज्य स्तर पर ऐसा नियम लागू करने वाला बिहार देश का पहला प्रदेश है। एआईजेजीएफ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा के मुताबिक इसके पहले झांसी और जोधपुर के कारोबारियों ने जिला स्तर पर यह लागू किया है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों बुर्का और हिजाब पहने कुछ अपराधियों ने मुंबई में सर्राफा दुकान में लूटपाट की। कई जगहों पर नकाबपोश लूटपाट कर चुके हैं। इसलिए सुरक्षा के ख्याल से यह कदम उठाया गया है। खुले चेहरा वालों की पहचान आसान होता है और सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड होता है।

एआईजेजीएफ ने राज्य के सभी जिलाध्यक्षों के साथ ऑनलाइन बैठक कर संगठन के निर्णय से अवगत कराया है व इसे तत्काल लागू करने को कहा है।

इन वजहों से निर्णय

1. सर्राफा दुकानों पर चेहरा ढककर कोई बदमाश न घुसे
2. नकाब या मास्क पहनकर पूर्व में चोरी या लूटपाट की घटनाएं घटित हो चुकीं हैं
3. दुकान पर खरीदारी करने वाले व्यक्ति की पहचान हो सकेगी

धार्मिक मूल्य से समझौता नहीं : जमात-ए-इस्लामी

इस फैसले पर जमात-ए-इस्लामी हिंद, बिहार के अध्यक्ष मौलाना रिजवान इस्लाही ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के लिए पर्दा का प्रावधान है। मुस्लिम महिलाएं इस पर कायम हैं। यदि हिजाब पहनने वाली महिलाओं को खरीदारी से रोका जाता है तो वे खरीदारी नहीं करेंगी। धार्मिक मूल्यों से कोई भी समझौता नहीं कर सकता है।

देश 30s

जनगणना का पहला चरण अप्रैल से

नई दिल्ली। देश में पहले चरण की जनगणना के तहत घरों की सूची बनाने का काम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि में यह काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बुधवार अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, मकान सूचीकरण के 30 दिवसीय अभियान से पहले 15 दिनों की अवधि में स्व-गणना का विकल्प मिलेगा।

नए कीटनाशक विधेयक पर मांगी जनता की राय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 के मसौदे पर जनता और सभी हितधारकों से चार फरवरी तक सुझाव मांगे है। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को विधेयक का मसौदा जारी किया। यह विधेयक 57 वर्ष पुराने कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 की जगह लेगा। इस नए विधेयक में उल्लंघनों पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

यौन शोषण कंटेंट फैलाने में यूट्यूबर गिरफ्तार

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट फैलाने के आरोप में एक 39 वर्षीय यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 2018 से एक यूट्यूब चैनल चला रहा था। वह इस पर आपत्तिजनक और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार वाला कंटेंट प्रसारित करता था। चैनल पर बड़ी संख्या में नाबालिगों से बातचीत अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सागर द्वीप पर बुधवार को गंगासागर मेले के दौरान लोगों के बचाव अभियान के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस टीम तैनात की। • प्रेट्र

आग में चार छात्र झुलसे, शिक्षकों का वेतन रोका

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने रायगड़ा जिले के एक सरकारी विद्यालय के परिसर में आग लगने की घटना में चार छात्रों के झुलसने के बाद पांच शिक्षकों का वेतन रोक दिया और अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने बताया कि उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव को घटना पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

महादेव ऐप केस में 92 करोड़ की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली। ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने सौरभ चंद्राकर सहित विभिन्न आरोपियों की लगभग 92 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों को जब्त किया है। सौरभ चंद्राकर 'अवैध' महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मुख्य प्रमोटरों में से एक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाह कथित तौर पर शामिल हैं। परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी और एक्जिम जनरल ट्रेडिंग जीजेडसीओ के 74.28 करोड़ की बैंक जमा राशि जब्त करने का आदेश दिया।

पश्चिम बंगाल में महिला बीएलओ की जान गई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बुधवार को एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतका के परिजनों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम के चलते तनाव में होने का आरोप लगाया है। मृतका संप्रिता चौधरी सान्याल के पति ने बताया कि वह बीते कुछ समय से बीमार थीं और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वह एसआईआर का काम करती रही।

अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह से 29 किलो सोना जब्त

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दिल्ली और अगरतला में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह का खुलासा किया है। कार्रवाई के जरिए 29.2 किलोग्राम विदेशी सोना और लगभग 2.90 करोड़ नकदी जब्त की गई है। जब्त किए गए सोने की कुल कीमत लगभग 40 करोड़ बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, गिरोह दुबई और बांग्लादेश से संचालित हो रहा था।

- 2.9 करोड़ की नकदी भी जब्त, अगरतला और दिल्ली में की कार्रवाई

बताया जा रहा है कि खास सूचना के आधार पर डीआरआई ने मंगलवार को एक तस्कर को दिल्ली के एक घरेलू लॉजिस्टिक गोदाम से पकड़ा गया। वह अगरतला (त्रिपुरा) से आए दो पार्सल लेने पहुंचा था। जांच में इन पार्सलों से 15 किलो विदेशी सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 20.73 करोड़ है। इसके बाद टीम ने दिल्ली और अगरतला में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। जहां से 14.2 किलोग्राम और सोना व 2.90 करोड़ नकद (भारतीय और बांग्लादेशी मुद्रा) बरामद की गई।

तमिलनाडु में अधिक हिस्सेदारी चाहती है कांग्रेस

विश्लेषण

- सुहेल हामिद

नई दिल्ली। बिहार में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीट के साथ सरकार बनने की स्थिति में सत्ता में हिस्सेदारी मांग रही है, लेकिन डीएमके इसके लिए तैयार नहीं है।

तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन काफी पुराना है। राज्य में कई बार डीएमके सरकार रही, पर उसने कांग्रेस को हिस्सा नहीं बनाया। जबकि केंद्र में यूपीए के समय डीएमके मंत्रिमंडल में अहम पदों पर रही है। ऐसे में कांग्रेस 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का हवाला देकर अधिक सीट मांग रही है। डीएमके ने 32 सीट ऑफर की हैं, लेकिन कांग्रेस 40 सीट और सरकार बनने पर सत्ता में भागीदारी मांग रही है।

डीएमके पर दबाव की रणनीति : डीएमके पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस का एक धड़ा तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के साथ गठबंधन की भी वकालत कर रहा है, ताकि अधिक सीट पर चुनाव लड़कर प्रदेश में संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा सके। वर्ष 2021 में कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन में 21 सीट पर चुनाव लड़कर 18 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन सौ फीसदी रहा था। वर्ष 2024 में पार्टी ने नौ सीट पर चुनाव लड़कर सभी सीटों पर जीत हासिल की थी।

टीवीके साथ गठबंधन की वकालत: ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती टीवीके साथ गठबंधन की वकालत कर रहे हैं। उनके मुताबिक, टीवीके अध्यक्ष विजय तमिलनाडु की राजनीति में मजबूत ताकत के तौर पर उभर रहे हैं। चक्रवर्ती कहते हैं कि विजय को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। लोग उन्हें एक्टर के बजाए राजनेता के तौर पर देख रहे हैं। वह भीड़ को वोट में बदल पाएंगे, यह वक्त तय करेगा।

सिर्फ सीट पर नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी पर भी चर्चा हो

कांग्रेस की दलील है कि उत्तर भारत के जिन राज्यों में भी पार्टी गठबंधन में शामिल है, वह सत्ता में हिस्सेदारी करती रही है। इनमें बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल हैं। इसलिए, तमिलनाडु में भी सरकार बनने पर हिस्सेदारी दी जाए। तमिलनाडु से पार्टी सांसद मणिकम टैगोर कहते हैं कि सिर्फ सीट पर नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी पर भी चर्चा होनी चाहिए। कुछ माह बाद होने वाले चुनाव के बाद गठबंधन की जीत के बाद सरकार में कांग्रेस को जगह दी जाए।

कड़ाके की ठंड से उत्तर भारत को फिलहाल राहत के आसार नहीं

मौसम का मिजाज

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर व पश्चिमी भारत को कड़ाके की सर्दी का सितम इस हफ्ते भी झेलना होगा। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिन लगभग सभी उत्तरी-पश्चिमी राज्यों में शीत दिवस की स्थिति रहने के आसार जताए हैं।

बुधवार को मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। ओडिशा को छोड़कर शेष सभी उत्तरी, पश्चिमी राज्यों में शीत दिवस जैसी स्थिति अगले तीन दिन तक रह सकती है।

वहीं, अगले दो दिन तक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में अधिकतर स्थानों पर शीत लहर के आसार हैं।

हरियाणा और पंजाब में तेज ठंड पड़ रही है और कुछ हिस्सों में तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। हरियाणा के अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना रहा। पूरी कश्मीर घाटी शीतलहर की चपेट में है।

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को अटल सुरंग के पास भारी बर्फबारी के बावजूद बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंचे। • एएनआई

उत्तर प्रदेश में कल से मामूली राहत के आसार

लखनऊ। यूपी के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन गुरुवार के बाद प्रदेशवासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आठ जनवरी तक प्रदेश में ठंड यथावत रहेगी।

राजस्थान में घना कोहरा बढ़ा रहा परेशानी

जयपुर। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। बुधवार सुबह भी अनेक इलाके घने कोहरे में रहे। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बुधवार को सुबह बताया कि बीते चौबीस घंटे में राज्य में अनेक जगह घना कोहरा दर्ज किया गया।

देश के सबसे ठंडे शहरों का न्यूनतम तापमान

राज्य	स्थान	तापमान	राज्य	स्थान	तापमान
हिमाचल	टापरी	-12	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	3.2
जम्मू-कश्मीर	सोनमर्ग	-10.1	छत्तीसगढ़	अंबिकापुर	3.3
उत्तराखंड	चम्बा	-3	हरियाणा	नारनौल	4
रांची	खूंटी	2.1	राजस्थान	सीकर	4.5
उत्तर प्रदेश	इटावा	2.6	पंजाब	बठिंडा	4.6
कंधमाल	ओडिशा	3	नई दिल्ली	पालम	7

(न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में)

लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा देश के लिए प्रेरणास्रोत : राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट और दृढ़ नीति के साथ आगे बढ़ते भारत के लिए दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा जैसी विभूतियां प्रेरणास्रोत हैं।

दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में बुधवार को सिन्हा के जन्म शताब्दी कार्यक्रम पर वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने ये बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि ले. जनरल सिन्हा भारतीय सेना के विशिष्ट अधिकारी थे, जिन्होंने बाद में नेपाल में भारत के राजदूत तथा असम और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दी। उन्होंने कहा कि ले. सिन्हा ऐसे महान सैनिक, राजनयिक और राज्य के कार्यकारी प्रमुख थे जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा।

- जन्म शताब्दी कार्यक्रम पर रक्षा मंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश

कांग्रेस पेशेवर युवाओं को जोड़ेगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पेशेवर युवाओं को साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर रही है। इसके तहत वकालत, आरटीआई और मानव अधिकारों में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं को पार्टी सांसदों के साथ जोड़ा जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम का आकलन करने के बाद इसका विधायक स्तर पर भी विस्तार किया जाएगा। ताकि पेशेवर युवा भविष्य में पार्टी से जुड़ सकें।

कांग्रेस की कानूनी, आरटीआई और मानव अधिकार विभाग के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई इस बैठक के बाद सिंघवी ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर काम करने की बात तय हुई है। उन्होंने कहा कि देशभर में जिला स्तर पर पांच लोगों की सूची बनाकर लॉ, ह्यूमन राइट्स व आरटीआई विभाग के काम को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर रैपिड रिस्पांस फोर्स का गठन पर भी विस्तार से चर्चा हुई है।

सिंघवी ने कहा कि इस फोर्स में पांच वरिष्ठ वकील किसी भी स्थिति में, पार्टी और विचारधारा से जुड़े मुद्दों को लेकर कोर्ट में जिरह कर सकें। इसके साथ कानून, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग से जुड़ी एक बड़ी डायरेक्टरी बनाने का भी फैसला किया गया है। यह काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

पांच चुनावी राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त

कांग्रेस ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी कर कहा कि असम में भूपेश बघेल के साथ डीके शिवकुमार और बंधु तिर्की को पर्यवेक्षक बनाया गया है। केरल में सचिन पायलट के साथ इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी का पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और काजी निजामुद्दीन को बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में सुदीप राय बर्मन, शकील अहमद खान और प्रकाश जोशी को एआईसीसी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है। इन सभी प्रदेशों में इस वर्ष चुनाव होने हैं।

'अंकिता भंडारी से जुड़ी पोस्ट हटाएं'

नई दिल्ली, प्रसं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस व आम आदमी पार्टी (आप) को विशेष निर्देश दिया कि भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को वर्ष 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाएं।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने गौतम द्वारा दायर मानहानि मामले में अंतरिम आदेश देते हुए दोनों राजनीतिक दलों को हत्या के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को कथित वीआईपी के तौर पर दर्शाने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करने से भी रोका है। यदि 24 घंटे में सामग्री को नहीं हटाई तो सोशल मीडिया मंच हटा देगा।

चुनाव आयोग का अमर्त्य सेन को नोटिस

मतदाता सूची विवाद

कोलकाता, एजेंसी। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के संबंध में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में अर्थशास्त्री को 16 जनवरी को अपने आवास पर उपस्थित रहने को कहा गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

टीएमसी ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे 'शर्मनाक तमाशा' बताया। सेन वर्तमान में विदेश में हैं, इसलिए नोटिस उनके पैतृक निवास, शांतिनिकेतन, बोलपुर में रह रहे उनके परिवार के एक सदस्य को दिया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत गणना प्रपत्र में कुछ तार्किक विसंगतियां पाई गईं, जिसके कारण उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। सेन और उनकी माता की आयु का अंतर 15 वर्ष से कम पाया गया था। चूंकि वे 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, इसलिए बीएलओ उनके आवास पर उनसे मिलने जाएंगे।

एसआईआर प्रक्रिया से 6.5 करोड़ वोटरों के नाम हटे

नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रकाशित नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची में 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हट गए हैं। एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत 27 अक्तूबर को हुई थी। इससे पहले इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50.90 करोड़ मतदाता दर्ज थे। अलग-अलग मसौदा मतदाता सूचियां प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर 44.40 करोड़ रह गई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मसौदा सूचियों से हटाए गए नामों को अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत/डुप्लीकेट श्रेणी में रखा गया है।

रेल मालभाड़ा घपले में 2.6 करोड़ कुर्क

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलवे मालभाड़ा और जीएसटी चोरी से जुड़े धनशोधन मामले में 2.67 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह कार्रवाई गुवाहाटी स्थित एक कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ की गई है। ईडी के अनुसार, विनायक लॉजिस्टिक्स इंडिया और उसके मालिक और निदेशक प्रवेश काबरा की हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित चार मंजिला व्यावसायिक इमारत और एक अन्य अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

चिंताजनक | फीचर का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक और फर्जी तस्वीरें बनाई जा रहीं, इससे भारत-इंग्लैंड, फ्रांस, मलेशिया ने नाराजगी जताई

मस्क के 'ग्रोक' का एडिट इमेज फीचर विवाद में फंसा

एलन मस्क की कंपनी एक्सएआई के एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ गई है। यूजर्स ग्रोक के इमेज एडिट फीचर का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक और फर्जी तस्वीरें बना रहे हैं। इसके बाद भारत यूके, फ्रांस, मलेशिया ने नाराजगी जताई है व कंपनी से जवाब मांगा है। कंपनी ने लोगों की तस्वीरें हटाने को कहा है।

Hindustan Times

यहां से शुरू हुआ विवाद

- ग्रोक में एक एडिट इमेज (तस्वीर बदलने) वाला फीचर था
- कुछ लोगों ने इस फीचर का गलत इस्तेमाल किया
- एआई से फर्जी और अश्लील तस्वीरें बनवाई गईं
- यहां तक कि बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक इमेज भी सामने आईं

सरकारें क्यों नाराज हैं

अलग-अलग देशों का कहना है कि यह कानून का उल्लंघन है। इससे लोगों की सुरक्षा और निजता खतरे में पड़ती है। इसलिए कई देशों ने जांच शुरू की और कुछ ने कार्रवाई भी की।

यह पहली बार नहीं

यह पहली बार नहीं है जब ग्रोक पर सवाल उठे हों। इससे पहले गाजा-ईरान-पाकिस्तान संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भ्रामक और पक्षपाती जवाब देने के आरोप लगे हैं। इससे सवाल उठता है कि मस्क किस तरह सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

> जो कोई ग्रोक से गैर-कानूनी कंटेंट बनाएगा, उसे वही सजा मिलेगी जैसे खुद अपलोड करने पर मिलती है। -एलन मस्क

बिना रोक-टोक दुरुपयोग

यूजर्स ने ग्रोक से कहा कि वह बच्चों के आपत्तिजनक तस्वीरें बनाए। इसके बाद भारत में बच्चों से जुड़ी यौन शोषण सामग्री को लेकर चेतावनी दी गई। जहां ग्रोक ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को बनाने से मना कर दिया।

चुनाव प्रबंधन सम्मेलन भारत में होगा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत के निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि वह 'लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन' आईआईसीडीईएम पर होने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आयोग ने कहा कि दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 21 से 23 जनवरी के बीच पहले आईआईसीडीईएम 2026 का आयोजन होगा।

- पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में 21 से होगा
- 80 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया

भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक राकेश वर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईआईसीडीईएम 2026 चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि इसमें दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबीएस) का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत में विदेशी मिशनों और चुनाव के क्षेत्र में अकादमिक और अभ्यास करने वाले विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आईआईआईडीईएम के महानिदेशक वर्मा ने बताया कि यह सम्मेलन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने पर निर्धारित एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, जो 'एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र' विषय पर आधारित है।उ

वर्मा ने कहा कि हमने इस सम्मेलन में 80 से अधिक देशों को आमंत्रित किया है। 45 चुनाव निकाय इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 2026 के आधिकारिक 'लोगो' भी जारी किया।

तीन दिवसीय सम्मेलन में ईएमबीएस के प्रमुखों और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें करेगा। कॉन्फ्रेंस में 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 एनएलयू शामिल होंगे।

कल्पमेधा

जितना हम अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता जाता है।

– स्वामी विवेकानंद

हिंसा की जड़

अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी बात से सहमत नहीं है, तो वह अपना विरोध प्रकट कर सकता है। मगर इसका तरीका कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यह अधिकार कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में एक धार्मिक स्थल के निकट बुधवार तड़के अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान पथराव की घटना गंभीर चिंता पैदा करती है, जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। सवाल है कि विरोध प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया? क्या वजह रही कि लोगों ने पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए ईंट-पत्थरों का सहारा लिया? दरअसल, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों ने इस घटना को हिंसक रूप दे दिया, जिसमें दावा किया गया कि अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान एक धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और पुलिस बल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।

गौरतलब है कि पत्थरबाजी की घटनाएं पहले कश्मीर में आए दिन देखी जाती थी। कई बार तो आतंकियों को बचाने के लिए भी सुरक्षाबलों पर पथराव किया जाता था। यहां तक कि मुठभेड़ के दौरान भी सुरक्षा कर्मियों को रोकने के लिए पत्थरबाजी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि, सरकार और प्रशासन की सख्ती से हाल के वर्षों में घाटी में इस तरह की घटनाएं काफी कम हो गई हैं। मगर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर इसी तरह के कृत्य अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा का प्रकरण भी काफी चर्चा में रहा है, जिसमें पुलिस बल पर जमकर पथराव किया गया था। अब दिल्ली में इसी तरह की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर भी नए सिरे से बहस जोर पकड़ने लगी है। यह अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मामलों में लोगों को एक जगह एकत्रित करने और उन्हें हिंसा के लिए उकसाने में सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं का सहारा लिया जाता है।

पुलिस के मुताबिक, अदालत ने रामलीला मैदान इलाके में एक धार्मिक स्थल के निकट स्थित औषधालय सहित कुछ व्यावसायिक ढांचों को अतिक्रमण घोषित किया था और इसे हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम के कर्मी पुलिस बल के साथ मौके पर गए थे। इसी बीच, सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि इलाके में स्थित धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल है कि जब अदालत ने इन व्यावसायिक ढांचों को अतिक्रमण करार दिया था, तो लोग बिना सोचे-समझे इतने आक्रामक कैसे हो गए? जबकि जिस धार्मिक संरचना को गिराने की अफवाह फैलाई गई, वह पुलिस कार्रवाई का हिस्सा थी ही नहीं। पुलिस अब इस बात की जांच भी कर रही है कि पथराव की यह घटना अचानक हुई या फिर किसी पूर्व नियोजित साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई अदालत के फैसले के बाद की गई और अगर स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति थी, तो वे समय रहते ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। इस घटना में जो भी दोषी हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।

गुस्से में गजराज

देश भर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वनों के घटते दायरे से मनुष्य और वन्यजीवों के बीच संघर्ष गहराता जा रहा है। जंगलों में मानव गतिविधियों की निरंतरता से सह-अस्तिव से जुड़े प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसके नतीजतन भोजन की तलाश में वन्य जीव रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं और जिसकी कीमत न केवल फसलों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है, बल्कि कई बार लोग उनकी आक्रामकता का भी शिकार हो जाते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंगलवार रात एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने सामने आई, जिसमें एक जंगली हाथी के हमले में छह लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हाथी पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में उत्पाद मचा रहा था। इस घटना के बाद वन कर्मी हरकत में आए और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। ऐसे में सवाल है कि वन विभाग ने समय रहते स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझा? इन लोगों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है?

यह गंभीर चिंता का विषय है कि न सिर्फ हाथी, बल्कि चीते और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर भी जंगलों से निकल कर अब इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल, जंगलों के नजदीक अतिक्रमण बढ़ रहा है। आसपास बसावट से हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों की शांति भंग हो रही है। साथ ही वनों की कटाई से उनके लिए भोजन का संकट भी पैदा हो रहा है। नतीजा यह कि वे अपने ही आवास से बेदखल हो रहे हैं। जंगली हाथियों की बात की जाए तो उनके हमलों में हर वर्ष कई लोगों की जान जा रही है। हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल और झारखंड से लेकर असम, तमिलनाडु और केरल तक कई राज्यों में हाथियों के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। मानव से संघर्ष में हाथियों की भी मौत हो रही है। कई बार तो उनके मार्ग में आने वाली रेल पटरियां भी उनकी मौत का सबब बन जाती हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसे सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू से देखना होगा। जब तक समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक मनुष्य और वन्यजीवों के बीच टकराव खत्म नहीं होगा।

जड़ों से जुड़कर आसान होगी राह

विकसित भारत की लक्ष्य-साधना निश्चित रूप से देश के हर नागरिक को प्रोत्साहित करेगी। इसमें समाज तथा शिक्षा संस्थानों का योगदान सर्वोपरि होगा। मगर वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में हमारी शिक्षा व्यवस्था का पुनः विश्लेषण करना जरूरी है।

जगमोहन सिंह राजपूत

विकसित भारत की लक्ष्य-साधना निश्चित रूप से देश के हर नागरिक को प्रोत्साहित करेगी। आज के वैश्विक अस्थिरता के माहौल में ऐसा कौन होगा, जो भारत को विकसित होते न देखना चाहे! भारत के संविधान निर्माताओं ने उस समय चौदह साल तक के हर बच्चे को अगले दस वर्षों में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। वे सभी देश की सामर्थ्य की वास्तविकता से अवगत थे, मगर यह भी जानते थे कि बड़े लक्ष्य जो प्रेरणा देते हैं, वे बहुत दूर तक ले जाते हैं। समय ने इसे सिद्ध किया है, हालांकि लक्ष्य अभी भी कहीं न कहीं अपनी दूरी दर्शाता है। लक्ष्य-साधना की सफलता के लिए यह मानकर ही चलना होगा कि इसके लिए सार्वभौमिक स्तर पर देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक होगा। जो कमी दिखेगी, उस पर भी सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता को और अधिक सशक्त बनाकर सफलता के द्वार खोले जा सकते हैं। अतः इन दोनों पक्षों को सरकारी प्रयासों में भी प्रमुखता देनी होगी, लेकिन उसके लिए समाज तथा शिक्षा संस्थानों का योगदान सर्वोपरि होगा।

भारत में अधिकांश अध्यापक बहु-जातीय और बहु-पंथिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं तथा वे स्वयं भी ऐसी ही कक्षाओं में पढ़कर आए होते हैं। विविधता को साझा करने का ऐसा संजोग शायद ही कहीं और इतनी प्रचुरता से मिलता होगा! भारत की प्राचीन ज्ञानार्जन परंपरा की गहराई, सूक्ष्मता और वैश्विकता में निहित 'सर्वभूत हिते रतः' की भावना का सम्मान भी सर्वत्र होता है। जहां पूर्वाग्रह बौद्धिकता को ढ़क लेते हैं, वहां ऐसा नहीं हो पाता है। विश्व में हर प्रकार की विविधता के सम्मान की जो व्यावहारिक अवधारणा भारत में पनपी है, और जो आज भी जीवंत है, वैसी अन्य कहीं नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता आंदोलन में देश ने अच्छी तरह समझ लिया था कि भारतीयों को बांटने, और अंततः देश का विभाजन करने में ब्रिटिश शासन ने कैसे-कैसे हथकंडे अपनाए थे। सबसे सशक्त साधन तो उनको 1835 में थामस बैबिंगटन मैकाले ने प्रदान किया था। उन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जो योजन बनाई, उसका लक्ष्य उनके लिए पूरी तरह स्पष्ट था: 'हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं, जो खून और रंग में भारतीय होंगे, मगर रुचि, राय, नैतिकता और बौद्धिकता में अंग्रेज होंगे।'

मैकाले की भारत, उसकी संस्कृति और वैश्विक ज्ञान भंडार में उसके योगदान के संबंध में जो राय थी, उसे याद करने से यह समझ में आ जाएगा कि भारतीयों को सूरत से भले ही न सही, दिल से अंग्रेज बना देने में अपनी सफलता के प्रति वह इतना आश्वस्त क्यों था! मैकाले ने भारत की सुव्यवस्थित ज्ञानार्जन प्रणाली और नए ज्ञान की जनहित में उपयोगिता के लिए शोध के प्रति समर्पण की परंपरा को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंपरागत स्कूलों और संस्थाओं को उसने यह कहकर नकार दिया कि उन पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा, जबकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्कूलों में लोग अच्छी-खासी फीस देकर आने को तैयार रहते हैं। ऐसा आज भी देश में हो रहा है, और यह लगातार बढ़ रहा है।

स्वतंत्रता के बाद तीन-चार दशकों में न जाने कितने बच्चों ने स्कूल कुछ वर्ष बाद केवल अंग्रेजी सीखने में असफल होने के कारण छोड़ दिए थे। धीरे-धीरे वह स्थिति बदली है, लेकिन आज भी अधिकांश सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। कहा नहीं जा सकता है कि

> **भारतीय दर्शन में शिक्षा प्रणाली के तहत विद्या, ज्ञान, मेधा और बुद्धि का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है, जो नैतिक कसौटी पर भी पूरी तरह खरे उतरें। भविष्य के भारत की शिक्षा नीतियां केवल ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण न करें, जो जीवन में सिर्फ धनार्जन और सुख सुविधाओं के संग्रहण को ही शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मान ले या जिन्हें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों और उससे प्राप्त होने वाले 'सत्, चित, आनंद' के संबंध में जानकारी न हो, और न ही इसे लेकर कभी कोई प्रेरणा मिली हो। शिक्षा में मानवीय मूल्यों का होना भी जरूरी है। बेहतर शिक्षा से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है।**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृ भाषा पर दिए गए जोर के बावजूद स्थानीय स्तर पर भी नौकरियों में अंग्रेजी का प्रभाव भाषागत भेदभाव का कारण नहीं बनेगा! वैसे लोग अब घरों में रखे जाने वाले सहायक एवं सहायिकाओं से भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो, वे 'माल' से सामान मंगा सकें, उसमें मियाद की तारीख पढ़ सके! मैकाले की दूरदृष्टि और भविष्य के आकलन की क्षमता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, क्योंकि वह भारतीयों को भारत से अलग करने में कितना सफल रहा, इसे हम आज भी देख रहे हैं। हम आजादी के बाद भी मैकाले के बिछाए जाल से नहीं निकाल पाए, तो इसमें दोष हमारा ही है!

वैसे भी अब समय मैकाले की आलोचना का नहीं, बल्कि भारतीयों को भारत से पुनः पूरी तरह जोड़ने का है। संभवतः ऐसे ही विचार सर्वोच्च स्तर पर नीति निर्धारकों के भी रहे होंगे, तभी तो देश को मैकाले के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करने का आह्वान किया गया है। यह भी स्वीकारोक्ति है कि 1835 में मैकाले ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें जमाने के लिए जिस शिक्षा व्यवस्था को तत्कालीन स्वदेशी प्रणाली को नष्ट कर लागू किया, उसके प्रभाव से भारत आज भी मुक्त नहीं हो पाया है। यह भी एक तथ्य है कि अनगिनत अवसरों पर संसद में चर्चाएं हुई थीं, आश्वासन दिए गए और प्रयास भी हुए, लेकिन बात बनी नहीं! इसका कारण अज्ञात नहीं है, मगर वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसका पुनः विश्लेषण आवश्यक हो गया है। इसके लिए फिर से अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत को स्वीकार करना होगा।

हावर्ड विश्वविद्यालय की ख्याति विश्वव्यापी है और उसे ज्ञान के प्रसार, प्रचार एवं संवर्धन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। यहां के दो पुराने छात्र हेनरी डेविड थोरो और राल्फ वाल्डो एमरसन अपने बौद्धिक ज्ञान और उसके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। एक बार दोनों अपनी पुरानी मातृ संस्था को लेकर चर्चा कर रहे थे। एमरसन ने कहा कि अब इस विश्वविद्यालय में ज्ञान की सभी शाखाएं स्थापित हो चुकी है और प्रगति कर रहीं हैं। थोरो ने उत्तर दिया- शाखाओं की बात अति सुंदर है एवं उत्साहजनक है, लेकिन जड़ें कैसी हैं, यह जानते रहना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक संरचना को गति और मजबूती देने के लिए सबसे पहले उसकी नींव के टिकाऊ आधार-स्तंभों को जानना और समझना आवश्यक है, ताकि इनके ऊपर आगे की संरचना आधुनिक वैश्विक संदर्भ में निर्मित की जा सके।

भारतीय दर्शन में शिक्षा प्रणाली में विद्या, ज्ञान, मेधा, बुद्धि का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है, जो नैतिक कसौटी पर भी पूरी तरह खरे उतरें। भविष्य के भारत की शिक्षा नीतियां केवल ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण न करें, जो जीवन में सिर्फ धनार्जन और सुख सुविधाओं के संग्रहण को ही शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मान ले या जिन्हें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों और उससे प्राप्त होने वाले 'सत्, चित, आनंद' के संबंध में जानकारी न हो, और न ही इसे लेकर कभी कोई प्रेरणा मिली हो। बेहतर शिक्षा से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा में मानवीय मूल्यों का होना भी जरूरी है, तभी सामाजिक चेतना का निर्माण होता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कारों की परंपरा व्यक्ति को उसकी आत्मा की उपस्थिति, गरिमा और उसकी विश्व व्यापकता का भान कराती है। यह पद्धति संस्कारों को जीवन-प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्त्व मानती है। इसी से व्यक्ति में सत्य और अन्याय की समझ बढ़ती है तथा इसकी खोज में जीवन लगाने में आनंद का आभास होता है।

दुनिया मेरे आगे

सुविधा की खामोशी

संगीता सहाय

हाल के दिनों में वर्ष भर की चर्चित राष्ट्रीय घटनाओं, दुर्घटनाओं की यादों की पुनरावृत्ति के क्रम में एक पति की हत्या करके ड्रम में डाल देने और हनीमून मनाने के क्रम में हत्या की बहुप्रचारित दो घटनाओं की खूब चर्चा की गई। ये भी कहा गया कि इन दोनों मामलों ने समाज में वैवाहिक रिश्तों की सुरक्षा, भरोसे और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। निश्चित रूप से ये दोनों घटनाएं भयावह थीं। इस अपराध में शामिल महिलाओं ने न सिर्फ दो निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके माता-पिता और परिवार को जीवन भर का दर्द दिया, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं को भी तार-तार किया। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि जब उन्हें उक्त वैवाहिक बंधनों को निभाना नहीं था, तो विवाह नहीं करना चाहिए था।

हालांकि जीवन और परिस्थितियों के अपने-अपने संदर्भ होते हैं और घटनाएं भी उसी मुताबिक संचालित होती रहती हैं। उसमें दूसरों की राय के लिए बहुत जगह नहीं होती। मगर इन बातों को आज के बिगड़ती सामाजिक बनावट, खराब माहौल, स्वतंत्रता की परिभाषा, मोबाइल और सोशल मीडिया के भयानक तरीके से जीवन में घुसपैठ, सांस्कृतिक क्षरण आदि के रूप में देखा जा सकता है। इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई हैं। टीवी चैनलों ने बहस और चर्चा भी परोसी। महीनों तक हर तरफ घरों, मोहल्लों, चौक-चौराहों यही मुद्दा छाया रहा। पूरी महिला बिरादरी इसके लपेटे में आई और गाहे-बगाहे उन्हें तीखी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। जो हुआ, वह निश्चित तौर पर बुरा था और पूरे समाज ने इसके विरोध में जिस तरीके से एकजुटता दिखाई, वह गौरतलब थी।

इसके समांतर कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल, जो इन शोरगुल के बीच दबे रह गए या किसी ने उठाया भी तो लोगों को गौरतलब ही नहीं लगा, वह यह है कि क्या ये दोनों मामले 'वैवाहिक हत्याओं' के संदर्भ में इकलौते हैं? क्या कभी लड़कियों की दहेज, अवैध संबंध, झूठे सम्मान के नाम पर हत्या अन्य मुद्दों को लेकर ऐसी ही या इससे भी विद्रूप नृशंस हत्याएं नहीं की गई हैं? सामूहिक बलात्कार, तेजाबी हमले से मारी जाती, अपंग होती लड़कियों के मामलों पर कभी इतना शोर क्यों नहीं हुआ? कम या ज्यादा उम्र में बलात्कार का दंश भोगती, प्रताड़ित होती, मौत की ओर धकेली जाती अनगिनत महिलाओं के सच को जानकर भी समाज ने अब तक क्या किया है?

हमारे इर्द-गिर्द हर रोज होती ऐसी घटनाएं और साल दर साल महिला उत्पीड़न के बढ़ते आंकड़ों का सच आखिर क्या है? प्रश्न यह भी कि चंद अपवादों की बात छोड दें, तो क्या दूसरा पक्ष भी परंपराओं, कट्टरता और आपराधिक प्रवृत्ति के त्रास तले उतना ही दंड भोग रहा है? ऐसे तमाम आपराधिक कृत्य हर रोज, हर तरफ होते हैं, तो फिर कुछ घटनाओं की तरह सामाजिक एकजुटता इन पर क्यों नहीं दिखाई जाती? संभव है, वैसी ही एकजुटता महिला उत्पीड़न के बढ़ते आंकड़ों की दर को कुछ कम कर देती। यहां आशय लैंगिक आधार पर अपराधों को कम या ज्यादा करके आंकना कतई नहीं है, क्योंकि अपराधी चाहे महिला हो या पुरुष, उसकी प्रवृत्ति सिर्फ अपराध करने की होती है। पीड़ित भी सिर्फ पीड़ित होता है। वर्ग या रसूख के आधार पर अन्याय तथा अनाचार का बंटवारा करना और न्याय का पलड़ा उसके अनुसार मोड़ना अपने आप में एक बड़ी खामी है।

आज के कथित आधुनिक समाज में भी स्त्री को पल प्रति पल अनगिनत मानसिक और शारीरिक अपराधों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति बाहर के साथ-साथ अक्सर घर में भी होती है। कभी मिथ्या सामाजिकता और संस्कृति बचाए रखने, कभी पारिवारिकता को बनाए रखने, कभी प्रचलित फिजूल की परंपराओं के सम्मान में, तो कभी सुरक्षा के नाम पर स्त्री को असंख्य आपराधिक कृत्यों का सामना करना पड़ता है। शादी के बाद परिवार के भीतर और खासतौर पर पत्नी के प्रति पति के निजी व्यवहार तो हमारे समाज में कभी बहस का विषय रहे ही नहीं हैं। ऐसे उत्पीड़न को आमतौर पर प्यार का नाम देकर बड़ी आसानी से छुटकारा पा लिया जाता है। ज्यादातर महिलाओं ने इसे सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया है।

> **आज के आधुनिक समाज में भी महिला को अनगिनत मानसिक और शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ता है। यह स्थिति बाहर के साथ-साथ अक्सर घर में भी होती है। कभी फिजूल की परंपराओं, तो कभी असुरक्षा के कारण महिलाओं को आपराधिक कृत्यों का सामना करना पड़ता है।**

अधिकांश परिवार आज भी उसी पुरातन सोच पर कायम है कि बेटियां जिस घर में ब्याही जाती हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वही उनका अपना घर होता है। यही सोच लड़कियों को सब कुछ सहकर ससुराल में रहने के लिए विवश करता है। परिवार भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें ऐसा करने को मजबूर करता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोचने-समझने के ढांचे और मानस में घुली सोच की होती है, जिससे छुटकारा पाना केवल साहस और दखल के बूते संभव है, लेकिन इसमें बेटियों की संपत्ति में हिस्सेदारी का डर एक बड़ी भूमिका निभाता है।

चूंकि तमाम कानूनों के बावजूद अभी भी पिता की संपत्ति पर व्यवहार में सिर्फ बेटों का ही अधिकार होता है और ससुराल की संपत्ति तो बेटियों की होती ही नहीं है, तो ऐसे में आर्थिक रूप से पराश्रित लड़कियां मृत्युपर्यंत सब कुछ सहने को अभिशप्त होती हैं। अगर वे आवाज उठाती भी हैं तो 'घर तोड़ने वाली' महिला जैसी संज्ञा से नवाजी जाती हैं। इस तरह की सारी परिस्थितियां स्त्रियों की चुप्पी का कारण बनती हैं। हमारा समाज भी स्त्रियों के अनुपयोगी होने की अपनी धारणा के अनुसार उनके साथ होने वाले तमाम अत्याचारों, यहां तक की मृत्यु पर भी मौन की खाल ओढ़े रहता है। कुछ खास और चर्चित घटनाओं में हत्याओं पर होने वाला शोर और शेष पर मौन उसी का हिस्सा है।

चौपाल

कार्रवाई पर सवाल

यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई क्यों की? क्या वेनेजुएला को सबक सिखाने के लिए या उसके तेल एवं खनिज संपदा पर कब्जा करने के लिए। अगर उसे निकोलस मादुरो की सत्ता को खत्म करना था, तो फिर वहां विपक्ष को सत्ता सौंपी जा सकती थी। वैसे भी यह अधिकार अमेरिका को किसने दिया है कि वह कहीं भी आक्रमण कर दे। वर्ष 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक, जिन देशों में तानाशाही है, उनमें ऐसे कई देश हैं, जिनकी पहचान अक्सर एकदलीय शासन से होती है। क्या ट्रंप प्रशासन ऐसे देशों पर भी हमला करने की योजना बना रहा है? वेनेजुएला ने कौन सा अपराध किया? अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी या उस पर कोई हमला? या अमेरिका को तेल निर्यात न करना? यही वो अमेरिका है, जिसने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन आरलैंडो जिन पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप साबित होने पर भी उन्हें क्षमादान दे दिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या यह दुनिया कानून से नहीं, बल्कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के तरीके से चलेगी?

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

दिखावे का साथ

'पीड़ा के स्तर' (दुनिया मेरे आगे, तीन जनवरी) पढ़ा। यह गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस बनावटी दुनिया में हर कोई अपना मतलब साधने में लगा है। इंसान आज के दौर में तेजी से रिश्ते बदल रहा है। जब तक आपसे मतलब है, तभी तक आपसे बात करता है, आपकी बात मानता है और तो और आप में उसको अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने उसके दस काम कर दिए और किन्हीं कारणों से एक काम नहीं कर पाए, तो सारे संबंध और सारी अच्छाइयां पल भर में गायब हो जाती हैं। जहां कल आप में सौ अच्छाइयां थीं, वही आदमी बुराइयों का अंबार लगा देता है। हमारी संस्कृति में तो देना सिखाया जाता है, लेना नहीं। मगर हम सब यह भूल गए हैं। हमारी सोच व्यक्तिगत हित तक सिमट गई है। लोग तुरंत कह देते हैं कि फिक्र मत करो, मैं हमेशा साथ खड़ा हूं, लेकिन वक्त पड़ते ही गायब हो जाते हैं।

– हुकम सिंह मेरठी, ग्वालियर

प्रशासनिक विफलता

भारत में प्रशासनिक नाकामी अमूमन आम बात हो गई है। खांसी की दवा से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौत के बाद इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में नगर निगम का गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। रीवा मेडिकल कालेज में हाल में आगजनी से नवजात की मौत हो गई। पिछले साल झांसी मेडिकल कालेज में आगजनी से कई लोगों की जान चली गई थी। गटर में सफाई के दौरान मौत का आंकड़ा डरावना है। भारत में इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हादसों को रोकने के उपाय लोगों की जान जाने के बाद कुछ समय के लिए प्रभावी होते हैं। यह ठीक उसी तरह है, जैसे प्यास लगने पर कुआं खोदा जाना। पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे को कोसने में लगे रहते हैं। प्रशासनिक लालफीताशाही सबके सामने है। अधिकारी आंकड़ों का खेल खेलते रहते हैं और हाशिए पर बैठे लोगों की सुध लेना केवल तस्वीरें खिंचवाने तक ही सीमित रहता है।

– कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, इटौरा, मप्र

साम्राज्यवादी सोच

'मनमानी के बरक्स' (संपादकीय, छह जनवरी) पढ़ा। स्वयं को विश्व शांति का पैरोकार बताने वाला अमेरिका वैश्विक अस्थिरता के सबसे बड़े कारकों में से एक है। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, क्यूबा और ग्रीनलैंड को धमकाने की भाषा किसी जिम्मेदार देश की नहीं, बल्कि एक साम्राज्यवादी सोच को दर्शाती है। इससे पहले मैक्सिको और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया जाना इसी मानसिकता का उदाहरण है। ग्रीनलैंड को लेकर उसकी महत्त्वाकांक्षा पुरानी है। अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। वेनेजुएला में उसे उसके विशाल तेल भंडार चाहिए, जबकि ग्रीनलैंड में दुर्लभ तत्त्वों का बड़ा स्रोत है। ये तत्त्व अमेरिका की तकनीक, आटोमोबाइल और रक्षा उद्योग के लिए अहम हैं। अमेरिका की यह मनमानी आगे और भी गंभीर रूप ले सकती है।

– चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

उच्चतम न्यायालय ने कहा

सड़कों पर कुत्ते और आवारा जानवर नहीं होने चाहिए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली,7 जनवरी।

उच्चतम न्यायालय ने नगरीय निकायों द्वारा नियमों और निर्देशों का अनुपालन न करने की ओर ध्यान दिलाते हुए बुधवार को कहा कि देश में न केवल कुत्तों के काटने से बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से भी लोगों की मौत हो रही है। पीठ ने कहा, सड़कों पर कुत्ते और आवारा जानवर नहीं होने चाहिए। कुत्तों के काटने की घटनाएं ही नहीं, बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों का घूमना भी खतरनाक साबित हो रहा है। सुबह-सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में होगा, यह कोई नहीं जानता। नगर निकायों को नियमों, कार्य प्रणालियों और निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

कुत्ता प्रेमियों और आदेशों के कड़े अनुपालन की मांग करने वालों द्वारा दायर न्यायालय के पूर्व आदेशों में संशोधन की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह सुनवाई इसलिए कर रही है, क्योंकि कई वकीलों और पशु कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि सात नवंबर को आदेश पारित होने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई थी। न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने समस्या की गंभीरता पर बात रखी तो सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जीव जन्तु प्रेमी का मतलब केवल कुत्ता प्रेमी नहीं होता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई गेटेड सोसायटी में भैंस पालना चाहे तो क्या होगा? न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि पिछले 20 दिनों में राजस्थान हाई कोर्ट के दो जज आवारा जानवरों से जुड़े हादसों का शिकार हुए हैं। इनमें से एक जज अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आवारा कुत्तों के काटने से ही नहीं, आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसों में भी लोगों की जान जा रही।
कोर्ट ने कहा, सड़कों पर आवारा जानवरों का घूमना भी खतरनाक साबित हो रहा है। सुबह-सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में होगा, यह कोई नहीं जानता। नगर निकायों को नियमों, कार्य प्रणालियों और निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

पशु प्रेमियों की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कोई प्रतिद्वंद्वी मामला नहीं है। हम यहां कुत्तों से प्रेम करने वालों के रूप में हैं। अगर कोई एक बाघ आदमखोर हो जाए तो हम सारे बाघों को नहीं मार सकते। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नसबंदी हो और प्रदूषण कम हो। इसके लिए एक प्रक्रिया है।

सिब्बल ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इससे कुत्तों की आबादी लगभग शून्य तक आ गई है। अगर ऐसे कुत्ते, जिन्हें रेबीज है और जिन्हें नहीं है, दोनों एक ही शेल्टर में रखे जाएं तो सभी को रेबीज हो जाएगा। जब भी मैं मंदिरों आदि में गया हूं, मुझे कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा। इसपर पीठ ने कहा कि आप भाग्यशाली हैं। लोगों को काटा जा रहा है। बच्चों को काटा जा रहा है।सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एनिमल लवर्स का मतलब डाग लवर्स नहीं होता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई गेटेड सोसायटी में भैंस पालना चाहे तो क्या होगा? इसका फैसला कौन करेगा? इस पर याचिकाकर्ता ने खुद दूसरे देशों का हवाला देते हुए कुछ आंकड़े पेश किए। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब आप दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, तो बताइए सिंगापुर या नीदरलैंड्स में आपको कितने आवारा कुत्ते दिखते हैं? इसपर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला विरोधी नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ कुत्तों से प्रेम करने वालों का नहीं, बल्कि इंसानों से प्रेम करने वालों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने पूछा कि दूसरे जानवरों का क्या? जैसे मुर्गी या बकरी? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें पिंजरों में रखा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय कुत्तों की देखभाल करता है और वे कई बार खान मार्केट गए हैं। जहां उन्हें कभी कुत्ते ने नहीं काटा। इस पर पीठ ने कहा कि आप और हम शायद खुशकिस्मत हों, लेकिन हर कोई नहीं। नेहरू पार्क में भी लोगों को कुत्तों ने काटा है। कपिल सिब्बल ने कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने और आक्रामक कुत्तों के पुनर्वास के लिए कुछ सुझाव गिनाए। इस पूरी बहस पर अंत में न्यायमूर्ति मेहता ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो बस काउंसलिंग ही बाकी रह गई है। किसी को कुत्तों को भी समझाना चाहिए कि वे लोगों को न काटें। न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने अदालत को बताया कि एनएचएआइ को एक एसओपी तैयार करने के लिए कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी से दिया अंतरिम संरक्षण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने नेहा सिंह राठौर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उनके विरुद्ध कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ ने यह राहत उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दी है।

यह याचिका इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नेहा सिंह राठौर को जांच अधिकारी के समक्ष जब भी बुलाया जाए, उपस्थित होना होगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि वह पहली बार 19 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों।

छत्तीसगढ़ : सुकमा जिले में 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा, 7 जनवरी (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 13 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की 'छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुकमा पुलिस 'पूना मार्गेम' पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान चला रही है। इससे प्रभावित होकर तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार शिविर स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव से नक्सली संगठन में सक्रिय सात महिला सहित 26 नक्सलियों ने बुधवार को सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण और सुरक्षाबलों के वरिष्ठ अधिकारियों सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से 13 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम है।

इनमें से 13 पर 65 लाख रुपए का इनाम है।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में नक्सलियों के सीआरसी कंपनी नंबर में प्लाटून नंबर दो का डिप्टी कमांडर लाली उर्फ मुचाकी आयते (35 वर्ष) भी शामिल है, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम है।

लाली के खिलाफ 2017 में सोनाबेड़ा गांव से कोरापुट मार्ग पर सुरक्षाबलों के वाहन को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ाने की घटना में शामिल होने का आरोप है। इस घटना में 14 जवानों की मृत्यु हुई थी।

सियासत
हावेरी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार केक खिलाते हुए।

क्या पद से हटाने के प्रस्तावित कानून के दायरे में नेता प्रतिपक्ष भी होंगे

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

संसद की एक समिति के सदस्यों ने बुधवार को यह सवाल किया कि क्या नेता प्रतिपक्ष का पद भी उस प्रस्तावित कानून के दायरे में आता है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के एक महीने के भीतर जमानत नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान है।

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही है। समिति ने विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी और कुछ अन्य के विचारों को सुना। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति जीएस बाजपेयी और हैदराबाद स्थित 'नैशनल एकेडमी आफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च' (नैलसर) के कुलपति श्रीकृष्ण देव राव भी इस संयुक्त समिति के सामने उपस्थित हुए। पूरे घटनाक्रम से अवगत एक सूत्र ने बताया कि कई सदस्यों ने यह जानने की कोशिश की कि क्या विपक्ष के नेता को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होने के बाद एक महीने के भीतर जमानत नहीं मिलने पर पद से हटाया जा सकता है।

संसद समिति के सदस्यों का सवाल।

विपक्ष के एक नेता ने तीन मसौदा कानूनों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित करने की जोरदार वकालत की, जो संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं हैं। समिति के सदस्यों का एक वर्ग विपक्षी सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत नहीं था।

नाबालिग से सामूहिक बलात्कार, स्थानीय पत्रकार पकड़ा गया

कानपुर, 7 जनवरी (भाषा) ।

जनपद में नाबालिग लड़की के अपहरण और उससे सामूहिक बलात्कार के मामले में एक स्थानीय पत्रकार को हिरासत में लिया गया और एक सिपाही की भूमिका की जांच की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, नाबालिग लड़की को सोमवार रात दो लोगों ने एक स्कार्पियो कार में अगवा कर लिया था। आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी था क्योंकि उसने वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसे सचेंडी में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां गाड़ी के अंदर करीब दो घंटे तक उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और बाद में बेहोशी की हालत में उसे उसके घर के बाहर फेंक दिया गया। पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया कि उसने आधी रात में घर के बाहर बहन को बेहोशी की हालत में पड़ा पाया, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सिपाही की भूमिका की जांच, शिकायत पर तुरंत नहीं हुई कार्रवाई।

परिवार ने बाद में मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक बलात्कार से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक बलात्कार के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कांग्रेस ने बघेल को असम और पायलट को केरल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया

नई दिल्ली,7 जनवरी (ब्यूरो)।

कांग्रेस ने बुधवार को पांच चुनावी राज्यों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को असम तथा पार्टी महासचिव सचिन पायलट को केरल की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।

असम के लिए बघेल, शिवकुमार और पार्टी की झारखंड इकाई के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने असम के लिए इन प्रमुख नेताओं को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त करने के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को राज्य से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। केरल के लिए पायलट के साथ कर्नाटक सरकार के मंत्री केजे जार्ज, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी और पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ इस बार सत्ता की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, तेलंगाना सरकार के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी व उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य काजी मोहम्मद निजामुद्दीन तथा पश्चिम बंगाल के लिए त्रिपुरा के वरिष्ठ नेता सुदीप राय बर्मन, बिहार में कांग्रेस के विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खान और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन राज्यों में इस साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभावित है।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया पर संदेह जताया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया पर संदेह जताया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा-सवाल यह है कि क्या राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव खारिज करने पर लोकसभा की कार्यवाही भी खत्म हो जाएगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के जांच कमेटी बनाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच सलाह मशविरा नहीं हुआ है।

बकौल न्यायमूर्ति वर्मा लोकसभा सचिवालय का कहना है कि राज्यसभा ने प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया है। इसलिए पुरानी व्यवस्था लागू नहीं होती है। अदालत इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इसमें जजों की जांच से जुड़े कानून की बारीकियों को समझा जा रहा है। यह फैसला भविष्य में महाभियोग की प्रक्रियाओं के लिए बड़ा उदाहरण बनेगा। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कड़ी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ है। जजेस इंक्वायरी एक्ट की धारा 3 के तहत एक खास प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव आता है, तो संयुक्त परामर्श जरूरी है।

रोहतगी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति के फैसले का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एकतरफा तरीके से तीन सदस्यों की जांच कमेटी बना दी। वकील ने इसे कानून का उल्लंघन और प्रक्रिया की बड़ी चूक बताया है। अगस्त 2025 में राज्यसभा के उप सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

पेज 1 का बाकी

चुनाव आयोग ने अमर्त्य सेन को तलब किया

दिया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत गणना प्रपत्र में कुछ तार्किक विसंगतियां पाई गईं, जिसके कारण उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। चूंकि वे 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, इसलिए संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार सुनवाई के लिए उनके आवास पर उनसे मिलने जाएंगे।'

सेन के चचेरे भाई ने नोटिस मिलने की पुष्टि की और कहा कि वह इस घटनाक्रम के बारे में शिक्षाविद को सूचित करेंगे। अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के दौरान 'तार्किक विसंगति' के आधार पर जारी किया गया था, क्योंकि गणना प्रपत्र में दर्ज सेन और उनकी माता की आयु का अंतर 15 वर्ष से कम पाया गया था। इस घटनाक्रम को लेकर पहले ही राजनीतिक हंगामा खड़ा हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सेन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एसआइआर नोटिस जारी करना 'बंगाल की जनता का अपमान' करने के समान है। लेकिन भाजपा और निर्वाचन आयोग, दोनों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। हालांकि, तृणमूल ने निर्वाचन आयोग और भाजपा पर लगातार हमले जारी रखे और इसे विभाजन करने और नीचा दिखाने का उनका 'बंगाल-विरोधी' एजंडा करार दिया। सेन को नोटिस सौंपे जाने के बाद पार्टी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'नोबेल पुरस्कार विजेता को किसी भी संदेह से परे होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर वह बंगाली हैं तब क्या होगा? फिर उन्हें आम अपराधी की तरह सुनवाई का नोटिस थमा दिया जाएगा।'पार्टी ने कहा, 'अमर्त्य सेन, जिनके अभूतपूर्व कार्यों ने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी है, जिन्होंने बंगाल और पूरे देश को अद्वितीय गौरव दिलाया है, और जिनके विचारों का अध्ययन दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में किया जाता है, उन्हें एसआइआर सुनवाई का नोटिस जारी किया गया है।'

तृणमूल ने आरोप लगाया कि एसआइआर भाजपा और निर्वाचन आयोग के इशारे पर किया गया एक 'घृणित और शर्मनाक तमाशा' है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, 'वे हमारे आदर्शों को बदनाम करेंगे, हमारे गौरव को धूमिल करेंगे और विभाजन और अपमानित करने के अपने बांग्ला-विरोधी एजंडे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं।'

वैष्णो देवी कालेज की एमबीबीएस मान्यता रद्द

का नाम आबंटित सूची में रखा गया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया। हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई। इसलिए दाखिला सूची तुरंत रद्द होनी चाहिए।

साथ ही हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि यह कालेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से चलता है। इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।आयोग के अनुसार, कालेज ने एनएमसी के मानकों का उल्लंघन किया। निरीक्षण के समय में ऐसी कमियां सामने आईं, जिन्होंने उन शर्तों का उल्लंघन किया, जिनके तहत संस्थान को मंजूरी दी गई थी। इसलिए एनएमसी ने मेडिकल कोर्स की मान्यता रद्द कर दिया। एनएमसी की टीम ने 2 जनवरी 2026 को कालेज का निरीक्षण किया।

संस्थान में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या और क्लीनिकल सुविधाओं में गंभीर कमियां हैं। रपट के अनुसार कालेज में शिक्षकों की संख्या करीब 39 फीसद कम थी। ट्यूटर, डेमोंस्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डाक्टरों भी 65 फीसद कम मिले।

मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, पांच पुलिसकर्मी घायल

लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 191 (दंगा), 223 (ए) (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से जारी आदेश की अवज्ञा) और 3(5) (संयुक्त दायित्व) तथा लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस ने कहा कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई और सामान्य स्थिति बहाल हो सकी। उनका कहना है कि जिस वीडियो के कारण विवाद पैदा हुआ, उनमें से एक को खालिद मलिक नामक व्यक्ति ने रिकार्ड किया था। इसमें लोगों से बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलने का आग्रह किया गया। अफवाहें फैलाई गईं।

एक अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो का विश्लेषण करके अन्य दोषियों की पहचान की जा रही है। वल्सान ने बताया कि अदालत ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास स्थित एक बारात घर और एक औषधालय को अतिक्रमण घोषित किया था और इन्हें ही ढहाया जाना था। एसीपी ने स्थानीय निवासियों को बताया कि यह तोड़फोड़ कानूनी कार्रवाई है।

दो निकायों में भाजपा का कांग्रेस व एआइएमआइएम से गठबंधन

बताया। भाजपा ने 20 दिसंबर को हुए स्थानीय चुनावों के बाद अपनी कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के साथ 'अंबरनाथ विकास आघाडी' के बैनर तले गठबंधन करके अंबरनाथ नगर पालिका परिषद का नेतृत्व संभाला और सहयोगी शिवसेना (एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली) को दरकिनार कर दिया।

भाजपा ने अकोला जिले की अकोट नगर पालिका परिषद में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) और अन्य पार्टियों के साथ इसी तरह का गठबंधन किया। इस घटनाक्रम से असहज स्थिति में आ गई कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए अंबरनाथ नगर पालिका परिषद के अपने 12 नवनिर्वाचित पार्षदों और ब्लाक अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। शिवसेना (उबाठा) ने भी भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि यह सत्तारूढ़ पार्टी के दोहरे मापदंड को दर्शाता है और दिखाता है कि वह सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अंबरनाथ में भाजपा ने कांग्रेस और राकांपा के साथ चुनाव बाद समझौता किया और 31 सीट के साथ बहुमत साबित किया, जबकि शिवसेना 27 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है।

शिवसेना ने 60 सदस्यीय नगर पालिका परिषद के चुनाव में 27 सीट जीतीं, जो बहुमत से मात्र चार कम थीं। भाजपा को 14 सीट, कांग्रेस को 12, राकांपा को चार सीट मिलीं, जबकि दो सीट पर निर्दलीय निर्वाचित हुए। एक निर्दलीय के समर्थन से, तीन दलों के गठबंधन की ताकत बढ़कर 32 पार्षद हो गई है, जो बहुमत के लिए जरूरी 30 के आंकड़े को पार कर गई। भाजपा पार्षद तेजश्री करंजुले पाटिल ने शिवसेना की मनीषा वालेकर को हराकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जीता और शपथ ली।

इस असहज स्थिति पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने अकोट के विधायक प्रकाश भरसखाले को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

प्रधानमंत्री से वार्ता को लेकर ट्रंप के दावे पर भारत ने साधी चुप्पी

व्यापार वार्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हम वही कर रहे हैं। दूसरी ओर, ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने उन्हें बताया है कि वह अपाचे हेलिकाप्टरों के लिए पांच साल से इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा, 'हम इसे बदल रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे हेलिकाप्टर का आर्डर दिया है।'

इस बारे में सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारत ने सिर्फ 28 अपाचे हेलिकाप्टर खरीदे हैं- वायुसेना के लिए 22 और थलसेना के लिए छह। ये सभी हमें मिल गए हैं। इनमें से 22 हेलिकाप्टर की खरीद के सौदे पर वर्ष 2015 के सितंबर में ओबामा के दौर में करार हुआ था। ये हेलिकाप्टर ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत को मिले थे। दूसरे सौदे के लिए ट्रंप के भारत दौरे के दौरान 2020 में करार हुआ था। इसमें देरी हुई थी और ये हेलिकाप्टर दिसंबर 2025 तक मिले। इन्हें जनवरी-फरवरी 2024 तक मिल जाना चाहिए था। जहां तक ट्रंप की टिप्पणियों का सवाल है, प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में चुप्पी बरती जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया व्यक्त करने से नुकसान हो सकता है। बेहतरी इसी में है कि राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया जाए। सूत्रों ने कहा कि हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह हमें व्यापार वार्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हम वही कर रहे हैं।

इस बीच, लक्जमबर्ग में बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान कहा कि मीलों दूर स्थित देश कहते हैं कि उन्हें तनाव होने से चिंता होती है, लेकिन वे अपनी स्थिति का आकलन नहीं करते कि उनके इलाके में क्या हालात हैं।

उन्होंने कहा, 'लिहाजा, जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं और सकारात्मक, मददगार हैं, उनके साथ हम उसी तरह पेश आएंगे। जो लोग वे काम करते हैं, जो पाकिस्तान कर रहा है, हमें उनके साथ अलग तरह से पेश आना होगा।' उन्होंने कहा, 'दूर बैठे लोग कुछ भी कहेंगे, कभी सोच-समझकर, कभी नहीं, कभी अपने हित में, कभी लापरवाही से। वे आपको मुफ्त की सलाह देते हुए। अगर कुछ होता है तो कहते हैं, आप मत करिए।'

महादेव एप मामला : ईडी ने मुख्य प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर सहित अन्य की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने अवैध महादेव आनलाइन सट्टेबाजी एप के मुख्य प्रवर्तकों में से एक सौरभ चंद्राकर सहित विभिन्न आरोपियों की लगभग 92 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया है।

परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी और एक्जिम जनरल ट्रेडिंग - जीजेडसीओ द्वारा धारित 74.28 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक जमा राशि को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया। ईडी ने एक बयान में कहा, ये इकाइयां सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया की हैं। महादेव एप का प्रचार चंद्राकर और उसके सहयोगी रवि उप्पल ने किया था। वे दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं।

ईडी ने कहा, ये इकाइयां सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया की हैं। महादेव एप का प्रचार चंद्राकर और उसके सहयोगी रवि उप्पल ने किया था। वे दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं।

उनका विदेश से प्रत्यर्पण कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके संयुक्त अरब अमीरात में होने का पता चला था। इसके अलावा, हरि शंकर टिबरेवाल के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है, जिसके बारे में ईडी का दावा है कि वह स्काईएक्सचेंज डाट काम का मालिक और दुबई स्थित एक कथित हवाला आपरेटर है। चंद्राकर और अन्य आरोपियों ने महादेव एप के माध्यम से लोगों से ठगी की, जिसे कई अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों या एप) को ग्राहकों को आकर्षित करने और इन अवैध सट्टेबाजी गेम और वेबसाइटों के लिए वित्तीय संचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

प्रेरणा

झूठे ज्ञान से बचकर रहना चाहिए। यह अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। - बर्नार्ड शॉ

संपादकीय

यूरोप से रिश्ते बेहतर करने का यही सबसे ठीक समय

जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आ रहे हैं। इस वर्ष गणतंत्र-दिवस के अवसर पर भी दो राजकीय मुख्य अतिथि होंगे- 27 देशों वाले संगठन ईयू कमीशन की मुखिया उर्सुला और इसकी परिषद् के अध्यक्ष अंटोनियो कोस्टा। ईयू आर्थिक और सामरिक रूप से एक समेकित इकाई की तरह काम कर रहा है और इसकी कुल जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। ईयू तकनीकी और सैन्य उत्पादन में भी शिखर पर है। आज जब ट्रम्प के टैरिफ ने भारत सहित दुनिया को हिला दिया है, ईयू-खासकर जर्मनी और फ्रांस से- भरोसे के संबंध रखना भारत के लिए दूरदर्शी और बहुआयामी है। यूके से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही हो चुका है और ईयू से ऐसा समझौता लगभग अंतिम दौर में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और खासकर भारत जैसे सम्प्रभु राष्ट्र के साथ ट्रम्प की मनमानी के मद्देनजर नई दिल्ली के लिए जरूरी था कि ईयू के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयां दे। ऐसा नहीं है कि यह एकतरफा जरूरत है। ग्रीनलैंड और अन्य यूरोपीय देश और हाल के दौर में दक्षिण अमेरिकी देश भी ट्रम्प की स्वेच्छाचारिता के शिकार बन रहे हैं। ऐसे में ईयू को भी भारत जैसे बाजार की जरूरत है। लिहाजा भारत-ईयू संबंध पारस्परिक होंगे। भारत अपनी प्रतिक्रिया से ट्रम्प को भड़काने के बजाय, सहज भाव में रूस, यूरोप, अफ्रीका और अवसर-विशेष पर चीन के साथ बेहतर संबंध रखे, यही समय की जरूरत है। भारत को अपने पत्ते होशियारी से खेलने होंगे।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

अतीत को भूलें, वर्तमान को पकड़ें और भविष्य से जुड़ें

नए साल की पहली तारीख को बहुत सारे लोग कोई न कोई संकल्प लेते हैं। फिर 2 तारीख तक उसे भूल भी जाते हैं और उसके बाद वैसे ही हो जाते हैं, जैसे पिछले साल थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। नए साल का उत्साह, संकल्प का चिंतन कम से कम एक महीने तो रहे- ताकि आने वाले 11 महीने हम कुछ नया कर सकें। श्रीराम को जब वनवास हुआ और उन्होंने रामकथा के अरण्यकांड में प्रवेश किया तो तीन बातें सिखाईं। अतीत को भूलना, वर्तमान को पकड़ना और भविष्य से जुड़ना। श्रीराम का जीवन लगभग यू-टर्न ले चुका था। लेकिन जब कुछ कैकेयी ने उनके साथ किया, उसे अतीत मानकर, उससे शिक्षा लेकर भूल गए। क्योंकि जीवन में जितने बोझ हम उठाते हैं, उनमें से एक बड़ा बोझ अतीत का भी होता है। सिर पर ज्यादा बोझ रख लो तो चाल बिगड़ जाती है। वर्तमान को पकड़ें। जो आज हो रहा है, उससे जुड़ें, एकाग्र होकर उस पर काम करें और भविष्य से अपने आप को जोड़ें। बहुत तेजी से इस साल दुनिया बदलेगी। हम अपडेट रहें, यही श्रीराम सिखा रहे हैं।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार हो

आज हमारे पास जरूरत से काफी कम पानी बचा है। कुओं की अनदेखी से उनका पानी दूषित हो चुका है। जल स्रोतों पर अतिक्रमण हो गए। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि गांव-शहरों में कुएं-बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराया जाए। यदि इन पर अतिक्रमण हो गया है तो उन्हें मूल स्वरूप में वापस लाने के प्रयास हों। जल स्रोतों की स्वच्छता से दूषित पानी से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। -राममोहन चंद्रवंशी, टिमरनी, मध्यप्रदेश

अर्थव्यवस्था टिकाऊ विकास की ओर बढ़े

दीर्घकालिक उन्नति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार में ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में भी आगे बढ़ाना जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश, निवेश-अनुकूल माहौल, निरंतर आर्थिक सुधार और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को प्राथमिकता जरूरी है। यदि जनसांख्यिकीय लाभांश, महिला श्रम भागीदारी, ग्रीन ट्रांजिशन प्रभावी ढंग से लागू करें तो भारत 2047 से पहले ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। -मोहम्मद जुबैर, दिल्ली

जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो

इंदौर में दूषित जल से मौतें अनदेखी और गलत निर्माण का नतीजा हैं। जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अमले के समन्वय से शहर, जिला व गांव में मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छ जल, अच्छी सड़क, सुरक्षा आदि प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इनमें लापरवाही पर राजनीति और प्रशासन, दोनों से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दोनों जब वेतन, भत्ते और पेंशन के हकदार हैं तो सजा की भागीदारी भी होनी चाहिए। -प्रतिभा शाह, इंदौर, मध्य प्रदेश

बांग्लादेश में खेलेगी भारतीय टीम?

बीसीसीआई ने केकेआर पर दबाव डाल कर बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से हटाने पर मजबूर कर दिया। अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी इतने ही अछूत हैं तो फिर कैसे भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर, 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी? यह दोनों टीमों के बीच पहली द्विपक्षीय टी-20 सीरीज होगी। अगर यह सीरीज होगी तो फिर किस आधार पर केकेआर पर दबाव बनाकर बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने के लिए मजबूर किया गया? -जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

कनाडा में हैं दुनिया की सर्वाधिक 8 लाख से ज्यादा झीलें

कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा झीलों वाला देश है। कनाडा में 8.79 लाख झीलें ऐसी हैं, जिनका क्षेत्रफल एक लाख वर्गमीटर से अधिक है। इसके अलावा छोटी झीलें भी जोड़ी जाएं तो यह आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंचता है। कनाडा की भौगोलिक स्थिति ही वहां पर इतनी संख्या में झीलें होने का कारण है। हजारों साल पहले हिम युग में यह पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादरों के नीचे दबा था। आइस शीट्स के पिघलने से बेसिन बने और ग्लेशियर्स के पिघलने से इनमें पानी भर गया। माना जाता है कि दुनिया की 60% झीलें अकेले कनाडा में ही हैं।

31000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है ग्रेट बेयर लेक का, जो कनाडा की सबसे बड़ी झील मानी जाती है।

सुर्खियों से आगे • बड़े-बूढ़े कह गए हैं कि जो पेड़ नई कोंपलों का स्वागत नहीं करते, ठूंठ हो जाते हैं

एआई से आगे जीत है...

कृत्रिम मेधा

नवनीत गुर्जर
navneet@dbcorp.in

जमाना एआई का है! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। भाव, भावनात्मक बातों और संवेदना जैसी चीजों का अकाल आने वाला है।

बच्चे को मां की कस्टडी में देने को हम मां के संरक्षण में देना लिखा करते थे। एआई उसे मां की हिरासत में देना लिख दे रहा है!

ऐसे कई भावनात्मक या भावानुवाद हैं, जहां एआई के कारण मशीनी उपहास हो रहा है।

इससे बचना या बचाना आखिर मनुष्य के हाथ में ही है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी!

निश्चित ही एआई के कारण बहुत युगांतकारी परिवर्तन आ रहा है। आने वाला है। लेकिन क्षेत्र या कार्यक्षेत्र कोई भी हो, मनुष्य की चतुराई या उसकी कल्पना, संवेदना का अब इस एआई के दौर में भी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आगे भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं।

कई ऐसी भावुक बातें हैं, संवेदनाएं हैं, जिन्हें दुनिया की कोई मशीन कभी महसूस नहीं कर सकती।

फिलहाल तो नहीं ही।

वो बनारस के मणिकर्णिका घाट पर घंटों बैठकर जो कुछ महसूस होता है, या महसूस किया जा सकता है, क्या एआई वह कर सकता है?

...कि कैसे मनुष्य का सबकुछ जब जलता-भुनता रहता है, तब आसपास की दीवारों की सीलन का पानी भी तपता, सूखता रहता है।

कैसे घाटों पर जाजम बिछाए बैठे लोग आते-जाते लोगों के हाथों से गिरे चावल के दाने बीनते रहते हैं!

वे नीचे फर्श पर ही बैठते हैं। क्योंकि वे कुर्सियों के पहले जन्मे हैं! असी घाट पर सुबह-ए-बनारस में क्या एआई यह कल्पना कर सकता है कि शंख जैसा भोर का नभ नजर आ रहा है। जैसे राख से लीपा हुआ चौका। जैसे केसर घोलकर रंगी हुई चौखट!

टुकड़े-टुकड़े आकाश कैसे धीरे-धीरे इकट्ठा होता हुआ दिखता है, जैसे किसी दर्जी ने आसमान के सारे टुकड़ों को एक साथ करके सी दिया हो!

किसी गुदड़ी की तरह!

बरसाने की लट्ठमार होली को देखकर, आदिकाल से गलत परम्पराओं और रूढ़ियों की मार सहती आ रही स्त्री के उस दिन के भावों को कोई एआई पढ़ पाएगा क्या, जिसमें वह कहती होगी कि लद गए वो दिन जब तुमने मुझे रूढ़ियों के नाम पर पीसा होगा, अब तो मैं अपनी हरियाली को खुद सींच रही हूं?

किसी बाहरी हवा या किसी बारिश का लेशमात्र भी कर्ज नहीं है मुझ पर।

होगी जन्म से मैं हिरन ...पर अब शेर बनना चाहती हूं। बन भी गई हूं।

यह भाव कोई तकनीक या कोई मशीन हमारे भीतर नहीं भर सकती।

जिन्होंने नई सोच को दुत्कारा वो इतिहास में ही समा गए...

इतिहास गवाह है जिन कम्पनियों या लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को समय रहते नहीं अपनाया, नई और अलग करने की सोच को हमेशा दुत्कारते रहे, वे इतिहास में ही समा गए। समय ने उनके ऊपर धूल डालने में किंचित् भी देर नहीं लगाई।

ये सब भाव आम व्यक्ति के मन में उभर रहे हैं...

कि कितनी नौकरियां जाने वाली हैं? कितने लोग बेकार होने वाले हैं? ठीक है! मशीन अपना काम करेगी। करती रहेगी, पर मनुष्य का काम कम नहीं होने वाला है।

निश्चित रूप से, वे जो भाव होते हैं! भावनात्मक संबंध होते हैं! संवेदनशीलता होती है, यह सब मशीन नहीं कर सकती। केवल मनुष्य और उसका दिमाग ही यह कर सकता है।

आखिर एआई को भी बनाने वाला तो मनुष्य ही है!

कुल मिलाकर, वो काम जो मशीन कर सकती है, वही मनुष्य करता रहेगा तो नौकरी जाएगी ही जाएगी। आज नहीं तो कल। हमें मशीन से आगे निकलना होगा। दिमाग जो केवल मनुष्य के पास ही है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना होगा। बहुत कुछ नया सोचना होगा।

यह सब किया तो हम अपना काम कुशलता से कर पाएंगे और मशीन हमारा बाकी काम संभालेंगी। हमें पूरा वक्त मिलेगा- सोचने का, समझने का और इम्प्लीमेंट करने का।

इतिहास गवाह है जिन कम्पनियों या लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को समय रहते नहीं अपनाया, नई और ज्यादा अलग करने की सोच को हमेशा दुत्कारते रहे, वे इतिहास में ही समा गए। बरबाद हो गए।

समय ने उनके ऊपर धूल डालने में किंचित् भी देर नहीं लगाई।

इसीलिए बड़े-बूढ़े कह गए हैं कि जो पेड़ नई कोंपलों का स्वागत नहीं करते, आखिरकार ठूंठ हो जाते हैं!

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

दूरदृष्टि • गलत मिसालें कायम कर रहा अमेरिका

दुनिया के तयशुदा नियमों को सिरे से बदल रहे हैं ट्रम्प

देश-दुनिया

पलकी शर्मा
मैनेजिंग एडिटर FirstPost
X@palkisu

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नाटकीय गिरफ्तारी महज सुर्खियां बटोरने वाला एक गुप्त अभियान नहीं था। यह एक संकेत था- मुखर, बेबाक और गहराई से विचलित कर देने वाला- कि डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह की दुनिया को आकार दे रहे हैं, उसमें शक्ति का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। वेनेजुएला पर हमला तेजतर्रार और निर्मम था। अमेरिका ने एक पदस्थ राष्ट्रपति को उसके आवास से उठा लिया। संदेश सीधा था : हमने यह किया, क्योंकि हम ऐसा कर सकते थे!

और यह केवल अमेरिकी विदेश नीति या लैटिन अमेरिका की क्षेत्रीय राजनीति को ही नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को भी तीन तरीकों से नया आकार दे रहा है।

पहला, यह 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली भू-राजनीति की वापसी का संकेत है। नियम, प्रक्रियाएं और संस्थाएं अब अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक सजावटी वस्तुओं की तरह हैं। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से कोई सबूत पेश नहीं किया। उसने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का रुख नहीं किया। उसने वैधता की तलाश नहीं की। उसने एकतरफा कार्रवाई की- क्योंकि वह कर सकता था।

यह ट्रम्प की क्लासिक शैली है। पहले कार्रवाई, बाद में सफाई। उनकी घरेलू राजनीति में हम इसे बार-बार देख चुके हैं- ऐसे कार्यकारी आदेश जो कानून की सीमाओं को परखते हैं, अदालतों से खुला टकराव और वैध प्रक्रियाओं के प्रति तिरस्कार। अब यही रवैया विदेश नीति में निर्यात किया जा रहा है। और दुनिया देख रही है।

अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र इतनी सहजता से किसी देश की सम्प्रभुता की अनदेखी कर सकता है, तो दूसरों को कौन रोकेगा? चीन को ताइवान के खिलाफ आक्रामकता बढ़ाने से कौन रोकेगा? रूस को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अपहरण करने से रोकने वाला कौन बचेगा? क्षेत्रीय ताकतों को कानून के बजाय बल प्रयोग से अपने विवादों को सुलझाने की मनाही अब क्यों कर होने लगेगी?

यही वह खतरनाक मिसाल है, जो अब दुनिया की तमाम राजधानियों तक पहुंच रही है।

दूसरे, ट्रम्पवाद पुरानी शैली के प्रभाव-क्षेत्रों को फिर से जीवित कर रहा है। यह शीत युद्ध वाली सोच है, जिसे आज के सौदेबाजी वाले दौर के हिसाब से अपडेट किया गया है। ट्रम्प के संकेतों के मुताबिक पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका की जागीर है। इसमें वेनेजुएला, कोलम्बिया, क्यूबा, यहां तक कि ग्रीनलैंड तक को सम्प्रभु देशों नहीं, बल्कि रणनीतिक परिसंपत्तियों के रूप में देखा जा रहा है।

इस गोलार्ध से बाहर किसी को अलग-थलग कर देने की अमेरिका की तत्परता भी उतनी ही चौंकाने वाली है। ट्रम्प ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की स्थिति को कमजोर कर दिया है, उन्होंने यूरोप में अमेरिका की पारम्परिक गठबंधन संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया है और नाटो की तो उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ, एशिया में उन्होंने जी-2 का विचार रखा है- यानी दो देशों का समूह : अमेरिका और चीन। गरज ये कि दो महाशक्तियां ही दुनिया के नियम तय करें और बाकी देश किनारे बैठकर देखते रहें। यह बहुपक्षीयता नहीं है। यह वर्चस्व का प्रबंधन है। और यह अन्य संशोधनवादी ताकतों को पूरी तरह रास आता है।

तीसरे, यह ट्रम्पवाद दुनिया को फिर से संसाधनों की खुली होड़ों की ओर धकेल रहा है। कुछ समय तक ऐसा लगने लगा था कि वैश्विक संघर्ष कच्चे संसाधनों की भूख से ज्यादा विचारधारा, पहचान या सुरक्षा संबंधी दुविधाओं से प्रेरित हैं। न तो यूक्रेन युद्ध तेल के कारण शुरू हुआ था, न गाजा संघर्ष और न ही दक्षिण एशिया में सीमा पर होने वाली झड़पें।

अगर अमेरिका ही इतनी सहजता से किसी देश की सम्प्रभुता की अनदेखी कर सकता है, तो दूसरों को कौन टोकेगा? चीन और रूस को ताइवान और यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता बढ़ाने से कौन रोकने वाला है?

लेकिन ट्रम्प इस समीकरण को भी बदल रहे हैं।

वेनेजुएला के मामले में तेल का खेल ही है। ग्रीनलैंड के मामले में दुर्लभ खनिजों पर ट्रम्प की नजर है। अब तो शांति की कीमत भी संसाधनों से तय की जा रही है। यूक्रेन से कहा गया है कि अमेरिकी मदद पर बातचीत आगे बढ़ने से पहले वह अपने दुर्लभ खनिज संसाधनों तक पहुंच प्रदान करे। जैसे-जैसे वैचारिक गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं, उनकी जगह संसाधन-आधारित साझेदारियां लेती जा रही हैं।

कूटनीति स्वयं बदल रही है। वह अब पहले से तेज, अधिक लेन-देन आधारित, अधिक सार्वजनिक और कहीं कम गोपनीय होती जा रही है। यह भारत की पारम्परिक शांत संवाद और रणनीतिक धैर्य वाली शैली से काफी अलग है। पर इस उथल-पुथल के बीच एक सकारात्मक पहलू भी है। ट्रम्प की शैली से पुरानी, पश्चिम-प्रधान वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो रही है। संस्थाएं बिखर रही हैं। सहमति का आधार टूट रहा है। और इस शून्य से कुछ नया उभर सकता है- एक अधिक वास्तविक बहुध्रुवीय व्यवस्था। यही भारत का घोषित लक्ष्य हमेशा से रहा भी है!

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मुद्दा • 125 दिनों के रोजगार का दावा भी भ्रामक

हम आजीविका के अधिकार को कमजोर नहीं कर सकते

मनरेगा

राजेंद्रन नारायणन
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मामले में यह फैसला दिया था कि अगर राज्य पर नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन और काम का अधिकार सुनिश्चित करने का दायित्व है, तो जीवन के अधिकार से आजीविका के अधिकार को बाहर करना मात्र शब्दजाल होगा।

मनरेगा- जो कई सालों के सामाजिक आंदोलनों के नतीजे से आया था और जिसे संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था- जीवन के अधिकार के लिए काम के अधिकार को एक अनिवार्य शर्त के रूप में परिकल्पित करने वाला था। यह सार्वजनिक रोजगार की पुरानी योजनाओं से भिन्न था, क्योंकि मनरेगा के प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय अधिकारों के समान थे। यह अधिनियम अकाल-राहत उपायों, पानी के स्रोतों के पुनरुद्धार, ग्रामीण संपर्क व्यवस्था आदि के माध्यम से दीर्घकालिक और सतत संपत्तियों के निर्माण कर सकता है और संकट से राहत की भी परिकल्पना करता है।

इसने कई सकारात्मक परिणाम दिए। मनरेगा शुरू होने के कुछ सालों में ही श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई और कुल मिलाकर गरीबी घटी। कृषि के ऑफ-सीजन में दलित और आदिवासी परिवारों की खपत में लगभग 30% तक की बढ़ोतरी हुई। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक, मनरेगा की लगभग 45% महिला श्रमिक या तो पहले काम नहीं करती थीं या केवल पारिवारिक खेत पर ही काम करती थीं। मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 55% रही है। यहां तक कि विश्व बैंक ने भी 2009 में इसे विकास में बाधा कहने से हटकर 2014 में इसे ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कोविड काल के दौरान मनरेगा की भूमिका दर्ज की गई है।

लेकिन मनरेगा को रद्द करने के आभास मिलते रहे थे। लगातार अपर्याप्त बजट आवंटन की वजह से मजदूरी भुगतान में निरंतर देरी हुई, जिसे वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है। बजटीय सीमाओं के चलते अधिकारियों ने काम की राशनिंग दो तरीकों में से किसी एक के माध्यम से करनी शुरू की : (एक) कई परिवारों को कम दिनों का रोजगार देना और/या (दो) कम संख्या में परिवारों को अधिक दिनों का काम देना। मजदूरों, शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं ने बार-बार अधिकारों से वंचित करने वाले कदमों की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये अपारदर्शी और अपरीक्षित तकनीकी पहलों- जैसे फोटो-आधारित उपस्थिति ऐप और जटिल भुगतान प्रणालियों से उत्पन्न हुए थे।

इसी परिप्रेक्ष्य में नए कानून को बिना किसी परामर्श के संसद में जबरन पारित कर दिया गया है। इसकी धारा 5(1) सरकार को यह तय करने के मनमाने अधिकार देती है कि सार्वजनिक कार्य कहां, क्या और कैसे होंगे। इससे पंचायत राज की आजादी खत्म होती है और केंद्र को अपार शक्तियां मिल जाती हैं। धारा 4(5) के तहत केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना आवंटन होगा। जैसा कि सांसद मनोज झा ने कहा, यह नागरिक-केंद्रित, मांग-आधारित कानून को उलट कर इसे आदेश-आधारित बना देता है, जिससे यह केंद्र प्रायोजित, आवंटन-आधारित मॉडल में बदल जाता है और राज्य केंद्र की कृपा पर निर्भर हो जाते हैं। वर्तमान में मनरेगा के 90% खर्च केंद्र सरकार करती है और 10% राज्यों द्वारा किया जाता है। नए कानून की धारा 22 के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, केंद्र-राज्य वित्तीय अनुपात को 60:40 कर दिया गया है।

मनरेगा गांधी के पंचायत राज के विचारों को आम्बेडकर की नागरिकों को अधिकारों के जरिए सशक्त करने की भावना के साथ जोड़ता था। पर नया कानून गांधी और आम्बेडकर- दोनों के विचारों पर प्रहार है।

इन प्रावधानों को एक साथ देखने पर कुछ राज्यों के पक्ष में राजनीतिक पक्षपात और अन्य राज्यों के साथ भेदभाव की आशंका उत्पन्न होती है। गरीब राज्यों को मनरेगा के लिए केंद्रीय राशि की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन केंद्र-राज्य वित्तीय अनुपात में यह बदलाव और राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालने से गरीब राज्य असमान रूप से अधिक प्रभावित होंगे। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की मजबूरी में राज्य काम की मांग को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे बेरोजगारी और पलायन बढ़ने की संभावना है। वर्ष के किसी भी समय काम पाने का मौका विशेष रूप से भूमिहीनों और महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि नए कानून की धारा 6(2) में कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों तक कोई रोजगार न देने का प्रस्ताव भूमिहीनों और महिलाओं के लिए बड़ा झटका साबित होगा। नए कानून में प्रति परिवार प्रति वर्ष 125 दिनों के रोजगार का दावा किया गया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जब प्रति परिवार औसतन सालाना काम के दिन लगभग 50 ही रहे हैं, तब 125 दिनों के रोजगार का दावा भी भ्रामक है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • जब दुनिया उपभोग के नशे में डूब रही है, तब भारत के पास संतुलित जीवन का मार्गदर्शन है

पश्चिमी जीवनशैली अपनाएंगे तो एक पृथ्वी काफी नहीं होगी

क्लाइमेट

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी
आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर
chetanss@gmail.com

मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। भारत आज इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर 1.4 अरब लोगों की जरूरतें हैं- रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा- जिसके लिए विकास हमारी मजबूरी है, विलासिता नहीं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की कड़वी सच्चाई है, जो अब किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं, हमारे घरों, खेतों और शहरों में दिखाई दे रही है। पंजाब की बाढ़, उत्तराखंड में बादल फटना, मध्य भारत की असहनीय गर्मी- ये सब बता रहे हैं कि जलवायु संकट भविष्य नहीं, वर्तमान है।

यह भी स्पष्ट है कि पृथ्वी असीमित नहीं है। न उसकी भूमि, न उसका जल, न उसकी हवा, कुछ भी असीमित नहीं है। सदियों तक हमने इस भ्रम में जीवन बिताया कि प्रकृति का भंडार कभी खत्म नहीं होगा। आज जब नदियां सूख रही हैं, भूजल गिर रहा है, मिट्टी थक चुकी है और हवा जहरीली हो गई है, इस भ्रम की कीमत हम चुका रहे हैं। उपभोग के हर कार्य के पीछे अदृश्य कार्बन रूपी कचरा उत्सर्जित होता है, जो पृथ्वी को और गर्म और भविष्य को असुरक्षित बनाता है। यदि भारत पश्चिम की अनियंत्रित खपत को अपनाता है, तो सिर्फ यह देश ही नहीं, पृथ्वी भी टिक नहीं पाएगी। यदि भारत के 1.4 अरब लोग भी अमेरिका या यूरोप के लोगों जैसी जीवन-शैली अपना लें, तो हमें कम से कम 8 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी, परंतु हमारे पास तो बस एक ही है।

लेकिन भारत के पास एक अनोखी शक्ति भी है- सभ्यता की जड़ें। यह भूमि हमेशा से सादा जीवन, उच्च विचार की रही है। नदियां माता मानी गई हैं, वृक्ष देवता बने हैं, पहाड़ों को घर का रक्षक माना गया है। गांधी ने भी चेताया था कि धरती हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, पर लालच नहीं। यह भारत की विरासत आज वैकल्पिक नहीं बल्कि आवश्यक है। जब दुनिया उपभोग के नशे में डूबती जा रही है, भारत के पास संतुलित जीवन का सांस्कृतिक मार्गदर्शन मौजूद है। आज का फाइनाइट अर्थ मूवमेंट इसी प्राचीन सत्य को आधुनिक भाषा में व्यक्त करता है कि सीमित पृथ्वी पर सीमित उपभोग ही संभव है और यही हमारा भविष्य भी है।

इस सबके बीच विकास का अर्थ भी बदलना होगा। केवल जीडीपी से सफलता मापना वैसा ही है, जैसे किसी के बैंक में पैसा तो बढ़े पर शरीर बीमार हो- यानी कागज पर अमीरी, जीवन में गरीबी। वास्तविक विकास वह है, जहां हवा स्वच्छ हो, पानी शुद्ध हो, मिट्टी जिंदा हो और समाज समरस हो। विकास का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना होना चाहिए। नौकरियां सिर्फ बड़ी फैक्टरियों में ही नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, मरम्मत-उद्योग, जैविक खेती, और स्थानीय उद्यमों में भी दी जा सकती हैं। शहर ऐसे बन सकते हैं, जहां इमारतें रोशनी बचाएं, हवा बचाएं, बिजली बचाएं, न कि ऐसे जहां एसी के बिना जी न सकें। परिवहन ऐसा हो सकता है जो सुविधा बढ़ाए और प्रदूषण घटाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवल डिग्री ही नहीं, जिम्मेदारी का बोध भी दे, और पृथ्वी की सीमितता की समझ भी दे।

इस दौर में भारत के पास एक दुर्लभ अवसर है। पश्चिम पहले ही अपने गलत मॉडल में फंस चुका है, उसे सुधारने में दशकों लगेंगे। कई विकासशील देश उसी रास्ते पर चलने को लालायित हैं। पर भारत अभी मोड़ पर है। हम चाहें तो शुरुआत से ही ऐसा विकास मॉडल बना सकते हैं, जो समृद्धि भी दे और पृथ्वी की सीमाओं के भीतर भी रहे। यदि भारत सीमित धरती पर सीमित उपभोग को अपनाता है, तो पूरी दुनिया का कार्बन उत्सर्जन का रास्ता बदल सकता है। हमारे पास युवाओं की ऊर्जा, तकनीक की शक्ति, सांस्कृतिक दर्शन और 1.4 अरब लोगों का पैमाना है। ये चारों मिलकर भारत को वैश्विक नेतृत्व का एक वास्तविक अवसर देते हैं।

हमारे सपनों का भारत वह है, जहां विकास और पर्यावरण साथी हों। जहां हर बच्चे को स्वच्छ हवा-पानी मिले। जहां किसान की मिट्टी पीढ़ियों तक उपजाऊ रहे। जहां समृद्धि का अर्थ वस्तुओं की संख्या नहीं, समाज और प्रकृति की सेहत हो। जहां शिक्षा नागरिक बनाती हो, उपभोक्ता नहीं। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

लगाव बढ़ा • अगले 5-7 साल लोग लंबी अवधि में निवेश से जोरदार रिटर्न की उम्मीद में सोने की खरीदारी जारी रखेंगेः डेलॉय की स्टडी

सोने की कीमत 1 साल में 77% बढ़ने का असर, निवेशक 50% से बढ़कर 86% हुए

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

एक साल में सोना 77% महंगा हो गया है। इसके चलते करीब एक तिहाई लोग कम वजन के गहनें खरीदने लगे हैं और हर 10 में से करीब 9 लोगों ने सोने को निवेश का साधन बना लिया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स के आंकड़ों के मुताबिक, 6 जनवरी 2025 को देशभर में 24-कैरेट सोने की औसत कीमत 77,161 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। बुधवार को यह 1,36,660 रुपए हो गई। इस बीच 22-कैरेट (जेवराती सोने) की कीमत भी 70,680 रुपए से बढ़कर 1,25,181 रुपए हो गई। इसका गहरा असर हुआ। प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी डेलॉय इंडिया की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, सोना महंगा होने के बावजूद लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन तरीके बदले हैं। महंगा होने के कारण लोग कम वजन के गहने खरीद रहे हैं, लेकिन शुद्धता से समझौता नहीं कर रहे। ऐसे लोग भी हैं, जो पुराना सोना बेचकर नए गहने बनवा रहे हैं।

33% खरीदार गहनों के वजन कम कर रहे, 17% कैरेट घटा रहे

डेलॉय इंडिया के सर्वे में शामिल 33% खरीदारों ने कहा कि वे सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए गहनों का वजन कम कर देते हैं, लेकिन शुद्धता से समझौता नहीं करते। 19% खरीदार सोना महंगा होने पर बजट बढ़ाते हैं, जबकि इतने ही खरीदार पुराने सोने के बदले नए गहने खरीदते हैं। केवल 17% खरीदार 22 के बजाय 18 या 14 कैरेट जैसे कम शुद्धता वाले सोने का रुख करते हैं।

खरीदना जरूरीः सोने के 19% खरीदार अब बजट बढ़ा रहे

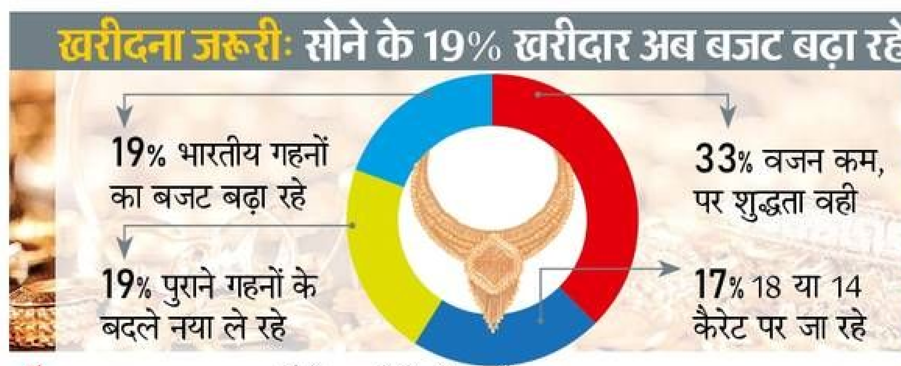

मौजूदा भावः 24-कैरेट सोने के औसत दाम ₹1,36,675/10 ग्राम

सोना	मौजूदा दाम	1 साल में कीमत बढ़ी	रिकॉर्ड स्तर से अब इतना कम
24 कैरेट	₹1,36,675	₹59,514 (77%)	-₹1,281 (0.93%)
22 कैरेट	₹1,25,194	₹54,514 (77%)	-₹1,174 (0.93%)

नई सोचः सोने के गहने अब निवेश के लिए प्रमुख एसेट क्लास

डेलॉय साउथ एशिया के कस्टमर स्ट्रैटजी पार्टनर प्रवीण गोविन्दु ने कहा, 'एक बदलाव जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वो ये है कि सोना और सोने के गहने अब निवेश के लिए प्रमुख एसेट क्लास बन गए हैं। डेलॉय के सर्वे में पिछले साल, करीब 50% लोगों ने कहा था कि उन्होंने एक एसेट क्लास के रूप में सोने में निवेश किया था। इस साल, यह संख्या बढ़कर 86% हो गई है।' यह म्यूचुअल फंड और शेयर जैसे बाजार से जुड़े निवेश साधनों के लगभग बराबर है। असल में सोना भारतीय घरों में दोहरी भूमिका निभाता है। आधे से अधिक उपभोक्ता आभूषणों को निवेश और फैशन एक्सेसरीज, दोनों के रूप में देखते हैं। हल्के और बहुमुखी डिजाइन, विशेष रूप से मिलेनियल्स और जेनरेशन जेड के उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। अगले 5-7 वर्षों में, लोग लंबी अवधि के निवेश के लिए सोने की खरीदारी करना जारी रखेंगे, जबकि आभूषणों की खपत सोने, चांदी और अन्य धातुओं में बंट जाएगी।

बिजनेस ब्रीफ

देश के 97% बैंक खाते बीमा सुरक्षा के दायरे में

मुंबई | मार्च 2025 तक देश के 97.6% बैंक खाते बीमा सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं। रकम के लिहाज से बैंकों में जमा कुल 241.08 लाख करोड़ रुपए में से 100.12 लाख करोड़ पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह कुल जमा का करीब 41.5% हिस्सा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में जमा बीमा फंड भी 15.2% बढ़कर 2.29 लाख करोड़ रु. हो गया है।

एसबीआई फंड्स आईपीओ से सिटी-जेपी मॉर्गन हटे

नई दिल्ली | सिटीग्रुप और जेपी मॉर्गन ने एसबीआई फंड्स के आईपीओ में सलाहकार की भूमिका से हटने का फैसला किया है। इसकी वजह आईपीओ पर मिलने वाली बहुत कम फीस (करीब 0.01%) है। अब आईपीओ में कोटक महिंद्रा कैपि., एक्सिस बैंक, एसबीआई कैपि. मार्केट्स, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज और जेएम फाइनेंशियल बचे हैं।

एनबीएफसी छोड़कर अब फिनटेक बनेगी एलकेपी

मुंबई | लिस्टेड कंपनी एलकेपी फाइनेंस अब एनबीएफसी कारोबार छोड़कर डिजिटल गिफ्टिंग और रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म 'गिफ्टर' के रूप में नई पहचान बनाएगी। कंपनी ने एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर करने के लिए आरबीआई के पास आवेदन किया है। 350 करोड़ रुपए के कैश रिजर्व और शून्य कर्ज वाली यह कंपनी अब पूरी तरह फिनटेक पर ही केंद्रित होगी।

बर्कशायर सीईओ एबेल का वेतन 19% बढ़ा

न्यूयॉर्क | बर्कशायर के नए सीईओ ग्रेग एबेल का सालाना वेतन 25 मिलियन डॉलर (225 करोड़ रु.) तय किया गया है। यह उनके 2024 में तय 21 मिलियन डॉलर (189 करोड़ रु.) के वेतन से 19% अधिक है। कंपनी ने मंगलवार को एक फाइलिंग में यह जानकारी दी। इससे पहले कंपनी के पूर्व सीईओ वॉरेन बफेट केवल 1 लाख डॉलर (90 लाख रु.) सालाना वेतन लेते थे।

रुपया 31 पैसे मजबूत, 89.87 का हुआ 1 डॉलर

मुंबई | रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे मजबूत हुआ और 1 डॉलर की वैल्यू 89.87 रह गई। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की शुरुआत 90.20 के स्तर पर हुई थी। कारोबार के दौरान यह 89.75 से 90.23 के दायरे में रहा। फॉरेक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा डॉलर की बिक्री करने से रुपए को सहारा मिला।

सतर्कता • जोखिम से बचने का माहौल, 3 दिन में 1,144 अंक तक टूटा सेंसेक्स

रिलायंस समेत 5 सबसे प्रभावशाली शेयर इस सप्ताह 5% तक गिर चुके

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

बाजार के सबसे प्रभावशाली शेयरों में इस हफ्ते भारी गिरावट देखी जा रही है। सोमवार से बुधवार के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस समेत सेंसेक्स के सबसे ज्यादा वेटेज वाले 5 शेयरों में 5.5% तक गिरावट आ चुकी है। सेंसेक्स में इनका वेटेज 35.65% है। यानी ये ही शेयर मोटे तौर पर पूरे बाजार का रुझान तय करते हैं। तीन दिनों में सेंसेक्स सबसे ऊंचे स्तर से 1,144 अंक तक टूट चुका है। सोमवार को यह 102 अंक गिरकर 84,961 पर बंद हुआ, जिसमें निचले स्तर से करीब 350 अंकों की रिकवरी हुई। 2 जनवरी यानी बीते हफ्ते शुक्रवार को यह 85,762 पर बंद हुआ था। इस हफ्ते निफ्टी भी 188 अंक गिरकर 26,141 पर आ गया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों और अमेरिका में रोजगार के आंकड़े जारी होने से पहले बाजार का रुख सतर्क है। अभी जोखिम से बचने का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि कंपनियों की कमाई बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितता के चलते विदेशी निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं।

संतुलनः एचडीएफसी बैंक जितना टूटा, आईसीआईसीआई उतना ही चढ़ा

सेंसेक्स के टॉप-5 शेयरों का वेटेज 35.6%, इस हफ्ते ये ही सबसे ज्यादा टूटे

शेयर	गिरावट	वेटेज
रिलायंस इंडस्ट्रीज	▼5.55%	11.99%
एचडीएफसी बैंक	▼5.20%	8.70%
बजाज फाइनेंस	▼2.11%	3.58%
भारती एयरटेल	▼1.08%	7.54%
इंफोसिस	▼0.11%	3.84%

प्रभाव के मामले में टॉप-10 में शामिल इन शेयरों ने बाजार को संभाले रखा

शेयर	गिरावट	वेटेज
टीसीएस	▲1.41%	6.92%
आईसीआईसीआई बैंक	▲5.25%	5.93%
एसबीआई	▲0.78%	5.53%
एचयूएल	▲2.07%	3.35%
एलएंडटी	▲3.40%	3.35%

आंकड़े बुधवार 7 जनवरी 2026 तक की स्थिति के मुताबिक (स्रोतः बीएसई)

...पर रक्षा कंपनियों के शेयरों में नए साल की शुरुआत से अब तक 5% तक उछाल

बाजार के आम रुझान के उलट 2026 की शुरुआत से ही डिफेंस (रक्षा) सेक्टर के शेयरों में 5% तेजी देखी जा रही है। इनमें भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और एमटीएआर टेक्नोलॉजीज शामिल हैं।
- चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वीपी (रिसर्च) सचिन गुप्ता के मुताबिक, डिफेंस कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत है। आगामी बजट में इस सेक्टर को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है।
- सचिन गुप्ता के मुताबिक, आगामी महीनों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और एमटीएआर जैसे डिफेंस शेयरों में 10-12% तेजी आ सकती है।

रिलायंस पर रूसी तेल विवाद भारी पड़ रहा

स्वतंत्र बाजार विश्लेषक अंबरीश बालिगा ने कहा कि रूसी तेल के इस्तेमाल से जुड़ा विवाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भारी पड़ रहा है। रिलायंस कंपनी के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की आशंका से घबराए हुए हैं, हालांकि कंपनी ने इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था। भारती एयरटेल के शेयर इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि निवेशक इसके तिमाही प्रदर्शन से खुश नहीं हैं।

डीजीसीए की सख्ती • पायलटों की कमी के बीच बढ़ाया था मनमाना किराया

एयरलाइंस से औसत किराये के आंकड़े मांगे

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

सरकार ने इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, अकासा से औसत किराये का आंकड़ा देने को कहा है। यह जानकारी प्रतिस्पर्धा आयोग की उस जांच के बीच मांगी गई है, जिसमें दिसंबर में बड़े पैमाने पर इंडिगो की फ्लाइट कैंसल होने की असल वजहों का पता लगाया जा रहा है।

देश के नागरिक विमानन बाजार में इंडिगो की करीब 65% हिस्सेदारी है। कंपनी में पायलटों की कथित कमी के कारण उसे पिछले महीने लगभग 4,500 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं थी। इससे हजारों यात्री फंस गए और पूरे देश में हवाई यात्रा बाधित हुई थी। इस संकट के दौरान कुछ एयरलाइंस ने किराये में भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद सरकार को अस्थायी रूप से किराये की सीमा तय करनी पड़ी।

यह संकट तब शुरू हुआ था जब नागरिक विमानन नियामक डीजीसीए ने पायलटों के लिए सख्त ड्यूटी और आराम के नए नियम पूरी तरह लागू किए।

बीते साल 1 से 15 दिसंबर तक की देनी है जानकारी

डीजीसीए ने 1 जनवरी को इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और अकासा सहित एयरलाइंस को पत्र लिखकर 1 से 15 दिसंबर तक के किराये की जानकारी मांगी। दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिसंबर में ही इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कंपनी ने अपनी प्रमुख बाजार स्थिति का दुरुपयोग किया।

फंसे कर्ज घटाने में भारत दुनिया में सबसे आगे

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

भारतीय बैंकिंग सेक्टर ने पिछले एक दशक में सुधार की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है। जुलाई-सितंबर 2025 की तिमाही में भारतीय बैंकों का फंसा कर्ज (एनपीए) घटकर 2.4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। 2015 में यह कुल कर्ज का 5.9% था। एक दशक के भीतर 3.5 प्रतिशत अंकों की यह गिरावट दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था के मुकाबले सबसे तेज है।

2015 बनाम 2025 : प्रमुख देशों में घटा बैंक एनपीए

भारत का एनपीए स्तर कई विकसित देशों से भी बेहतर

भारत ने 10 साल में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बैंकों के फंसे कर्ज तेजी से साफ किए हैं। मौजूदा एनपीए (2.4%) स्तर अब कई विकसित देशों के पुराने बेंचमार्क से भी बेहतर स्थिति में है। कम एनपीए इस बात का प्रमाण है कि भारतीय बैंक अब बड़े प्रोजेक्ट्स को कर्ज देने में अधिक सक्षम, सुरक्षित और भरोसेमंद हैं।

भास्कर नॉलेज

एलआईसीः लैप्स पॉलिसियां दोबारा इस तरह शुरू करें...

अमित कुमार | नई दिल्ली

एलआईसी प्रीमियम भुगतान में चूक के कारण लैप्स हो चुकी इंडिविजुअल पॉलिसियों को फिर शुरू करने में मदद के लिए महीने का विशेष अभियान चला रही है।

1 जनवरी से 2 मार्च 2026 तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य विलंब शुल्क में महत्वपूर्ण छूट देकर पॉलिसीधारकों को फिर से बीमा के दायरे में लाना है।

- **क्यों महत्वपूर्ण है ये मुहिम?**
एलआईसी द्वारा ये कदम तब उठाया गया है जब कई परिवार अनियमित आय से जूझ रहे हैं। इसके कारण उन्हें जीवन बीमा जैसे लंबे समय के वित्तीय खर्च का प्रबंधन करने में परेशानी हो रही है। इस मुहिम से ऐसे परिवारों का फायदा होगा।
- **एलआईसी का ये अभियान किन पॉलिसियों के लिए है?**
मामले के जानकारों के मुताबिक ये अभियान उन सभी गैर-लिंक्ड व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों पर लागू होता है जो प्रीमियम भुगतान में चूक के कारण लैप्स हो गई हैं।
- **इस अभियान के तहत क्या सहूलियत मिल रही है?**
- पॉलिसीधारकों को विलंब शुल्क पर 30% तक की छूट, अधिकतम 5,000 रुपए तक।
- माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसियों पर विलंब शुल्क में 100% तक छूट।
- प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी और पॉलिसी अवधि पूरी न कर पाने वाली पॉलिसियों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है।
- **कौन से पॉलिसीधारक इस अभियान में पॉलिसी शुरू करने पर विचार कर सकते हैं?**
ये अभियान उन पॉलिसीधारकों के लिए है जो व्यक्तिगत या वित्तीय परिस्थितियों के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए। इनमें नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या धन की अस्थायी कमी हो सकती है। एलआईसी ने स्पष्ट किया है कि मुहिम के तहत विलंब शुल्क में छूट उपलब्ध है, लेकिन चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में कोई छूट नहीं दी गई है।

इंटर्नल को जीएसटी, ब्याज, जुर्माने सहित 3.7 करोड़ चुकाने का आदेश

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

जोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी 'इटर्नल' को जीएसटी विभाग से झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के स्टेट टैक्स एडिशनल कमिश्नर (अपील्स) ने कंपनी को 3.7 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आउटपुट टैक्स के कम भुगतान को लेकर की गई है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया उसे यह ऑर्डर 6 जनवरी 2026 को मिला।

टैलेंट परखने की चाल मानी

जोमैटो के सीईओ गोयल ने माना है कि 2024 में 'चीफ ऑफ स्टाफ' पद के लिए 20 लाख फीस वाली वैकेंसी महज एक 'चाल' (ब्लफ) थी। असल उद्देश्य उन उम्मीदवारों को छांटना था जो पैसों के बजाय सीखने को प्राथमिकता देते हैं।

कुल राशि में 1.92 करोड़ रु. मूल टैक्स, 1.58 करोड़ रु. ब्याज और 19.24 लाख रु. पेनल्टी शामिल है।

भारतीय निर्यातक अमेरिकी ऑर्डर गंवाने की दहलीज पर

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में देरी से भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। घरेलू साज-सज्जा से लेकर चमड़े के जूतों तक के निर्यातकों को चिंता है कि अगर वे जनवरी में ऑर्डर हासिल नहीं कर पाए तो वे अमेरिका समर सीजन की खरीदारी से चूक जाएंगे। स्थानीय निर्यातकों के अनुसार, व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए यह महीना निर्णायक होगा, ताकि 2026 के पहले छह महीनों के लिए अनुबंध सुरक्षित किए जा सकें।

बांग्लादेश यार्न पर लगा सकता है 20% शुल्क

भास्कर न्यूज़ | चेन्नई

भारतीय धागे (यार्न) का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन में 20% तक ड्यूटी लगाने पर चर्चा हो चुकी। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अतुल गणात्रा ने कहा, 'भारत कुल धागा उत्पादन का 30% निर्यात करता है। अगर बांग्लादेश शुल्क लगाता है, तो धागों के दाम घट सकते हैं।' इस बीच एक जनवरी से अब तक कपास के भाव 5% से ज्यादा बढ़ गए हैं।

जेपी फ्रॉड केसः ईडी ने 400 करोड़ की संपत्ति अटैच की

नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेपी इंफ्राटेक धोखाधड़ी मामले में 400 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। इसमें जेपी इंफ्राटेक के पूर्व एमडी मनोज गौड़ से जुड़े ट्रस्ट 'जयप्रकाश सेवा संस्थान' और रियल्टी ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टर्स क्लीनिक के प्रमोटर हनी कटियाल की कंपनी 'पेज 3 बिल्डटेक' की अचल संपत्तियां शामिल हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई। ईडी जांच के अनुसार, नोएडा के जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट्स के खरीदारों से जुटाए पैसे में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। गौड़ वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। दोनों कंपनियों को घर खरीदारों के डायवर्ट किए फंड का हिस्सा मिला था। पूरा मामला दिल्ली, यूपी पुलिस की एफआईआर पर आधारित है।

इस साल 10 गुना बढ़ सकती है देश की बैटरी स्टोरेज क्षमता

नई दिल्ली | भारत की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता इस साल के अंत तक करीब 10 गुना बढ़कर 5 गीगावॉट घंटा तक पहुंच सकती है। 2025 में यह क्षमता केवल 507 मेगावॉट घंटा थी। ये आंकड़े इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की रिपोर्ट में सामने आए हैं। 2025 में देश में 69 टेंडर जारी किए गए, जिससे कुल 224 गीगावॉट घंटा की परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से करीब 60 गीगावॉट घंटा की परियोजनाएं अब निर्माण और संचालन के करीब हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद देश की बैटरी क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 2025 में बीईएसएस टैरिफ में गिरावट देखी गई। लेकिन फंडिंग और तकनीकी चुनौतियां कायम हैं।

सेहत • 2024 में 571 करोड़ की बिक्री थीं एंटी-ओबेसिटी दवाएं

देश में वजन घटाने की दवाओं का मार्केट 2025 में 115% बढ़कर 1,230 करोड़ रुपए तक पहुंचा

संकेत कौल | नई दिल्ली

देश में मोटापा घटाने वाली दवाओं का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इंजेक्टेबल ग्लूकागॉन-लाइक पेप्टाइड-1 (जीएलपी-1) एगोनिस्ट क्षेत्र में लॉन्च किए गए तिरजेपेटाइड और सेमाग्लूटाइड जैसे नए प्रोडक्ट की बढ़ती बिक्री इसकी मुख्य वजह है। 2025 में देश का एंटी-ओबेसिटी (मोटापा-रोधी) दवाओं का मार्केट 2024 की तुलना में 115% बढ़ गया। 2024 में जहां 571 करोड़ रुपए की एंटी-ओबेसिटी दवाएं बिकी थीं वहीं 2025 में 1,230 करोड़ रुपए की बिकीं। एली लिली की मोंजारो बिक्री मार्च 2025 में लॉन्च होने के नौ माह के भीतर 601 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। नोवो नॉर्डिस्क की वेगोवी की छह माह में करीब 61 करोड़ रुपए तक पहुंची। वहीं, भारत में पिछले महीने ही लॉन्च हुए ओजेम्पिक ने करीब 1 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस साल मार्च में सेमाग्लूटाइड का पेटेंट समाप्त हो रहा है। इससे दाम घट सकते हैं, पर इनकी मूल्य वृद्धि धीमी हो सकती है।

क्या होती है जीएलपी-1

जीएलपी-1 एगोनिस्ट दवाओं का एक वर्ग है जो खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने, तृप्ति बढ़ाने और पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। इससे वजन कम होता है और टाइप 2 मधुमेह और मोटापे में ग्लूकोज नियंत्रण में सुधार होता है।

बिजनेस एंकर अमेरिका और यूरोप में कृत्रिम रंगों पर कड़े नियमों से बढ़ रही नीले फूलों की मांग

कुदरती रंग, औषधीय गुणों के लिए मशहूर अपराजिता की खेती अब भारतीय किसानों के लिए नया बिजनेस; थाईलैंड, इंडोनेशिया को टक्कर

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

अपराजिता (बटरफ्लाई पी) नाम का नीला फूल पहले बगीचों और घरों की सजावट तक ही सीमित था। इसके औषधीय गुणों का भी इस्तेमाल होता था। लेकिन अब ये देश के कई हिस्सों में किसानों के लिए आय का साधन बनता जा रहा है। चाय और प्राकृतिक रंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले इन फूलों की खेती और बिक्री से किसान आय बढ़ा रहे हैं। जब ये फूल गर्म पानी में डाले जाते हैं तो पानी नीला हो जाता है और नींबू डालने पर बैंगनी रंग में बदल जाता है। यह जादुई रंगत है। पारंपरिक रूप से थाईलैंड और इंडोनेशिया इस फूल के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता रहे हैं। लेकिन वैश्विक मांग बढ़ने से भारत के उद्यमियों का ध्यान भी इस तरफ गया है। टीएचएस इम्पेक्स की संस्थापक वर्शिका रेड्डी कहती हैं, 'प्राकृतिक रंगों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। उपभोक्ता अब प्राकृतिक सामग्री ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप ने कृत्रिम रंगों पर कड़े नियम लागू किए हैं। इसके चलते उन देशों में कुदरती रंगों की मांग बढ़ गई है।'

अपराजिता के स्वास्थ्य संबंधी फायदों को लेकर अध्ययन जारी

स्वास्थ्य लाभ के मामले में अपराजिता के फूलों पर अध्ययन हो रहा है। चेन्नई के रामचंद्रा इंस्टीट्यूट की एसोसिएट प्रोफेसर वी. सुप्रिया कहती हैं, 'प्री-डायबिटिक लोगों ने जब इस फूल की चाय पी, तो उनके शुगर नियंत्रण में सुधार हुआ।' साल 2021 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपराजिता फूल को फूड एडिटिव के रूप में मंजूरी दी थी। हालांकि, 2022 में यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने इसके इस्तेमाल पर चिंता भी जताई थी।

असम के अंतार्ग्वलाओ गांव की नीलम ब्रह्मा को दो साल पहले पता चला कि गांव की महिलाएं यह फूल बेचकर कमाई कर रही हैं। वह भी उनसे जुड़ गईं। वे बताती हैं, 'कुछ साल पहले तक बटरफ्लाई-पी फूल हमारे गांव में बस एक साधारण बेल वाला पौधा ही था। पहली बार जब मैंने सूखे फूल बेचकर 4,500 रुपए कमाए, तो मुझे खुद हैरानी हुई।' इसके बाद उन्होंने छोटा लोन लेकर से सोलर ड्रायर लिया और धीरे-धीरे यह एक छोटे बिजनेस में तब्दील हो गया। पश्चिम बंगाल के किसान पुष्पल बिस्वास पहले चावल और सब्जियां उगाते थे। कई बार फसल बिक नहीं पाती थी और नुकसान होता था। बटरफ्लाई-पी की खेती से उनका जीवन बदल गया। वे कहते हैं, 'वैज्ञानिक तरीकों से मेरा उत्पादन 50 किलो से बढ़कर 80 किलो हो गया। इससे मैंने और जमीन ली और धीरे-धीरे मेरी आमदनी बढ़ी।' उनके अनुसार, यह अब सिर्फ खेती नहीं रही, बल्कि इससे एक व्यावसायिक परिवार और समुदाय बन गया है।

वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट की संशोधित बोली भी ठुकराई

एजेंसी | लॉस एंजिलिस

वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (डब्ल्यूबीडी) के बोर्ड ने पैरामाउंट स्काईडांस द्वारा स्टूडियो को खरीदने के नवीनतम प्रयास को भी खारिज कर दिया है। बोर्ड ने पैरामाउंट स्काईडांस का संशोधित 108.4 बिलियन डॉलर (करीब 9.7 लाख करोड़ रुपए) का प्रस्ताव जोखिम भरा बताकर ठुकरा दिया है। वार्नर ब्रदर्स के बोर्ड ने कहा कि पैरामाउंट का प्रस्ताव बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग पर निर्भर है। इससे सौदे के पूरा होने का जोखिम बढ़ जाता है। बोर्ड ने फिल्म और टेलीविजन स्टूडियो और अन्य संपत्तियों के लिए स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स के 82.7 बिलियन डॉलर (7.42 लाख करोड़ रुपए) के सौदे पर कायम रहने की पुष्टि की है। मतलब यह कि अब लगभग तय हो गया है कि ये डील नेटफ्लिक्स के साथ होगी।

ईवी • 1.77 लाख कारें, 12.8 लाख दोपहिया बिके

2025 में ई-कारों की बिक्री 77%, दोपहिया की 36% बढ़ी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) बाजार के लिए 2025 बदलाव वाला साल रहा। ऑटो डीलरों के संगठन फाडा के मुताबिक, बीते साल ई-कारों की रिटेल बिक्री 77% बढ़कर 1,76,817 तक पहुंच गई, जो 2024 में 99,875 थी। अब नए प्लेयर्स ने दिग्गज कंपनियों को चुनौती देना शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स अब भी लीडर है, लेकिन उसकी बाजार हिस्सेदारी में बड़ी गिरावट आई है। दूसरी ओर, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर और महिंद्रा ने अपनी बिक्री में रिकॉर्ड इजाफा किया है। दोपहिया सेगमेंट में भी 11.36% की औसत ग्रोथ रही, 12.8 लाख ई-दोपहिया बिके। जहां टीवीएस और बजाज ने अपनी पकड़ मजबूत की है। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक के लिए यह साल संकट भरा रहा और उसकी बिक्री आधी रह गई।

ओला की बिक्री 4 लाख से घटकर आधी रह गई

दोपहिया सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री 4.08 लाख से 51% गिरकर 1.99 लाख रह गई। बाजार हिस्सेदारी 35.47% से घटकर 15.57% पर आ गई। टीवीएस मोटर 2.99 लाख दोपहिया बेचकर पहले और बजाज ऑटो 2.7 लाख के साथ दूसरे स्थान पर रही।